राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

गौरवशाली भारत

दिल्ली से प्रकाशित

R.N.I. NO. DELHIN/2011/38334 वर्ष- 10, अंक- 225 पृष्ठ - 08, नई दिल्ली, शनिवार ,06 फरवरी 2021 , मूल्य रु. 1.50

एक नज़र...

गुजरात में सड़क हादसे में दो की मौत, पांच घायल

तापी, (वेबवार्ता)। गुजरात के तापी जिले में बारातियों को ले जा रही एक निजी लक्जरी बस शुक्रवार सुबह सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गई जिससे दो व्यक्तियों की मौत हो गई और पांच अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दुर्घटना वलोड गांव के पास व्यारा-बाजीपुरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुई। वलोड पुलिस थाने के निरीक्षक वी/ आर/ वसावा ने कहा कि लक्जरी बस में बाराती सवार थे जो महाराष्ट्र के मालेगांव से गुजरात के सूरत जा रहे थे। उन्होंने कहा, आज सुबह हुई दुर्घटना में दो यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि पांच अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। वसावा ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि बस चालक सड़क किनारे खड़े टैंकर-ट्रक को देख नहीं पाया और टक्कर हो गई।

भाजपा विधायक के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज

उदयपुर, (वेबवार्ता)। राजस्थान के उदयपुर शहर में भाजपा के एक विधायक पर एक महिला ने शादी का झांसा देकर बलात्कार करने का आरोप लगाते हुए एक मामला दर्ज कराया है। पुलिस के अनुसार गोगुन्दा से विधायक प्रताप लाल भील (52) के खिलाफ बृहस्पतिवार को बलात्कार के आरोप में सुखेर पुलिस थाने में एक प्राथमिकी दर्ज की गयी। उदयपुर के पुलिस अधीक्षक राजीव पचार ने कहा, 'पीड़िता की चिकित्सकीय जांच के बाद उसका बयान दर्ज किया गया।''मध्य प्रदेश की रहने वाली पीड़िता का आरोप है कि विधायक ने उससे शादी करने का वादा किया और इसकी आड़ में कई बार उससे बलात्कार किया। पुलिस अधिकारी के अनुसार, विधायक व आरोप लगाने वाले महिला एक ही समुदाय से हैं और कुछ वर्षों से संपर्क में थे। आरोपी विधायक से इस बारे में कोई बात नहीं हो पाई है।

हास्य कलाकार मुनव्वर फारूकी को इंदौर में दर्ज मामले में अंतरिम जमानत मिली

नई दिल्ली, (वेबवार्ता)। उच्चतम न्यायालय ने हास्य कलाकार मुनव्वर फारूकी को कथित रूप से धार्मिक भावनाएं आहत करने के लिये मध्य प्रदेश के इंदौर में दर्ज मामले में शुक्रवार को अंतरिम जमानत दे दी। न्यायमूर्ति आर एफ नरीमन की अध्यक्षता वाली पीठ ने नियमित जमानत देने से इनकार करने के उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ दायर मुनव्वर फारूकी की याचिका पर मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस भी जारी किया है। पीठ ने वीडियो कांफ्रेंस के जरिये हुई सुनवाई के दौरान कथित रूप से धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिये फारूकी के खिलाफ उत्तर प्रदेश में दर्ज मामले में जारी पेशी वारंट पर भी रोक लगा दी है। फारूकी और चार अन्य को भाजपा विधायक के बेटे की शिकायत पर एक जनवरी को गिरफ्तार किया गया था। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि फारूकी ने नववर्ष के मौके पर इंदौर में हुए एक हास्य कार्यक्रम के दौरान हिंदू देवी-देवताओं तथा केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां की थीं। इसके बाद एक और व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था। उच्च न्यायालय ने 28 जनवरी के अपने आदेश में फारूकी को जमानत देने से इनकार करते हुए कहा था कि ''सौहार्द को बढ़ावा'' देना एक संवैधानिक कर्तव्य है।

शादी के निमंत्रण पत्र पर किसान आंदोलन के समर्थन में नारे लिखवा रहे लोग

कैथल, (वेबवार्ता)। कृषि कानूनों के विरुद्ध चल रहे आंदोलन को समर्थन देने के लिए हरियाणा के कुछ किसानों ने नया तरीका अपनाया है जिसके तहत शादी के निमंत्रण पत्र पर किसान नहीं तो अन्न नहीं जैसे नारे और किसान नेता सर छोटू राम की तस्वीर छपवायी जा रही है। यहां एक प्रिंटिंग प्रेस के मालिक के अनुसार, विवाह के निमंत्रण पत्र पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भगत सिंह का चित्र भी छपवाया जा रहा है। प्रेस के मालिक ने कहा, बहुत से किसान परिवार और अन्य लोग शादी के निमंत्रण पत्र पर 'किसान नहीं तो अन्न नहीं' जैसे नारे छापने और सर छोटू राम तथा भगत सिंह के चित्र लगाने का अनुरोध कर रहे हैं।

राज्यसभा में तल्ख बहस: कृषि मंत्री बोले- खून से खेती सिर्फ कांग्रेस कर सकती है, भाजपा नहीं

बताए कानून में काला क्या..

नई दिल्ली (एजेंसी)। राज्यसभा में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार गांव, गरीब और किसान के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और आने वाले कल में भी रहेगी। तोमर ने कहा कि हमने उत्पादन लागत से 50त्न अधिक एमएसपी प्रदान करना शुरू कर दिया है। साथ ही, 1 लाख करोड़ रुपये का कृषि बुनियादी ढांचा कोष आत्मनिर्भर पैकेज के तहत दिया गया है। हमने कृषि क्षेत्र में अपेक्षित निवेश सुनिश्चित करने का प्रयास किया है। विपक्ष पर निशाना साधते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि दुनिया जानती है कि पानी से खेती होती है। खून से खेती सिर्फ कांग्रेस ही कर सकती है, भारतीय जनता पार्टी खून से खेती नहीं कर सकती। मंत्री ने कहा कि 15 वें वित्त आयोग ने ग्राम पंचायतों को 2.36 लाख करोड़ रुपये प्रदान करने की सिफारिश की है, जिसे मंत्रिमंडल ने स्वीकार कर लिया है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा के लिए लगभग 43,000 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। 5 लाख में ग्राम पंचायतों के माध्यम से 2.8 लाख करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि हमने मनरेगा के लिए लगातार फंड बढ़ाया है। जब देश में COVID-19 अपने चरम पर था तब हमने मनरेगा को निधि आवंटन 61,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1.115 लाख करोड़ रुपये कर दिया। तोमर ने दावा किया कि 10 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार दिया गया।

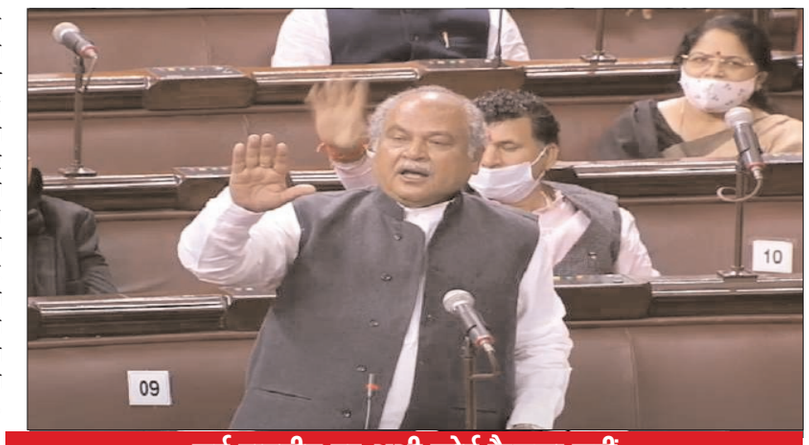

नई बातचीत पर अभी कोई फैसला नहीं

कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर किसानों के आंदोलन से पैदा हुआ गतिरोध जल्द टूटता नजर नहीं आ रहा है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के रुख से भी लग रहा है कि निकट भविष्य में सरकार और किसान नेताओं के बीच बातचीत नहीं होने वाली। जब उनसे दोनों पक्षों के बीच बातचीत के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जब इसके बारे में कोई फैसला किया जाएगा तो हम सूचित करेंगे। जब उनसे प्रदर्शनकारियों की रिहाई के बारे में पूछा गया तो उनका कहना था की किसान नेताओं को इस बाबत पुलिस आयुक्त से बात करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यह कानून व्यवस्था से जुड़ा मामला है और इस पर टिप्पणी करना मेरा काम नहीं है। मालूम हो कि कुछ किसान नेताओं ने कहा है कि जब तक गिरफ्तार किए गए प्रदर्शनकारियों की रिहाई नहीं होती है तब तक बातचीत का कोई सवाल ही नहीं है।

देश में उलटी गंगा बह रही..

कृषि मंत्री ने कहा, केंद्र सरकार का ऐक्ट टैक्स को खत्म करता है जबकि राज्य सरकार का ऐक्ट टैक्स देने पर बाध्य करता है। जो टैक्स ले रहा है, बढ़ा रहा है आंदोलन उसके खिलाफ होना चाहिए या जो टैक्स फ्री कर रहा है, उसके खिलाफ होना चाहिए? अब देश में उलटी गंगा बह रही है। उन्होंने कहा, भारत सरकार पूरी तरह से किसानों के प्रति समर्पित है। किसान आंदोलन के लिए हम लोगों ने लगातार उनको सम्मान देने की कोशिश की है। 12 बार ससम्मान बुलाकर बातचीत की है। एक शब्द भी हमने उनके बारे में इधर-उधर नहीं बोला। संवेदनशीलता के साथ विचार किया है। लेकिन हमने ये जरूर कहा है कि आप प्रावधान में कहां गलती है, हमारा ध्यान आकर्षित करिए।

बंधन समारोह में बोले राजनाथ सिंह, डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़कर 9,000 करोड़ रुपए का हुआ

बेंगलुरू। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने बेंगलुरू में येलहंका विमानक्षेत्र पर बंधन समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि 2015-2020 में डिफेंस एक्सपोर्ट 2,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 9,000 करोड़ रुपये हो गया। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक मुझे आपको को ये बताते हुए खुशी हो रही है कि 2015-2020 में डिफेंस एक्सपोर्ट 2,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 9,000 करोड़ रुपए हो गया। ये भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट का एक बड़ा हिस्सा निजी क्षेत्र से है।
उन्होंने कहा कि अगर हमें 2025 तक 25 बिलियन डॉलर के डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन और 5 बिलियन डॉलर के एक्सपोर्ट के लक्ष्य को हासिल करना है, तो इसमें एयरोस्पेस क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। रक्षा मंत्री ने कहा कि दिसंबर 2020 में सरकार द्वारा दिए गए 48,000 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के 83 एलसीए एमके 1ए का आदेश घरेलू विनिर्माण और विशेष रूप से विमानन उद्योग को एक बड़ा बढ़ावा देगा। यह नई और लचीला आपूर्ति श्रृंखलाओं को फैलाएगा।
उन्होंने बताया कि भारत में रक्षा से संबंधित वस्तुओं के विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से हमारा प्रयास 2022 तक रक्षा आयात को कम से कम 2 बिलियन डॉलर तक कम करने का लक्ष्य है। इसके अलावा 2016 और 2019 में घरेलू विनिर्माण के लिए 37 बिलियन डॉलर से अधिक के 138 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है।

किसानों का चक्का-जाम

पुलिस ने किए सुरक्षा के कड़े इंतजाम

नई दिल्ली (एजेंसी)। 6 फरवरी का चक्का जाम किसानों के लिए ताकत का प्रदर्शन और सरकार के गले की फांस बन गया है। हालांकि किसान नेता राकेश टिकैत ने दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड को चक्का जाम से मुक्त रखकर सरकार को राहत दी है लेकिन किसानों और सरकार के बीच मसले के हल के लिए गतिरोध बना हुआ है और इसके फिलहाल दूर होने के भी आसार नहीं दिख रहे हैं। लेकिन आज आंदोलनकारी किसानों के खेमे से आई एक नई खबर इस समय सबकी जुबान पर है कि दिल्ली में चक्का जाम सरकार ने कर दिया है, शेष देश में किसान करेंगे इसमें दक्षिण भारत के राज्य भी शामिल होंगे। हालांकि फिलहाल किसान आंदोलन का असर यूपी, हरियाणा पंजाब और राजस्थान में दिखाई दे रहा है। इसके अलावा किसान नेताओं के हवाले से कहा ये भी जा रहा है कि अब आंदोलन को गति देने के लिए साप्ताहिक चक्का जाम का कार्यक्रम भी किसान कर सकते हैं। किसानों ने इस चक्का जाम का आह्वान इंटरनेट बैन, दिल्ली में किसानों के विभिन्न प्रदर्शनस्थलों की कील कांटों से बाड़बंदी के विरोध में किया है। 26 जनवरी के ट्रैक्टर रैली प्रदर्शन के बाद ये किसानों का दूसरा सबसे बड़ा प्रदर्शन है। इस चक्का जाम का आह्वान 40 किसान यूनियनों वाले संयुक्त किसान मोर्चा ने किया है।

- 6 फरवरी को तीन घंटे तक चलेगा किसान यूनियनों का चक्का जाम
- दोपहर 12 से तीन बजे तक बंद रखे जाएंगे नैशनल और स्टेट हाइवे
- राकेश टिकैत का ऐलान- दिल्ली में नहीं होगा चक्का जाम
- की अपील- जो यहां नहीं आ पाए, वो अपने यहां चक्का जाम करें

देश की राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। सिंघु बॉर्डर पर 72वां और गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन को आज 70वां दिन है। किसान नेता जगतार सिंह बाजवा ने कहा कि शनिवार को सभी राज्य और जिलों के हाइवे पर चक्का जाम किया जाएगा। दिल्ली में तो पहले से ही किसान बैठे हैं इसलिए यहां चक्का जाम वाली स्थिति नहीं होगी। देश की अन्य जगहों पर 12 बजे से 3 बजे तक चक्का जाम की स्थिति रहेगी।

शांतिपूर्ण होगा चक्का जाम: गौरव टिकैत

कृषि सुधार कानूनों के विरोध में आंदोलनरत किसानों के 'संयुक्त किसान मोर्चा' की ओर से देशभर में शनिवार को चक्का जाम का आह्वान किया गया है। किसान नेताओं के अनुसार दोपहर 12 से 3 बजे तक देशव्यापी चक्का जाम किया जाएगा। गौरव टिकैत ने शुक्रवार को बताया कि शनिवार को किसान तीन घंटे के लिए अपने खेतों से निकलकर सड़क पर बैठेगा और चक्का जाम करेगा। इसके साथ ही अधिकारियों को ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। यह चक्का जाम पूरी तरह से शांतिपूर्ण ढंग से किया जाएगा। चक्का जाम के दौरान आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहनों को नहीं रोका जाएगा। चक्का जाम के दौरान किसानों का किसी को भी परेशान करने की कोई मंशा नहीं है। उन्होंने बताया कि चक्का जाम के दौरान जिन वाहनों को रोका जाएगा उसमें मौजूद लोगों के लिए खाने-पीने की व्यवस्था भी की जाएगी।

जब किसान आंदोलन कर रहे, तब राष्ट्रपति कृषि कानूनों की प्रशंसा कर रहे, यह दुर्भाग्यपूर्ण: आनंद शर्मा

नई दिल्ली । राज्यसभा में कांग्रेस के उपनेता आनंद शर्मा ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना की है और कहा कि जब तीन नए कृषि कानूनों के विरोध में देश में बड़े पैमाने पर किसान आंदोलन कर रहे हों, और ठीक उसी वक्त देश के राष्ट्रपति उन्हीं कानूनों की संसद में तारीफ कर रहे हों तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है. शर्मा ने शुक्रवार को कहा कि किसानों को अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए मजबूर किया गया और जो स्थिति पैदा हुई है उसके लिए केंद्र जिम्मेदार है.

कांग्रेस सांसद ने कहा कि किसान आंदोलन के दौरान गणतंत्र दिवस के दिन लाल किले की घटना से पूरा देश आहत है. उन्होंने कहा कि इस घटना की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए. शर्मा ने कहा कि देश में विषम परिस्थितियां हैं. केंद्र सरकार ने किसानों को घर से बाहर निकलकर प्रदर्शन करने को मजबूर किया है.उन्होंने किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान

गणतंत्र दिवस की हिंसा के दौरान घायल हुए पुलिस कर्मियों और अधिकारियों के प्रति सहानुभूति व्यक्त की. उन्होंने कहा, राष्ट्रपति का अभिभाषण सरकार का निराशाजनक प्रशंसा पत्र है. इस अभिभाषण में तीन कृषि कानून का अनावश्यक उल्लेख किया गया है जो दुर्भाग्यपूर्ण है. उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति वही पढ़ते हैं जो सरकार लिख कर देती है. शर्मा ने कहा, एक तरफ किसान आंदोलन चल रहा है, दूसरी तरफ संसद में उसी कानून की तारीफ हो रही है. इससे यादा दुख की बात नहीं हो सकती.

उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में विदेश नीति की चर्चा तक नहीं है. शर्मा ने पूछा कि क्या हम अलग-थलग पड़ गए हैं? यहां तक कि पड़ोस तक की चर्चा नहीं है. शर्मा ने कहा, लॉकडाउन में रेलगाड़ी नहीं चली, बस नहीं चली. लाखों लोगों को पैदल चलना पड़ा. रेलवे स्टेशन पर एक बच्चा अपनी मरी हुई मां का कंबल हटा रहा, इसका कहीं जिक्र भी नहीं है. मैं इसकी निंदा करता हूं. अभिभाषण में कहना चाहिए था कि हमें इस बात की तकलीफ है.

कांग्रेस सांसद ने कहा, यह जरूरी नहीं है कि जो सरकार बोले उसे जनता मान ही ले या विपक्ष उसके साथ खड़ा हो तो फिर लोकतंत्र नहीं है. सरकार का दायित्व है जनता की आवाज को सुनना लेकिन विरोध प्रदर्शन को आप अपराध करार दे रहे हैं लेकिन जब किसान पर अत्याचार होगा या होता है तो उसके साथ देश खड़ा होगा सरकार को यह भूलना नहीं चाहिए.

रालोद की महापंचायत में उमड़े किसान, जयंत चौधरी बोले-

दिल्ली की हिंसा भाजपा की साजिश

शामली, (वेबवार्ता)। उत्तर प्रदेश के शामली में कृषि कानूनों के विरोध में गांव भैंसवाल में स्वामी कल्याण देव कन्या गुरुकुल में आज रालोद के आह्वान पर किसान महापंचायत हुई। जिसमें रालोद उपाध्यक्ष जयंत चौधरी ने कहा कि गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में हुई हिंसा भाजपा की साजिश थी। उपद्रवियों को दिल्ली पुलिस मूक दर्शक बनकर देखती रही। उन्होंने कहा कि जो आज किसानों के साथ नहीं, उन्हें आगामी चुनाव में वोट नहीं देना है। महापंचायत में भाकियू के अध्यक्ष नरेश टिकैत के छोटे भाई नरेंद्र ने भी शिरकत की। वहीं, राकेश टिकैत ने शामली में होने वाले आंदोलन से खुद को किनारा किया है। कहा है कि इस

पंचायत से भाकियू का कोई लेना-देना नहीं है। जयंत चौधरी ने कृषि कानूनों पर बोलते हुए कहा कि सरकार कृषि कानूनों पर अडिग है। सरकार को इतना अहंकार नहीं करना चाहिए। उन?होंने कहा कि जब? सभी लोग इस कानून का विरोध कर रहे हैं तो सरकार को इसको वापस ले लेना चाहिए। उन?होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि अगर विधानसभा में किसानों के प्रतिनिधि कम हो गए है। अब फिर से विधानसभा में प्रतिनिधियों को भेजना होगा। इसके लिए किसान नेताओं को जीताने की अपील की। भैंसवाल गांव में बुलाई गई रालोद की महापंचायत में किसानों का सैलाब उमड़ा हुआ नजर आया। प्रशासन ने सुरक्षा का हवाला देते हुए पंचायत कराने की अनुमति नहीं दी थी, लेकिन इसके बाद भी पंचायत बुलाई गई। पंचायत में सुबह से ही किसान जुटते चले गए। तकरीबन दो बजे रालोद नेता के पहुंचने के बाद पंचायत का आगाज हुआ। वक्ताओं ने कृषि कानूनों का विरोध करते हुए कहा कि सरकार को इन कानूनों को वापस लेना ही होगा।

मौद्रिक नीति : आम जनता के लिए कोई राहत की बात नहीं

रिजर्व बैंक ने बनाये रखी यथास्थिति

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की बैठक आज समाप्त हो गई है। आम बजट 2021-22 पेश होने के बाद यह पहली समीक्षा बैठक है। पिछली तीन मौद्रिक समीक्षा बैठकों में समिति ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। रिजर्व बैंक ने आखिरी बार 22 मई 2020 में नीतिगत दरों संशोधन किया था। यानी जो लोन की किस्तें पहले थीं वो वैसी की वैसी हैं।
आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया है कि आरबीआई ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। यह चार फीसदी पर बरकरार है। एमपीसी ने सर्वसम्मति से यह फैसला लिया है। यानी ग्राहकों को ईएमआई या लोन की ब्याज दरों पर नई राहत नहीं मिली है। दास ने कहा कि रिवर्स रेपो रेट को भी 3.35 फीसदी पर स्थिर रखा गया है। इसके साथ ही बैंक रेट में भी कोई बदलाव नहीं करने का फैसला लिया गया है। यह 4.25 फीसदी पर है। रिज़र्व बैंक की समिति ने आम बजट के प्रस्तावों का समर्थन किया है और कहा है कि सरकार ने बाजार से पैसा उठाने की जो कार्यक्रम बनाया है, रिजर्व बैंक उसका अनुपालन सुनिश्चित करेगा। गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि इस बार के बजट ने स्वास्थ्य और इन्फ्रा सेक्टरों पर जोर दिया है जो एक सकारात्मक कदम है।

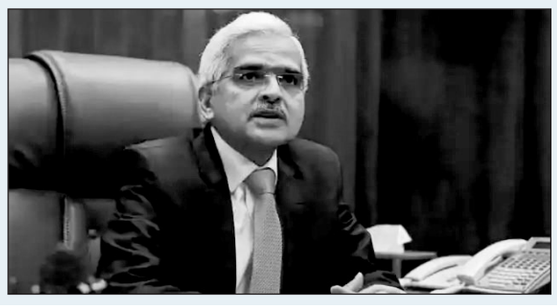

"शक्तिकांत दास ने कहा कि सरकार रिजर्व बैंक के लिए नियत इन्फ्लेशन लक्ष्य की समीक्षा मार्च में करेगी। इससे पता चलेगा कि महंगाई किस लेवल पर है। उन्होंने बताया कि निकट भविष्य में सब्जियों के दाम नरम बने रहेंगे।

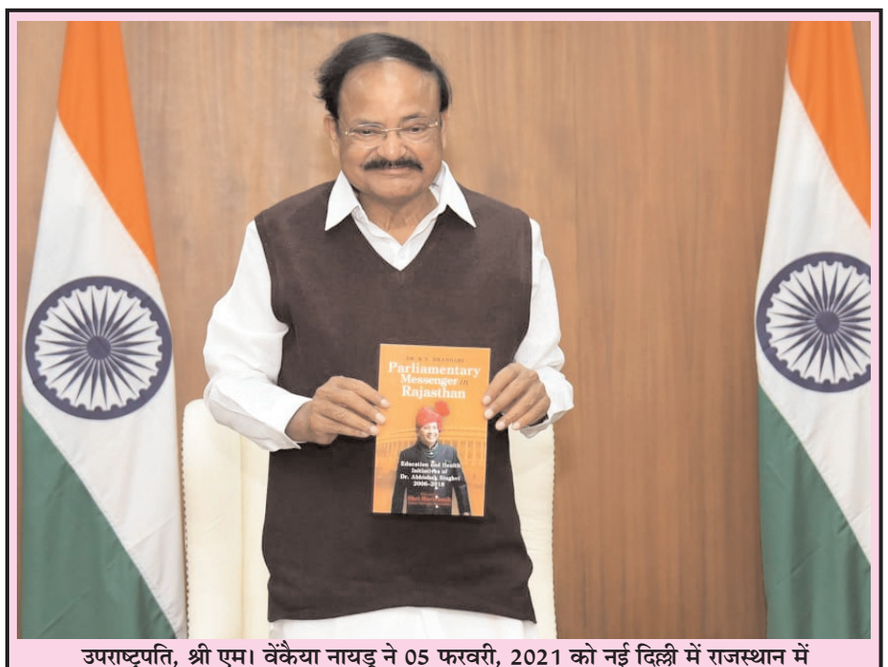

उपराष्ट्रपति, श्री एम। वेंकैया नायडू ने 05 फरवरी, 2021 को नई दिल्ली में राजस्थान में संसदीय दूत नामक पुस्तक का विमोचन करते हुए।

रूस की कोर्ट का फैसला-पुतिन विरोधी विपक्षी नेता नवेलनी को ढाई साल की जेल, 1100 समर्थक भी गिरफ्तार

मास्को। रूस के विपक्षी नेता एलेक्सी नवेलनी को वहां की अदालत ने ढाई साल कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने कहा कि उन्होंने 2014 में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दोषी होने के बाद भी साढ़े तीन साल की अपनी निलंबित सजा की शर्तों का उल्लंघन

किया। अदालत के इस फैसले के बाद एलेक्सी समर्थक सड़कों पर उतर आए। इस दौरान पुलिस से 1100 से ज्यादा लोगों को हिरासत में ले लिया।

नवेलनी को चुनाव लड़ने से रोका गया

44 वर्षीय एलेक्सी नवेलनी भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन चलाने वाले व्यक्ति हैं। उन्होंने 2018 में राष्ट्रपति चुनाव में उतरने की कोशिश की थी। लेकिन उन्हें एक आरोप में दोषी ठहरा दिया गया और चुनाव लड़ने से रोक दिया गया। पिछले साल 20 अगस्त को नोविचोक जहर दिए जाने के बाद से वह जर्मनी में अपना इलाज करा रहे थे।

जर्मनी से लौटते ही हिरासत में लिए गए

नवेलनी जर्मनी से लौटकर 17 जनवरी को जैसे ही मॉस्को एयरपोर्ट पर उतरे, पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया था। इससे पहले उन्होंने कुछ वीडियो जारी किए थे। इनमें पुतिन पर आरोप लगाया था कि उनके पास शाही महल है, जिसमें विलासिता की चीजों के साथ जुआघर भी है। साथ ही पुतिन महिलाओं पर सरकारी खजाना लुटा रहे हैं।

रूस में लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे

रूस में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के धुर विरोधी नवेलनी की गिरफ्तारी के विरोध में पूरे देश में प्रदर्शन चल रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि पुतिन के खिलाफ रूस में यह अब तक का सबसे बड़ा आंदोलन है। हालांकि, इसे लेकर पुतिन ने भी सख्त रवैया अपनाया है।

पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर 50 रॉकेट दागे

काबुल। पाकिस्तान ने एक बार फिर अफगानिस्तान पर हमला किया है। देर रात अफगानिस्तान के कुनार प्रांत के शेल्टन जिले में लगातार 50 रॉकेट दागे गए। जिससे पूरे देश में हड़कंप और अपफरा-तफरी मच गई। पाकिस्तान की इस नापाक हरकत से कई स्थानीय लोगों के घरों को भारी नुकसान पहुंचा। बता दें, पाकिस्तान द्वारा किये गए इन हमलों से अफगानिस्तान में मातम

मचा हुआ है। रॉकेटों से कई लोगों के घरों को भारी नुकसान हुआ है, साथ ही कई लोगों के घर पूरी तरह से तबाह हो गए है।ऐसे में अफगानिस्तान में इस रॉकेट हमले में 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 50 से ज्यादा लोग बुरी तरह से घायल हो गए हैं। हमले में घायल हुए लोगों को अफगान सैन्य कर्मियों ने अस्पताल में भर्ती कराया।अफगानिस्तान में लगभग हर हमले आए करते हैं। इससे पहले अफगानिस्तान के काबुल में बीते साल नबंबर के माह में कई इलाकों में 23 मोर्टार शेल दागे गए थे। इसमें 8 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 31 लोग घायल हो गए थे। ये मोर्टार दो कारों से दागे गए थे। अभी तक किसी भी आतंकी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली।इस हमले के बारे में मंत्रालय के मुताबिक, ये मोर्टार काबुल के वजीर अकबर खान और शेर-ए-नॉ एरिया, गुल-ए-सुर्ख, स्पाइंजर रोड, नेशनल आर्काइव रोड, लैजी मरियम मार्केट और पंज्साद एरिया में गिरे।

बता दें, रॉकेट हमले से पहले चेहल सुतून और अजान कीमत एरिया में दो विस्फोट भी हुए थे। घायलों को शेर-ए-नॉ एरिया में मौजूद अस्पताल में भर्ती करवाया गया। तालिबान ने कहा कि हमला उसकी तरफ से नहीं हुआ। वजीर अकबर खान इलाके में डिप्लोमैटिक मिशन हैं। इन हमलों की वजह से लोंगों में हाहाकार मचा रहता है।नई दिल्ली। पाकिस्तान ने एक बार फिर अफगानिस्तान पर हमला किया है। सोमवार को देर रात अफगानिस्तान के कुनार प्रांत के शेल्टन जिले में लगातार 50 रॉकेट दागे गए। जिससे पूरे देश में हड़कंप और अपफरा-तफरी मच गई। पाकिस्तान की इस नापाक हरकत से कई स्थानीय लोगों के घरों को भारी नुकसान पहुंचा। इस बारे में प्रांतीय गवर्नर मोहम्मद इकबाल सईद के हवाले से अफगानिस्तान की टोलो इसकी जानकारी दी।

चीन पर सख्त बाइडेन: एक हफ्ते में दूसरा यूएस वॉरशिप साउथ चाइना सी में तैनात

अमेरिका ने कहा- ताइवान की मदद करेंगे

वॉशिंगटन। दक्षिण चीन सागर पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे चीन को अमेरिका ने माकूल जवाब देने की तैयारी कर ली है। अमेरिकी नेवी का सबसे खतरनाक और एडवांस्ड वॉरशिप निमित्ज मिडल-ईस्ट से निकालकर साउथ चाइना सी की तरफ रवाना कर दिया गया है। पेंटागन ने इसकी पुष्टि की है। निमित्ज से पहले इस इलाके में थियोडोर रूजवेल्ट वॉरशिप तैनात है। दक्षिण चीन सागर में ताइवान समेत बाकी देशों को चीन धमकाने की कोशिश कर रहा है। हाल के दिनों में कई बार उसके फाइटर जेट्स ताइवान के करीब उड़ान भर चुके हैं। अमेरिका ने साफ कर दिया है कि ताइवान की हिफाजत जरूर की जाएगी।

इस फैसले के मायने

ईरान से तनाव के चलते ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने निमित्ज को अरब सागर में तैनात किया था। बाइडेन ने सत्ता

संभालते ही इसे दक्षिण चीन सागर भेज दिया। बाइडेन का यह फैसला साफ तौर पर चीन के लिए सख्ती और ईरान की तरफ नरमी का संकेत है। उनका प्रशासन ईरान के साथ उस एटमी डील को फिर लागू करने की तैयारी में है जिसे ट्रम्प ने रद्द कर दिया था। यानी यहां तनाव कम होगा। वहीं, चीन के खिलाफ एक साथ दो एडवांस्ड वॉरशिप तैनात करके बाइडेन ने साफ कर दिया है कि उसकी दबाव की हर चाल का जवाब दिया जाएगा।

यह सिर्फ नेवी वॉरशिप नहीं है

'साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट' ने गुरुवार को जारी रिपोर्ट में लिखा- यह चीन को साफ संकेत हैं। अमेरिका ने अरब सागर से निमित्ज को हटाकर इस इलाके में तैनात किया है। यह सिर्फ वॉरशिप नहीं बल्कि मोबाइल एयरफोर्स बेस है। इसके जरिए अमेरिका दुनिया में अपने सैन्य और आर्थिक हित साधता है।

पिछले हफ्ते जब रूजवेल्ट को इस इलाके में तैनात किया गया था तो चीन बिफर गया था। चीन ने कहा था कि इससे साउथ चाइना सी में तनाव बढ़ेगा और टकराव की आशंका बहुत ज्यादा हो जाएगी। अमेरिका के साथ जापान और ऑस्ट्रेलिया भी यहां मौजूद हैं।

निमित्ज इसलिए बेहतर

naval technology.com की एक रिपोर्ट के मुताबिक, स्स निमित्ज एयरक्राफ्ट कैरियर है। इसका फ्लाइट डेक ही 333द्व × 77द्व है। 2017 में ऑपरेशनल होने वाले इस वॉरशिप पर एक वक्त में 6 हजार नौसैनिक तैनात रहते हैं। फिलहाल, इस पर अमेरिका के सबसे खतरनाक और बेहतरीन 60 एयरक्राफ्ट मौजूद हैं। इस पर मौजूद मिसाइलें दुनिया के किसी भी हिस्से में सटीक निशाना साध सकती हैं। कहा जाता है कि निमित्ज पर इंटर बैलेस्टिक मिसाइलें भी मौजूद हैं। इसके अलावा स्पाय और अटैकिंग ड्रोन भी हैं।

किसान आंदोलन: अमेरिका ने भारत के नए कृषि कानूनों का समर्थन किया

कहा- यह बाजार की सेहत भी सुधारेंगे

वाशिंगटन। अमेरिका ने भारत में मोदी सरकार के नए कृषि कानूनों का समर्थन किया है। जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा- भारत सरकार के इन कदमों की तारीफ की जानी चाहिए। इससे भारतीय बाजार की हालत बेहतर होगी और प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा इन्वेस्टमेंट आएगा।

अमेरिका की तरफ से यह बयान ऐसे वक्त आया है जबकि क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग और सिंगर रिहाना ने किसान आंदोलन का समर्थन किया है। अमेरिका के पड़ोसी देश कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भी किसान आंदोलन का समर्थन कर चुके हैं। भारत में आज किसान आंदोलन का 71वां दिन है।

शांतिपूर्ण आंदोलन के पक्ष में अमेरिका

अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने पहली बार भारत में जारी किसान आंदोलन पर टिप्पणी की। बुधवार को डेली ब्रीफिंग के दौरान प्रवक्ता ने कहा- अमेरिका किसी भी शांतिपूर्ण आंदोलन का समर्थन करता है, यह लोकतंत्र की पहचान है। अगर कोई मतभेद है

तो उसे मामले से जुड़े पक्षों को बातचीत के जरिए सुलझाना चाहिए। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा है।

किसान आंदोलन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में: किसान आंदोलन बुधवार को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में आ गया। दुनिया की कुछ बड़ी हस्तियां भारतीय किसानों के सपोर्ट में आ गईं। भारतीय हस्तियों ने भी पलटवार किया और बहकावे में न आने की अपील की। विदेश मंत्रालय ने भी अपील की कि अपनी बात रखने से पहले मुद्दे को समझ लें। उधर, सरकार ने ट्विटर को नोटिस जारी कर किसानों की हत्या की साजिश का दावा करते ट्वीट्स तुरंत हटाने को कहा। क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग, सिंगर रिहाना, पॉर्न स्टार मिया खलीफा और अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस की भतीजी मीना हैरिस ने किसान आंदोलन का समर्थन किया। विदेशी सेलिब्रिटीज को जवाब भारत से मिला। सचिन तेंडुलकर ने इसे भारत का अंदरूनी मामला बताया। कंगना ने किसानों को आंतकी बता दिया। कुछ और बॉलीवुड स्टार्स ने मामले को शांति से सुलझाने की बात कही।

विदेश मंत्रालय ने कहा- पहला मामला तो समझ लें

सोशल मीडिया पर मामला बढ़ता देख विदेश मंत्रालय को बयान जारी करना पड़ा। इसमें कहा गया, 'हम गुजारिश करेंगे कि ऐसे मामलों पर टिप्पणी करने से पहले तथ्यों का पता लगाया जाए और मुद्दों को अच्छी तरह समझ लिया जाए। सोशल मीडिया पर सनसनीखेज हैशटैग और टिप्पणियां लुभावनी बन जाती हैं, खासकर तब, जब मशहूर हस्तियों और अन्य लोग इससे जुड़ जाते हैं, जबकि उनका बयान न तो सटीक होता है और न ही जिम्मेदाराना।'

आतंकियों से डरा पाकिस्तान: कोरोना टीकों की लूट का खतरा, इमरान की बढ़ी मुसीबत

नई दिल्ली। कोरोना महामारी से बचाव के लिए पाकिस्तान को रो-गाकर पांच लाख टीके तो मिल गए हैं मगर अब इन टीकों की सुरक्षा को लेकर पाकिस्तान सरकार काफी परेशान है। जबर्दस्त आर्थिक संकट में फंसी इमरान सरकार कोरोना टीके खरीदने की स्थिति में नहीं थी। इसलिए पाक सरकार ने चीन के सामने गिड़गिड़ाकर ये टीके हासिल किए हैं।

टीके की पहली खेप पहुंचने के बाद पाकिस्तान में टीकाकरण की शुरुआत भी की जा चुकी है। ऐसे में पाकिस्तान सरकार को इस बात का डर सता रहा है कि कहीं ये टीके आतंकी न लूट ले जाएं।टीकों को बचाने के लिए सरकार की ओर से इन्हें गुप्त ठिकानों पर रखने का आदेश दिया गया है। इसके साथ ही यह भी निर्देश दिया गया है कि सेना की तैनाती की जाए और सीसीटीवी से इसकी निगरानी भी की जाए।आतंकी हमलों से सुरक्षा की गाइडलाइन जारी 22 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले पाकिस्तान को चीन ने पांच लाख टीके मुहैया कराने का आश्वासन दिया है। टीकों की पहली खेप पहुंचने के बाद नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की ओर से टीकों की चोरी रोकने और आतंकी हमलों से सुरक्षा के लिए गाइडलाइन जारी की गई है।

चीन में निर्मित सिनोफॉर्म टीके को सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों को लगाया जा रहा है। देश के विभिन्न प्रांतों में करीब 70,000 टीके भेजे गए हैं। सरकार की ओर से इन टीकों की सुरक्षा को लेकर विशेष रूप से सतर्कता बरती जा रही है। सरकार को इस बात का डर सता रहा है कि कहीं आतंकी इन टीकों को लूट न ले जाएं।

किसी भी अप्रिय घटना और आतंकी हमले को रोकने के लिए प्रशासन की ओर से विशेष योजना बनाई गई है। साथ ही इन टीकों को नकली टीकों से बदले जाने की घटनाओं से भी सतर्क किया गया है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशंस सेंटर (एनसीओसी) की ओर से जारी गाइडलाइन में टीकों को लेकर जाने वाले वाहनों के साथ पुलिस, रेंजर्स और सेना की अनिवार्य रूप से तैनाती का आदेश दिया गया है।

सऊदी अरब ने पाकिस्तान समेत 20 देशों से विमान सेवा को किया निलंबित

रियाद। सऊदी अरब ने अपने यहां पर कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों की वजह से पाकिस्तान समेत 20 देशों से हवाई यातायात को फिलहाल स्थगित कर दिया है। अब केवल वही लोग सऊदी अरब में प्रवेश कर सकेंगे जो वहां के नागरिक हैं, डिप्लोमेट हैं और डॉक्टर या उनके परिजन हैं। ये आदेश 3 फरवरी से लागू कर दिया गया है। जिन देशों से आने वाले लोगों पर सऊदी अरब ने बैन लगाया है उनमें संयुक्त अरब अमीरात, जर्मनी, अमेरिका, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका, फ्रांस, मिस्त्र, लेबनान, अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, आयरलैंड, इटली, ब्राजील, पुर्तगाल, तुर्की, स्वीडन, स्विटजरलैंड, जापान और भारत और भारत का भी नाम शामिल है। सऊदी अरब की स्टेट न्यूज एजेंसी के मुताबिक सऊदी अरब ने 21 दिसंबर 2020 को विदेश से आने और जाने वाली विमान सेवाओं को रोक दिया था। 28 दिसंबर को इसको फिर बढ़ा दिया गया था। ये सब कुछ कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के कई देशों में पाए जाने के बाद किया गया था। इसके बाद 4 जनवरी को अपनी सीमा खोली थी।

गौरतलब है कि सऊदी अरब ने जिन देशों के यात्रियों पर अपने यहां आने अस्थायी तौर पर रोक लगाई उनमें अधिकतर वही देश शामिल हैं जहां पर कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के मामले सामने आए हैं। आपको बता दें कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री इस स्ट्रेन को पहले सामने आए प्रकारों से अधिक घातक बता चुके हैं। यही वजह है कि पूरी दुनिया इस नए खतरे को देखते हुए सभी एहतियाती उपाय कर रही हैं। आपको यहां पर ये भी बता दें कि सऊदी अरब द्वारा जिन देशों के यात्रियों पर बैन लगाया गया है उनमें से कुछ को भारत कोविड-19 वैक्सीन की सप्लाई कर रहा है। इतना ही नहीं सऊदी अरब का भी नाम उन देशों में शामिल है जहां पर भारत अपनी वैक्सीन को उपलब्ध करवा रहा है।

म्यांमार में तानाशाही को ड्रैगन का सपोर्ट : सैन्य शासन के समर्थन में चीन का वीटो; संसद में 25फीसदी सीटें आरक्षित होने से लोकतांत्रिक सत्ता पर सेना ही हावी

वाशिंगटन। म्यांमार में आम चुनाव के नतीजों को ठुकराने के बाद हुए तख्तापलट और आंग सान सू की समेत सभी नेताओं को जेल में डाले तीन दिन बीत चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र, भारत और अमेरिका समेत अन्य देशों ने लोकतंत्र के बहाल करने को कहा है। जबकि, चीन ने म्यांमार के संविधान का हवाला देकर इससे पल्ला झाड़ लिया है।

दरअसल, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में मंगलवार को निंदा प्रस्ताव आया। परिषद के 5 स्थाई सदस्यों में शामिल चीन ने इसके खिलाफ अपनी वीटो ताकत का इस्तेमाल कर अड़ंगा लगा दिया। तख्तापलट करने वाले जनरलों का समर्थन कर उसने एक बार फिर जता दिया कि वह लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखता।

2011 में लोकतंत्र बहाल हुआ

म्यांमार के इतिहास पर नजर डालें, तो 1962 से 2011 तक सैन्य शासन रहा। जब आंग सान सू की मुक्त हुई और 2011 में लोकतंत्र बहाल हुआ, तब भी देश की सत्ता पर सेना का ही नियंत्रण रहा।

दरअसल, 2008 के संविधान के तहत सुरक्षा से जुड़े सभी मंत्रालयों पर सेना का नियंत्रण है। संविधान के तहत संसद की 25त्न सीटें सेना के लिए आरक्षित हैं। उसे म्यांमार सरकार द्वारा संविधान में किसी बदलाव पर वीटो लगाने का अधिकार है।

प्रमुख मंत्रालयों भी सेना के पास ही थे: प्रमुख मंत्रालयों भी सेना को ही मिलने के चलते सत्ता से सेना की पकड़ एक दशक बाद

भी ढीली नहीं पड़ी। मौजूदा सरकार में भी 11 मंत्री सेना से जुड़े हुए लोग हैं, जो विदेश, गृह, वित्त, स्वास्थ्य जैसे मंत्रालय संभाल रहे हैं। तख्तापलट करने वाले जनरल मिन आंग ह्लाइन ने तख्तापलट को जरूरी बताया है। उधर, संयुक्त राष्ट्र ने चिंता जताई है कि देश में अभी भी 6 लाख रोहिंग्या हैं। कहीं सेना उनका दमन शुरू न कर दे।

तख्तापलट की वजह भी साफ

म्यांमार में डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ तख्तापलट के खिलाफ हड़ताल पर हैं। जनता भी थाली पीटकर, गाडियों के हॉर्न बजाकर विरोध जता रही है। सू की पार्टी ने विवादित दस्तावेज में बदलाव का वादा किया था।

इसी क्रम में एक समिति बनाने के प्रस्ताव पर संसद में मतदान कराया गया था, जो पारित हो गया था। इससे सेना को लगा कि उसका नियंत्रण अब खत्म हो सकता है। इसलिए तख्तापलट किया।

गैर जिम्मेदाराना रवैया: पाकिस्तान की मंत्री ने कहा- अपनी रिस्क पर वैक्सीन लगवाएं, इससे कई देशों में मौतें हो चुकी हैं

इस्लामाबाद। पाकिस्तान को चीन से 5 लाख मुफ्त वैक्सीन मिली हैं। इसके बाद देश में फ्रंट लाइन वर्कर्स को वैक्सीनेट किया जा रहा है, लेकिन यहां के मंत्री महामारी और वैक्सीनेशन पर बेतुके और गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं।

पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर यास्मिन राशिद ने मंगलवार को कहा- अगर कोई वैक्सीन लगवाना चाहता है तो बिल्कुल लगवाए, लेकिन इसकी रिस्क उसे खुद लेनी होगी। राशिद के मुताबिक, वैक्सीन के कई साइड इफेक्ट्स हैं और दुनिया में कुछ लोगों की इसकी वजह से मौत भी हुई है।

इमरान की सहयोगी हैं यास्मिन

यास्मिन राशिद प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी सीनियर लीडर हैं और उनकी सलाहकार भी रह चुकी हैं।

फिलहाल, वे देश के सबसे बड़े राज्य पंजाब की हेल्थ मिनिस्टर हैं। इतना ही नहीं खुद डॉक्टर भी हैं। मंगलवार को उन्होंने कहा- अगर लोग वैक्सीनेशन करवा रहे हैं तो अपनी रिस्क पर करवा रहे हैं। इसके कुछ साइड इफेक्ट्स हैं। दुनिया में इसकी वजह से कई लोगों की मौत हो चुकी है। हम लोगों को इस बारे में आगाह कर रहे हैं। किसी को भी जबरदस्ती वैक्सीनेट नहीं किया जा सकता। वैज्ञानिक खुद नहीं जानते कि वैक्सीन का असर कितने दिन रहेगा।

राशिद के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने उनकी निंदा की। एक यूजर ने कहा- यास्मिन का फर्ज है कि वो लोगों को वैक्सीनेशन के लिए कहें, उनसे अपील करें। वे तो उल्टा काम कर रही हैं।

चीनी वैक्सीन लेने को तैयार नहीं

कोरोनावायरस के खात्मे के लिए कई देशों ने बड़ी कंपनियों की वैक्सीन की बुकिंग करवाई है, लेकिन चीन की वैक्सीन भरोसे के ट्रायल में फेल साबित हो रही है। दुनिया को कोरोना बांटने वाले चीन ने वैक्सीन का भंडार तैयार कर लिया है। उसके पास वैक्सीन के छह फॉर्मूले तैयार हैं, लेकिन कोई देश उसकी वैक्सीन पर भरोसा नहीं कर रहा।

चीन की वैक्सीन का सऊदी अरब, तुर्की, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान जैसे देशों में ट्रायल जरूर चल रहा है, लेकिन जनता में सर्वे और अधिकारियों के बयान बताते हैं कि चीन इन देशों के करोड़ों लोगों को यह आश्वस्त करने में असफल रहा है कि उसकी वैक्सीन सुरक्षित है। चीन ने पिछले दिनों पाकिस्तान को सायनोफॉर्म वैक्सीन के पांच लाख डोज मुफ्त दिए हैं। खास बात यह है कि इन वैक्सीन को लाने के लिए पाकिस्तान को ही एयरक्राफ्ट भेजना पड़ा था।

दुनिया में पहली बार एक इंसान के चेहरे और दोनों हाथों का हुआ सफल ट्रांसप्लांट, डॉक्टरों का करिश्मा

न्यूयॉर्क। अमेरिका में डॉक्टरों की एक टीम ने दुनिया में पहली बार एक इंसान के चेहरे और दोनों हाथों का सफल ट्रांसप्लांट किया है। अमेरिका के न्यू जर्सी में डॉक्टरों ने एक लड़के के चेहरे और दोनों हाथों का सफल ट्रांसप्लांट किया है। यह दुनिया का अपनी तरह का पहला ट्रांसप्लांट है। एक कार दुर्घटना में इस इंसान के शरीर का 80 प्रतिशत हिस्सा जल गया था। चेहरे और दोनों हाथों के दुर्लभ और सफल प्रत्यारोपण के लगभग छह महीने बाद जो डिमियो ने पलक झपकाई और चुटकी भी बजाई।

दरअसल 22 साल का जो डिमियो साल 2018 में अपनी नौकरी की नाइट शिफ्ट करके आ रहा था और उसे कार में नींद आ गई। इससे कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई, फिर उसमें विस्फोट हो गया। उसकी किस्मत अच्छी थी कि लोगों ने उसकी जान बचा ली और उसे आग की लपटों से खींच लिया। लेकिन उसका चेहरा बुरी तरह खराब हो गया था और वह हादसे में दोनों हाथ गंवा चुका था। जो डिमियो की ट्रांसप्लांट के बाद हालत अब बेहतर है और वह तेजी से ठीक हो रहे हैं। बीते साल अगस्त महीने में न्यूयॉर्क शहर के एनवाईयू लैंगोन हेल्थ सेंटर में उनका ट्रांसप्लांट किया गया था। दुर्घटना के बाद वह दो महीने तक कोमा में थे। 9 अगस्त 2020 को उसके मैच का एक डोनर मिल गया था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण ऑपरेशन नहीं हो पाया था।

एक नजर

छावला पुलिस ने शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया

नई दिल्ली, एजेंसी। छावला थाना की पुलिस टीम ने एक बदमाश को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से बटनदार चाकू, चोरी की मोटरसाइकिल और तीन मोबाइल फोन बरामद किए गए. इसकी पहचान रवि के रूप में हुई है और यह गोयला डेयरी के स्वामी विवेकानंद नगर का रहने वाला है.

डीसीपी संतोष कुमार मीणा के अनुसार, छावला थाना एसएचओ ज्ञानेंद्र राणा की देख-रेख में कॉन्स्टेबल रामस्वरूप और महेंद्र की टीम ने पेट्रोलिंग के दौरान सीक्रेट इंफॉर्मेशन मिलने पर नजफगढ़ के कुतुब विहार इलाके में ट्रैप लगाकर इस बदमाश को गिरफ्तार किया और जब उसकी तलाशी ली गई तो इसके पास से बटनदार चाकू और मोबाइल फोन बरामद हुआ जो छावला थाना इलाके से ही चुराया गया था. पूछताछ में पता लगा कि जिस मोटरसाइकिल पर वह जा रहा था वह मोटरसाइकिल सूरज विहार थाने इलाके से चुराई गई है. इसके बाद इसकी निशानदेही पर चोरी की और दो मोबाइल फोन बरामद किए गए. जानकारी के अनुसार, इस पर छावला थाना में 1 पुराना मामला दर्ज है और इसकी गिरफ्तारी से छावला और सूरज विहार थाना के 5 मामलों का खुलासा हुआ है.

मोबाइल स्नैचिंग के आरोप में पकड़ा गया नाबालिग

नई दिल्ली, एजेंसी। डाबड़ी थाना की पुलिस टीम ने स्नैचिंग के आरोप में एक नाबालिग को पकड़ा है जिसके पास से मोबाइल फोन बरामद किया गया. डीसीपी संतोष कुमार मीणा के अनुसार, डाबड़ी थाना एसएचओ हेमंत कुमार की देख-रेख में कॉन्स्टेबल सुभाष पेट्रोलिंग ड्यूटी पर तैनात थे. चाणक्य प्लेस इलाके में पहुंचने पर कॉन्स्टेबल ने एक व्यक्ति को मदद के लिए चिल्लाते हुए सुना, जब कॉन्स्टेबल उसके पास पहुंचे तो उसने बताया कि एक लड़का उसका मोबाइल फोन छीन कर फरार हो गया है.

इसके बाद कॉन्स्टेबल ने कुछ दूरी तक पीछा करते हुए लड़के को धर दबोचा और उसके पास से पीड़ित व्यक्ति से छीना गया फोन बरामद कर लिया। उससे पूछताछ में पुलिस को पता लगा कि वह नाबालिग है जिसके बाद डाबड़ी थाना में मामला दर्ज करते हुए उसे हिरासत में ले लिया गया है और अब आगे की कार्रवाई की जा रही है.

उधार के रुपये मांगने पर धारदार हथियार से हमला

नई दिल्ली, एजेंसी। उत्तर पूर्वी दिल्ली के न्यू उस्मानपुर में गुरुवार को एक हजार रुपये के लिए चाचा-भतीजा आपस में भिड़ गए। दोनों परिवार के बीच मारपीट हुई। एक परिवार ने दूसरे पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिसमें दो लोग घायल हो गए। घायल 52 वर्षीय खलील मुस्तफा व सुहैल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस केस दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। पीड़ित खलील मुस्तफा परिवार के साथ न्यू उस्मानपुर के जगजीत नगर में रहते हैं। उनका सिलाई का कारोबार है। खलील मुस्तफा के अनुसार, करीब एक महीना पहले उन्होंने अपने चाचा अब्दुल हक को एक हजार रुपये उधार दिए थे। गुरुवार शाम को उसने चाचा से रुपये मांगे, जिसको लेकर दोनों के बीच कहासुनी हो गई। इसके बाद खलील अपने घर आ गया। थोड़ी देर बाद अब्दुल हक अपने बेटे भूरे व आमिर के साथ उनके घर पहुंचा और मारपीट करने लगे। खलील का भतीजा सुहैल बचाव करने लगा, लेकिन तीनों ने उस पर भी हमला कर दिया। इससे खलील व सुहैल दोनों जख्मी हो गए। दोनों को नजदीक के जग प्रवेश चंद अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार चल रहा है। पुलिस केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश कर रही है।

कोरोना नियमों के उल्लंघन पर बार मैनेजर गिरफ्तार

नई दिल्ली, एजेंसी। कुतुब औद्योगिक क्षेत्र स्थित होटल कुतुब में मौजूद बार और रेस्तरां में कोरोना नियमों के उल्लंघन पर किशनगढ़ पुलिस ने केस दर्ज कर मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया है। यहां पर देर रात पार्टी के दौरान लोगों को शराब परोसी जा रही थी। पार्टी में अधिकतर ने मास्क नहीं पहना हुआ था, जबकि सामाजिक दूरी के नियमों का भी ख्याल नहीं रखा जा रहा था। ज्ञात हो कि एक माह में दिल्ली के विभिन्न इलाके में कोरोना नियमों को तोड़ने पर करीब 30 से अधिक बार पर कार्रवाई की गई है।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि बुधवार रात करीब 1. 45 बजे किशनगढ़ थाने के एसआई मीठा लाल मीणा और कांस्टेबल रघुविंद्र गश्त पर निकले हुए थे। पुलिसकर्मियों ने देखा कि कुतुब होटल में मौजूद वी बार व रेस्तरां में लोगों की भीड़ लगी हुई थी। बार में शराब परोसी जा रही थी, जहां कई लोग बगैर मास्क के ही थे। पुलिस ने आईपीसी एक्ट और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की धाराओं में केस दर्ज कर बार में मौजूद मैनेजर शोविक मुखर्जी को गिरफ्तार कर लिया।

थप्पड़ मारने पर कर दी थी ट्रांसपोर्टर की हत्या

नई दिल्ली, एजेंसी। उत्तम नगर इलाके में रविवार को ट्रांसपोर्टर मनोज कुमार झा की हत्या के मामले में पुलिस ने गुरुवार शाम एक नाबालिग और उसके दोस्त को पकड़ा है। दोनों का शनिवार को मनोज से झगड़ा हुआ था। मनोज ने सबके सामने दोनों थप्पड़ मार दिया था, जिसका बदला लेने के लिए उन्होंने हत्या की वारदात को अंजाम दिया।

पुलिस उपायुक्त एस.के मीणा ने बताया कि रविवार रात 8 बजे उत्तम नगर थाना पुलिस को हत्या की सूचना मिली। मृतक की पहचान ट्रांसपोर्टर मनोज कुमार झा के रूप में हुई। मनोज को आधा दर्जन से ज्यादा चाकू मारे गए थे। पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर जांच शुरू की। उत्तम नगर थाना एसएचओ राम किशोर और स्पेशल स्टाफ इंस्पेक्टर नवीन कुमार की टीम ने जांच में पाया कि 30 जनवरी की रात मनोज का दो किशोरों से झगड़ा हुआ था। पुलिस टीम ने सर्विलांस और मुखबिरों की मदद से दोनों को दबोच लिया। पकड़े गए आरोपी अभिषेक शर्मा ने पूछताछ में बताया कि उत्तम नगर में मनोज के घर के पास एक खाली प्लाट है।

आत्मनिर्भर बजट में हर वर्ग को लाभ देने का प्रयास: गुप्ता

नई दिल्ली, एजेंसी। प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की कार्यकारिणी की बैठक में आज केंद्रीय बजट को देश को आत्मनिर्भर बनाने वाला और अन्तिम पंक्तियों में खड़े व्यक्ति से लेकर अग्रणी उद्योगपतियों तक के हित का बताया। दिल्ली भाजपा द्वारा इस ऐतिहासिक बजट के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बधाई दी गई। बैठक में भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रोफ विजय कुमार मल्होत्राए भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री और सांसद दुष्यंत गौतम, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सांसद मनोज तिवारी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और विधायक विजेन्द्र गुप्ता, नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी, प्रदेश संगठन महामंत्री सिद्धार्थन, प्रदेश महामंत्री हर्ष मल्होत्रा और दिनेश प्रताप सिंह सहित प्रदेश पदाधिकारी और कार्यकारिणी के सदस्य उपस्थित रहे। बैठक का संचालन प्रदेश महामंत्री कुलजीत सिंह चहल ने किया। प्रदेश कार्यकारिणी की वर्चुअल बैठक में प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि यह बजट कोविड काल की कठिन परिस्थितियों के बावजूद देश को दूरगामी परिणाम देने वाला और सभी वर्गों का हित साधने वाला है।

6 स्तंभों पर खड़ा यह बजट भारत को आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने वाला एक दृष्टि पत्र है। भारत के विकास में यह बजट बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। हमेशा से गरीब कल्याण के लिए काम करने वाले नरेन्द्र मोदी द्वारा कोरोना काल में पूरे 9 महीनों तक 90 करोड़ देशवासियों को मुफ्त राशन देने का काम किया गया है। विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान के लिए अलग से 35, 000 करोड़ रुपये का बजट वैक्सीन के लिए दिया गया है। इस बजट में स्वास्थ्य से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर, परिवहन और छोटे-मध्यम कारोबारियों के लिए कई सारी सुविधाओं को भी निश्चित किया गया है। आदेश गुप्ता ने कहा कि इस आत्मनिर्भर बजट में 75 साल से अधिक आयु वाले पेंशनधारियों को आयकर में छूट देना उनके प्रति सम्मान को दशार्ता है। उज्जवला योजना के तहत 8 करोड़ महिलाओं को एलपीजी सिलेंडर दिया गया और अब एक करोड़ और सिलेंडर दिए जाएंगे। एक देश एक राशन जैसी योजना भी इस बजट का हिस्सा हैं। पिछले बजट से 137 प्रतिशत ज्यादा का बजट बनाया गया है। खासकर किसानों के लिए इस बजट में 16ण्5 लाख करोड़ रुपये देकर एक तोहफा दिया है। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री और सांसद दुष्यंत गौतम ने कहा कि कठिन परिस्थितियों में जिस तरह का बजट पेश किया गया हैए उसमें आम जनता के लिए बहुत कुछ है। यही वजह है कि अभी तक कोई भी विरोधी दल बजट प्रस्तावों पर सवाल नहीं कर रहा है। किसी देश की सरकार का आकलन करना हो तो उस देश के गरीब आदमी और महिलाओं का उत्थान देखना चाहिए।

स्कूलों में राशन नहीं बंटने पर कार्रवाई करें मुख्यमंत्री : बिधूड़ी

नई दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा है कि गरीबों के लिए भेजा गया हजारों क्विंटल गेहूं व चावल दिल्ली के स्कूलों में सड़ रहा है। इसमें घुन लग गया है और यह अनाज चूहे खा रहे हैं। इसी प्रकार हजारों की संख्या में राशन के किट भी बर्बाद हो रहे हैं। इनमें रखे गए रिफाइंड तेल, मसाले, छोले, चीनी, हल्दी आदि के उपयोग की समय सीमा तक समाप्त हो गई। उन्होंने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से इस मामले में जिम्मेदारी तय कर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है।

मुख्यमंत्री केजरीवाल को लिखे एक पत्र में बिधूड़ी ने कहा है कि उनके अपने बदरपुर विधानसभा क्षेत्र के बदरपुर, मीठापुर, मोलड़बंद व ताजपुर पहाड़ी स्थित सरकारी स्कूलों में करीब 1200 क्विंटल गेहूं, 300 क्विंटल चावल और करीब 3000 राशन किट पड़ा हुआ है। इसी प्रकार बगल के तुगलकाबाद विधानसभा क्षेत्रों के भी सरकारी स्कूलों में भी करीब 1600 क्विंटल गेंहू व चावल व 1500 राशन किट पड़ा हुआ है। इसके अलावा दिल्ली के प्रत्येक क्षेत्र में इसी प्रकार हजारों क्विंटल अनाज व राशन किट में रखा गया समान सड़ रहा।

नेता प्रतिपक्ष बिधूड़ी ने कहा कि सरकार ने करोड़ों रुपये का यह राशन दिल्ली के गरीबों के लिए भेजा, लेकिन अफसोस की बात यह है कि यह अनाज गरीबों को देने के बदले सड़ रहा है। दूसरी ओर आज भी दिल्ली में लाखों गरीब लोग ऐसे हैं जिनके राशन कार्ड आज तक नहीं बने हैं और इसी वजह से उनको सरकारी राशन तक नहीं मिल पा रहा है।

लोगों की निगरानी का मामला

केंद्र ने कहा- सब कुछ कानून के मुताबिक हो रहा है

नई दिल्ली, एजेंसी। सेंट्रल मानिटरिंग सिस्टम (सीएमएस), नेशनल इंटेलीजेंस ग्रिड(नैटग्रिड) और नेटवर्क ट्रैफिक एनालिसिस (नेत्रा) के जरिये डाटा जुटाने पर रोक की मांग करनेवाली याचिका पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में कहा कि सबकुछ कानून के मुताबिक हो रहा है और सरकार कानून का उल्लंघन नहीं कर सकती है. याचिकाकर्ता के वकील प्रशांत भूषण ने केंद्र की इस दलील का विरोध किया. इस मामले पर अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी.

सुनवाई के दौरान प्रशांत भूषण ने कहा कि सरकार ने अपने जवाब में यह नहीं बताया कि इस तरह के सर्विलांस की जरूरत क्या है. उन्होंने कहा कि सिर्फ यह कह देना काफी नहीं है कि सब कुछ कानून के मुताबिक और उसके दायरे में हो रहा है. सरकार को अपना रुख रिकॉर्ड पर लाने दिया जाए. प्रशांत भूषण ने कहा कि हर महीने इन प्रणालियों के जरिए सर्विलांस की करीब नौ हजार मंजूरियां दी जा रही है. उनमें सिर्फ फोन टैपिंग ही नहीं है. व्हॉट्स एप पर चैट, यात्रा आदि सबकुछ शामिल है.

याचिका सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (सीपीआईएल) और सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर ने दायर की है. याचिकाकर्ता की ओर से वकील प्रशांत भूषण ने कोर्ट से कहा कि तीनों डाटा कलेक्शन सिस्टम लोगों की निजता का उल्लंघन कर रही है. याचिका में मांग की गई है कि सीएमएस, नेत्रा और नैटग्रिड चौबीसो घंटे लोगों के बारे में डाटा जुटाती रहती है. इस पर रोक लगाया जाना चाहिए.

याचिका में कहा गया है कि कानून के मुताबिक मानिटरिंग करने के लिए न्यायिक या संसदीय निकाय गठित करने की जरुरत है. ये निकाय टेलीग्राफ एक्ट औड्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत मानिटरिंग या वारंट के आदेशों की समीक्षा करेगा. याचिका में कहा गया है कि इन तीनों सिस्टम के जरिये संविधान की धारा 21 के अलावा खंड तीन में दी गई स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लंघन है. इन सिस्टम के जरिये केंद्र और राज्य सरकारों की एजेंसियों को बड़े पैमाने पर फोन या इंटरनेट कम्युनिकेशन पर नजर रखने की छूट मिल जाती है. ऐसा करना लोगों के अधिकारों और निजता का उल्लंघन है. याचिका में कहा गया है कि इन सिस्टम के जरिये लोगों पर नजर रखना सुप्रीम कोर्ट के निजता के अधिकार के फैसले का उल्लंघन है.

झूठ बोलते हैं सरकार के नुमाइंदें, नहीं मिला एक भी पैसा : महापौर

नई दिल्ली, एजेंसी। आर्थिक तंगी से जूझ रहे उत्तरी दिल्ली नगर निगम को आखिरकार सरकार कब तक 1683 करोड़ की बकाया राशि जारी करेगी। सरकार की उपेक्षा के चलते साफ सफाई के लेकर आम जनता के काम प्रभावित हो रहे हैं। उत्तरी दिल्ली के महापौर जय प्रकाश ने संवाददाता सम्मेलन कर सरकार पर यह आरोप लगाए। इस अवसर पर स्थायी समिति के अध्यक्ष छैल बिहारी गोस्वामी, नेता सदन योगेश वर्मा और उपाध्यक्ष स्थायी समिति विजेंद्र यादव मौजूद रहे। महापौर जय प्रकाश ने कहा कि सरकार ने अब तक 938 करोड़ की घोषणा के बावजूद भी राशि जारी नहीं की है। अभी तक निगम को एक भी रुपया नहीं मिला है। आप पार्टी अब आरोप आदमी पार्टी बन गई है जो रोज नए-नए आरोप लगा कर भ्रम फैला रहे है। उन्होंने बताया कि अब आप पार्टी के प्रवक्ता रोज प्रेस वार्ता कर निगम को फंड जारी करने का भ्रम नागरिकों के मध्य फैला रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि दिल्ली सरकार के पास अपनी कोई उपलब्धि नहीं है वो बस नगर निगमों

से लड़कर व निगमों को आधा-अधूरा फंड दे कर सुर्खियों में बना रहना चाहते हैं। जय प्रकाश ने कहा कि सरकार की उपेक्षा के बावजूद भी निगम विपरीत परिस्थितियों में भी दिल्ली की जनता को सेवाएं देने का कार्य बदस्तूर कर रहा है। दिल्ली सरकार ने अपने बजट प्रावधानों में दिल्ली नगर निगम को 2090 करोड़ रुपए देने का प्रावधान किया था और 14 जनवरी को दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने संवाददाता सम्मेलन कर घोषणा की थी कि दिल्ली सरकार ने काफी परियोजनाएं रोककर दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों के लिए 938 करोड़ रुपए निगम को जारी किए है। जिसमें से उत्तरी दिल्ली नगर निगम को एक पैसा नहीं मिला है। उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार ने आज तक नहीं बताया कि किसी निगम को कितना पैसा दिया है। और कौन-कौन सी परियोजना उन्होंने निगमों को फंड देने के लिए रोकी है। महापौर ने कहा कि दिल्ली सरकार ने उत्तरी दिल्ली नगर निगम को अभी बस तीसरी तिमाही का ही पैसा जारी किया है। जो हमारा संवैधानिक अधिकार है। निगम का अभी 745 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार पर बकाया है यानी 745 करोड़ रुपए और 938 करोड़ रुपए वेतनके लिए कुल 1683 करोड़ रुपए अभी उत्तरी दिल्ली नगर निगम का दिल्ली सरकार पर बकाया है।

पैसा डबल करने का झांसा देकर करोड़ों की ठगी, दूसरा आरोपी भी गिरफ्तार

नई दिल्ली, एजेंसी। राजधानी में चंद महीनों में 200 फीसदी मुनाफे का झांसा देकर लोगों से करोड़ों रुपये की ठगी करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी संजीव उपाध्याय कई महीनों से फरार चल रहा था, जिसे आर्थिक अपराध शाखा ने गिरफ्तार कर तीन दिन के रिमांड पर लेकर पुलिस टीम पूछताछ कर रही है. इस मामले में एक अन्य आरोपी को पहले गिरफ्तार किया जा चुका है. संयुक्त आयुक्त ओपी मिश्रा ने बताया कि संजीव उपाध्याय और अरुण अग्निहोत्री ग्रेट इंडिया एक्सपो नाम से कंपनी चलाते हैं. उन्होंने लोगों से कंपनी में रुपये लगाने के लिए कहा और कुछ ही समय में रकम को डबल करने का झांसा दिया. उनके झांसे में आकर बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई जमा करा दी. काफी रकम एकत्रित होने के बाद उन्होंने लोगों को रुपये लौटाना बंद कर दिया. अपना दफ्तर और मोबाइल बंद कर वह फरार हो गए. पुलिस के अनुसार, 130 से अधिक शिकायतकताओं ने आर्थिक अपराध शाखा को शिकायत की थी. जिस पर अगस्त 2020 में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था.

छानबीन के दौरान आरोपियों के बैंक खाते खंगाले गए. इससे पता चला कि सेल्फ चेक के माध्यम से संजीव उपाध्याय ने करोड़ों रुपये निकाले हैं. आरबीआई की तरफ से इस बात की पुष्टि की गई कि इस कंपनी को नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी की तर्ज पर काम करने की अनुमति नहीं थी. उन्होंने अवैध तरीके से लोगों से पैसे एकत्रित किए हैं. इनमें से एक आरोपी अरुण अग्निहोत्री को आर्थिक अपराध शाखा ने गिरफ्तार कर लिया था और वह न्यायिक हिरासत में चल रहा है, लेकिन दूसरा आरोपी संजीव उपाध्याय जांच में शामिल नहीं हो रहा था. वह दिल्ली से फरार हो चुका था. पुलिस टीम लगातार उसकी तलाश में दबिश दे रही थी. पुलिस के दबाव के चलते संजीव उपाध्याय ने सरेंडर कर दिया. उसे आर्थिक अपराध शाखा ने गिरफ्तार कर लिया है और 3 दिन की रिमांड पर लिया है.

पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह और अरुण दोस्त हैं और राजधानी कॉलेज में साथ पढ़ते थे. वह रूस और उज्बेकिस्तान में छोटी-छोटी प्रदर्शनी आयोजित करते थे, जिनमें 20 से 25 स्टाल होते थे. वह इनमें से कुछ स्टॉल पर सजावट का सामान बेचते थे, जबकि अन्य स्टाल को किराए पर देते थे. उन्होंने लोगों को दिखाया कि वह बड़ा कारोबार करते हैं और इसमें मोटा मुनाफा है. उन्होंने लोगों को बताया कि उनके द्वारा जमा करवाई गई रकम को 18 से 24 महीने के भीतर डबल किया जाएगा. अभी तक की जांच से पता चला है कि लोगों ने पांच करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि उनके पास जमा कराई थी.

नामांकन पत्र में गलत जानकारी नहीं दी : प्रीति तोमर

नई दिल्ली, एजेंसी। आप विधायक प्रीति तोमर ने शुक्रवार को उच्च न्यायालय में कहा कि विधानसभा चुनाव के नामांकन पत्र में उन्होंने अपनी शैक्षणिक योग्यता के बारे में कोई गलत जानकारी नहीं दी थी। नामांकन पत्र में शैक्षणिक योग्यता के बारे में झूठी घोषणा करने का आरोप लगाते हुए चुनाव रद्द करने की मांग को लेकर दाखिल एक याचिका के जवाब में उन्होंने न्यायालय को यह जानकारी दी है। तोमर ने उच्च न्यायालय को बताया कि एमएससी और बीएड की डिग्री उनकी शादी से पहले के उनके नाम पर जारी हुई थी। शादी के बाद उन्होंने अपना नाम बदल लिया था। आप विधायक ने अपने जवाब में कहा कि पूर्व विधायक जितेंद्र सिंह तोमर के साथ शादी से पहले उनका नाम कुमारी तुलसा सोलंकी था और उनका पंजीकरण इसी नाम के साथ रघुनाथ गर्ल्स डिग्री कॉलेज में हुआ था जो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से संबद्ध है। उन्होंने कहा है कि इस विश्वविद्यालय को पहले मेरठ विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता था। वर्ष 1998 में शादी के बाद उन्होंने अपना नाम प्रीति तोमर रख लिया जिसकी घोषणा 2017 में दो दैनिक समाचार पत्रों में की गई थी। मार्च 2020 में एक बार फिर से उन्होंने अपना नाम बदलकर प्रीति जितेंद्र तोमर कर लिया। त्रिनगर से आप विधायक तोमर के चुनाव को रद्द करने की मांग को लेकर उनके विधानसभा क्षेत्र त्रिनगर के निवासी नवीन पराशर ने याचिका दाखिल की है। पाराशर ने याचिका में आरोप लगाया कि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में 1994 में बीएड का पाठ्यक्रम नहीं था, जहां से आप विधायक ने डिग्री हासिल करने का दावा किया है।

सिसोदिया ने स्कूल का दौरा कर बच्चों के साथ की चर्चा

बोले- हम जीरो कोरोना केस डे का इंतजार नहीं कर सकते

नई दिल्ली, एजेंसी। राजधानी दिल्ली के स्कूलों में शुक्रवार से नौवीं और 11वीं की कक्षाएं फिर से शुरू होने के बाद दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आज गांधी नगर इलाके में एक सरकारी स्कूल का दौरा किया और वहां टीचर्स और बच्चों से भी बात करने के साथ ही कोविड-19 प्रोटोकॉल की समीक्षा भी की। सिसोदिया दिल्ली के शिक्षा मंत्री भी हैं। सिसोदिया ने कहा कि हमें स्कूलों को फिर से खोलने का निर्णय करना पड़ा। हम उस दिन का इंतजार नहीं कर सकते जब कोरोना पूरी तरह खत्म हो जाएगा, क्योंकि तब तक हमारे बच्चों की पढ़ाई को काफी नुकसान हो चुका होगा। स्कूल में छात्रों से बातचीत में उन्होंने कहा कि छात्र अगर कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करें तो स्कूली जीवन भी सामान्य हो जाएगा।

इससे पहले दिल्ली सरकार ने बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए राजधानी

के सभी स्कूलों को दसवीं और 12वीं की कक्षाओं के फिर से संचालन की अनुमति दी थी।

सिसोदिया ने कहा कि 15 दिन पहले दसवीं और 12वीं कक्षाओं के लिए स्कूल खुले थे। मैं खुश हूं कि नौवीं और 11वीं के छात्रों के लिए भी स्कूल खुल गए हैं। मैं उनके चेहरे पर खुशी देख सकता हूं। महामारी के दौरान स्कूलों को खोलना चुनौती है, लेकिन हमने इसे स्वीकार किया है।

हमारे बच्चे स्कूलों को बहुत मिस कर रहे हैं, कोरोना से बचाव के साथ हमें बच्चों को स्कूल के माहौल में वापस लाना है, धीरे-धीरे ही सही बच्चों की स्कूली ज़िंदगी की खुशियां और रौनक अब वापस लौट रही हैं।

मनीष सिसोदिया ने ट्विटर पर अपने स्कूल दौरे की फोटो शेयर करते हुए कहा, "स्कूलों में आज 9वीं और 11वीं के बच्चे भी लौट आए हैं..जिंदगी में रौनक लौट आई है. जिंदगी को वापस पटरी पर लाने के लिए हम 'द जीरो कोरोना केस डे' का इंतजार नहीं कर सकते. हमें सावधानी से लेकिन कोरोना की चुनौती के बीच ही ज़िंदगी की रौनक वापस लानी है..और आज देखिए- ये हो रहा है..."

सिसोदिया की पोस्ट को रीट्वीट करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, "हमारे बच्चे स्कूलों को बहुत मिस कर रहे हैं, कोरोना से बचाव के साथ हमें बच्चों को स्कूल के माहौल में वापस लाना है, धीरे-धीरे ही सही बच्चों की स्कूली जिंदगी की खुशियां और रौनक अब वापस लौट रही हैं।

मनोज तिवारी ने मांगा केंद्र से क्षेत्र के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय

नई दिल्ली, एजेंसी। सांसद मनोज तिवारी ने अपने संसदीय क्षेत्र के लिए एक जवाहर नवोदय विद्यालय खोलने की मांग की है संसद में शून्यकाल के दौरान प्रश्न उठाते हुए मनोज तिवारी ने केंद्र सरकार से मांग की और संसदीय क्षेत्र में दिल्ली सरकार की उपेक्षा के चलते शिक्षा की बदतर व्यवस्था की ओर सदन का ध्यान आकर्षित कियाउन्होंने सदन को अवगत कराया कि दिल्ली सरकार की शिक्षा व्यवस्था बद से बदतर होती जा रही है जिसका खामियाजा हमारे संसदीय क्षेत्र के हजारों छात्रों को भी भुगतना पड़ रहा है उन्होंने सब सदन को अवगत कराया कि जब मैं दिल्ली सरकार द्वारा संचालित स्कूलों में गया तो वहां के छात्रों ने बताया कि वह प्रतिदिन दो से 3 घंटे ही पढ़ पाते हैं कई छात्रों ने तो यहां तक बताया कि सप्ताह में 3दिन ही विद्यालय जाने का उन्हें अवसर मिलता है क्योंकि छात्र-छात्राओं की संख्या अधिक और अध्ययन के लिए ऐसे विद्यालयों का

अभाव होने के कारण 1 स्कूल में 3 से लेकर चार चार पारियां लगती हैं जिसके कारण छात्रों को अध्ययन का पूरा समय नहीं मिलता है और उसके दुष्प्रभाव के चलते लाखों बच्चे परीक्षाएं उत्तीर्ण करने में असफल हो रहे है उन्होंने सदन से कहा कि एक जिम्मेदार सांसद होने के नाते दिल्ली सरकार की लचर शिक्षा व्यवस्था से मैं आहत हूं और सरकार से मांग करता हूं कि वह बच्चों के बेहतर भविष्य को ध्यान में रखते हुए हमारे संसदीय क्षेत्र में एक जवाहर नवोदय विद्यालय खोलें जिससे बच्चों को बेहतर भविष्य और अच्छी शिक्षा मिल सके मनोज तिवारी ने जारी प्रेस बयान में कहा कि 2014 के बाद क्षेत्र की गलियों में चुनाव के दौरान भी और उसके बाद भी जब भी मैं गया मैंने प्रतिभाओं की भरमार देखी लेकिन साधनों का अभाव भी स्पष्ट दिखाई दिया और मैंने शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए अपने संसदीय क्षेत्र में तीन केंद्रीय विद्यालय खुलवाने का प्रयास शुरू किया इनमें से एक शहादरा केंद्रीय विद्यालय बनकर तैयार है बाकी दो केंद्रीय विद्यालय खजूरी खास और बुराड़ी में बनाने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है उन्होंने कहा कि हर स्तर से पिछड़ा हुआ संसदीय क्षेत्र मुझे विरासत में मिला जिस में तेजी से सुधार लाते हुए विकास के कई काम पूरे किए लेकिन शिक्षा के बगैर न तो समाज का विकास संभव है और ना ही क्षेत्र का क्योंकि हर काम के लिए जागरूकता जरूरी है और जागरूकता के लिए शिक्षित होना जरूरी है।

संपादकीय

दिल्ली पर फिर आंच न आए

मंगलवार को एक तरफ राजपथ पर राष्ट्र के गौरव का प्रदर्शन हो रहा था, तो दूसरी ओर दिल्ली के कुछ इलाकों में कानून-व्यवस्था को निशाना बनाया जा रहा था। यह एक शोचनीय स्थिति थी। ऐसा इसलिए हो रहा था, क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी की सीमा पर करीब 60 दिनों से जमे किसानों को 26 जनवरी की सुबह 12 बजे से ट्रैक्टर परेड निकालने की अनुमति दी गई थी, मगर उनका वह मार्च 9.30 बजे ही शुरू हो गया था। दिल्ली पुलिस पर काम का बोझ पहले से अधिक है, फिर 26 जनवरी को वह विशेष तनाव में रहती है। राजपथ पर निकलने वाली परेड और झांकियों के लिए रूट की व्यवस्था करने के साथ-साथ उसे आतंकवादी हमले या अन्य व्यवधानों से निपटने के लिए खास जतन करने पड़ते हैं। ऐसे में, भीड़ द्वारा पुलिसकर्मियों को निशाना बनाने और लाल किला पर केसरिया झंडा फहराने की तस्वीरें ऐसी हैं, जिनको आसानी से भुलाया नहीं जा सकेगा। महज 20 दिन पहले ही हमने अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन में लोकतंत्र पर हमला होते देखा था। उस दिन बड़ी संख्या में उपद्रवी अमेरिकी संसद अर्थात कैपिटल हिल में दाखिल हो गए थे, जिससे चुने गए जन-प्रतिनिधियों की जान सांसत में आ गई थी। उस घटना में चार लोगों की मौत हुई और कई सुरक्षाकर्मी घायल हुए थे। वह अमेरिकी लोकतंत्र के इतिहास में काले दिन के रूप में देखा गया। ठीक यही धब्बा 26 जनवरी को हमारे गणतंत्र पर भी लग गया है। यह घटना आंदोलन के हिंसक होने का एक और उदाहरण है। यहां मुझे 1988 के उस किसान आंदोलन की याद हो आती है, जो भारतीय किसान यूनियन के तत्कालीन नेता महेंद्र सिंह टिकैत की अगुवाई में हुआ था। उल्लेखनीय है कि महेंद्र सिंह टिकैत उन्हीं राकेश टिकैत के पिता थे, जो मौजूदा किसान आंदोलन के नेताओं में शामिल हैं। वह एक ऐसा आंदोलन था, जिसमें पहली बार दिल्ली में किसानों की ताकत दिखी थी। बिजली, सिंचाई की दरें घटाने, फसलों की उचित कीमतें मिलने सहित करीब 35 मांगों के साथ विशेषकर उत्तर प्रदेश और हरियाणा के हजारों किसानों ने दिल्ली के बोट क्लब पर डेरा डाल दिया था। वे बसों, रेलों, बैलगाड़ियों आदि पर सवार होकर दिल्ली में दाखिल हुए थे। मैं उन दिनों नई दिल्ली (तब दिल्ली को प्रशासनिक स्तर पर बांटा नहीं गया था) के अतिरिक्त कमिश्नर के पद पर नियुक्त था। आंदोलन कर रहे किसानों की नाराजगी शांत करने के लिए हमने कई तरह के उपाय किए। जैसे, लाउडस्पीकर लगाकर उन्हें गाना सुनाया, उनकी सुविधाओं का ख्याल रखा, उनके लिए अस्थाई बाथरूम व शौचालय बनवाए, खाना बनाने में उनकी मदद की। देखा जाए, तो हमने एक तरह से उनसे रिश्ता बना लिया था। उन्हें यह भरोसा देने में सफल रहे थे कि हम उनके अपने हैं, जबकि उपद्रवियों ने उस समय भी जमकर तोड़फोड़ की थी। मैं उस समय बापा नगर में रहता था और अपने घर के सामने तीन-चार मटके लगाए थे, ताकि जरूरतमंदों की प्यास बुझ सके। हुड़दंगियों ने उन सबको तोड़ दिया था। वे एकाध आंदोलनकारियों की मौत पर भी हंगामा कर रहे थे। मगर दिल्ली पुलिस उन सबको समझाने-बुझाने में सफल रही थी।

यह अनुभव बताता है कि दिल्ली पुलिस के पास कठिन परिस्थितियों से निपटने का पर्याप्त अनुभव है। वह इन सबसे लोहा लेने में दक्ष है। 26 जनवरी को उसने अपने धैर्य का बखूबी परिचय दिया। पुलिसकर्मियों पर लाठी-डंडे और लोहे के रॉड से हमले किए गए। उनको ट्रैक्टर से कुचलने का प्रयास किया गया। बावजूद इसके उन्होंने संयम दिखाया। उपद्रवियों की उकसाने की कार्रवाइयों का पुलिस ने शांतिपूर्वक जवाब दिया। यही वजह है कि इस घटना में 300 से भी अधिक पुलिसकर्मियों के घायल होने की सूचना आ रही है। सवाल अब यह है कि इस तरह के आंदोलनों से पुलिस को किस तरह निपटना चाहिए? शांतिपूर्ण विरोध-प्रदर्शन लोगों का मौलिक सांविधानिक अधिकार है। ऐसे प्रदर्शन लोकतंत्र में सेफ्टी वॉल्व का काम करते हैं। मगर अपने यहां दिक्कत यह है कि आबादी के हिसाब से पुलिसकर्मियों की संख्या बहुत कम है। आंकड़े बताते हैं कि भारत में प्रति लाख जनसंख्या पर महज 144 पुलिसकर्मी तैनात हैं, जबकि संयुक्त राष्ट्र तक मानता है कि 1,00,000 की आबादी पर कम से कम 222 पुलिसकर्मियों की नियुक्ति होनी चाहिए। यही वजह है कि अपने यहां पुलिस बल पर अतिरिक्त जिम्मेदारी आ जाती है। वह इस सवाल से भी जूझती है कि उसे आंदोलनकारियों की मर्जी के मुताबिक जगह आवंटित करनी चाहिए या किसी खास जगह पर आंदोलन की इजाजत देनी चाहिए? सौभाग्य से, दिल्ली-एनसीआर को लेकर कई अदालती आदेश यह बताते हैं कि यहां आंदोलन खास जगहों पर ही होने चाहिए। हमें इसका ख्याल रखना होगा। साथ ही, आंदोलन को लेकर तमाम खुफिया जानकारी पुलिस से साझा की जानी चाहिए और हर स्थिति से निपटने के लिए पुलिस के पास पूरी प्लानिंग होनी चाहिए। लोकतांत्रिक संस्थाओं को भी इतना मजबूत होना चाहिए कि वे इस तरह की चुनौती से लोकतांत्रिक उपायों से पार पा सकें। वैसे, मैं अब भी यही मानता हूं कि दिल्ली पुलिस के पास पर्याप्त अनुभव है और वह हर स्थिति का सामना करने में सक्षम है। भविष्य में दिल्ली इस तरह से बंधक न बने, इसके लिए यह भी जरूरी है कि 26 जनवरी की हिंसा के दोषी बख्शे न जाएं। उन्हें न्याय के कठघरे में खड़ा किया जाना चाहिए। इसका मतलब है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच हो और हिंसा के जिम्मेदार लोगों को सजा मिले। यहां वे किसान नेता अपनी जवाबदेही से नहीं बच सकते, जिन्होंने शांतिपूर्ण ट्रैक्टर परेड का आश्वासन दिया था या जिन्होंने इस मार्च के लिए अनुमति मांगी थी। एक जरूरत उन कानूनों को मजबूत करने की भी है, जिनसे देश को लोकतांत्रिक दिशा मिलती है। इन सभी उपायों पर अमल न सिर्फ शांति बहाली के लिए, बल्कि लोकतंत्र की बेहतरी के लिए भी जरूरी है।

प्रवीण कुमार सिंह

आयुर्वेद में सर्जरी करने के अधिकार का सवाल है अहम, अधिक व्यवहारिक बनाना ज्यादा जरूरी

संबंधित शासनादेश का सबसे कमजोर पक्ष आयुर्वेद संस्थान, शिक्षक, छात्र व चिकित्सक हैं, जो अपने संस्थानों की स्थिति सुधारने, समयानुकूल प्रायोगिक और व्यावहारिक बनाने, कौशल विकास करने और बजट बढ़ाने के लिए कभी मुखर होकर अपनी बात नहीं रखते हैं। विचित्र बात यह है कि एलोपैथी का एक संगठन सरकार को फैसले बदलने के लिए विवश कर देता है, परंतु आयुर्वेद के सैकड़ों संगठन एकजुट होकर कभी बजट बढ़ाने, कॉलेज में फैकल्टी, लैब्स, ओपीडी व पाठ्यक्रम को अधिक व्यावहारिक बनाने समेत कार्यकुशलता का विकास करने के लिए मुखर होते या आंदोलन करते नहीं दिखते हैं।

सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन (सीसीआइएम), आयुष मंत्रलय एवं यूजीसी के अंतर्गत आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी के शिक्षण-प्रशिक्षण के लिए कार्यदायी संस्था है, जिसने नवंबर 2020 में आयुर्वेद चिकित्सकों को सर्जरी करने संबंधित शासनादेश जारी किया। इसके तहत आयुर्वेद चिकित्सक सामान्य सर्जरी सहित हड्डी, नाक, कान, गले एवं आंख की सर्जरी कर सकेंगे। इस आदेश के बाद से देश का स्वास्थ्य तंत्र दो फाड़ हो गया। एलोपैथी चिकित्सक विरोध पर उतर आए तो आयुर्वेदिक चिकित्सक समर्थन में निकल पड़े। इस स्थिति पर गंभीर दृष्टि डालने पर लगता है कि सीसीआइएम ने अपने भ्रम में एलोपैथी-आयुर्वेद दोनों पद्धतियों के चिकित्सकों को उलझा दिया। इस मामले में सीसीआइएम या सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए था कि नवंबर 2020 के पहले से आयुर्वेद संस्थानों द्वारा जो शल्य-शलाक्य (सर्जरी एवं आंख, नाक, कान व गले की सर्जरी) की पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री दी जा रही थी, क्या वह अवैध थी? प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय परीक्षाओं के माध्यम से चयनित होकर एमएस आयुर्वेद की डिग्री लेकर निकलने वाले आयुर्वेदिक सर्जन क्या अवैध थे? यहां सरकार या सीसीआइएम का शासनादेश हास्यापद प्रतीत होता है। जब आयुर्वेद चिकित्सकों को सर्जरी का अधिकार ही नहीं था, तो एमएस आयुर्वेद का पाठ्यक्रम क्यों और कैसे चलाया जा रहा था? आयुर्वेद में सर्जरी को शल्य तथा आंख, नाक, कान, गले की सर्जरी को शलाक्य कहते हैं। यह उपाधि प्राप्त करने वाले चिकित्सक अभी तक क्या कर रहे थे? यह प्रश्न सीसीआइएम, एलोपैथिक व आयुर्वेदिक चिकित्सकों के लिए अनुत्तरित है।

शासनादेश का विरोध करने वाले एलोपैथी चिकित्सकों को आयुर्वेद व उसके पाठ्यक्रम के बारे में क्या कोई जानकारी नहीं है? यदि नहीं तो विरोध के पहले क्या जानने की कोशिश भी की है? या सर्जरी के अपने बाजार को बचाने के लिए मैदान में उतर गए हैं। इसी तरह आयुर्वेद चिकित्सकों ने भी अपने शिक्षण-प्रशिक्षण व कौशल की स्थिति का आकलन करने की जहमत नहीं उठाते हुए खुशफहमी पाल ली है।

एलोपैथी चिकित्सक इतना भी नहीं सोच पा रहे हैं कि आयुष की डिग्री में जो एस यानी बीएएमएस या बीयूएमएस जुड़ा होता है, उसका तात्पर्य सर्जरी ही होता है। आयुर्वेद चिकित्सकों को यहीं सर्जरी का अधिकार प्राप्त हो जाता है। यह अलग बात है कि आयुर्वेद संस्थानों ने अपने छात्रों को कुशल सर्जन बनाने का प्रयास नहीं किया है। जबकि सीसीआइएम की अनुमति से पोस्ट ग्रेजुएट स्तर पर सर्जरी विशेषज्ञता की एमएस की उपाधि वर्षों से दी जा रही है। इस उपाधि के साथ ही आयुर्वेद चिकित्सकों को शल्यकर्म की अनुमति स्वत- मिल जाती है।

वर्तमान में इस आशय के शासनादेश की जरूरत क्यों पड़ी? यह संदेह होता है कि पाठ्यक्रम शुरू करते समय विधिक स्थिति स्पष्ट नहीं थी।

अब एलोपैथिक चिकित्सकों के संगठन आइएमए के विरोध के औचित्य को देखें तो उन्हें उसी समय विरोध करना चाहिए था, जब सरकार ने आयुर्वेद पाठ्यक्रम निर्धारित करते हुए बीएमएमएस, एसएस आयुर्वेद यानी बैचरल ऑफ आयुर्वेद एंड सर्जरी व एसएस आयुर्वेद का पाठ्यक्रम शुरू किया था। आइएमए को अध्ययन करना चाहिए था कि शल्यकर्म आयुर्वेद का अंग है या एलोपैथी से लिया गया है। उधर स्वास्थ्य क्षेत्र के स्वयंभू कर्णधार एलोपैथी समुदाय का स्वास्थ्य क्षेत्र की पूरक संस्थाओं के बारे में ज्ञान शून्य होना कम खेद का विषय नहीं है। इसकारण वे आयुर्वेद को आभासी चिकित्सा पद्धति मानते हैं। हालांकि उन्हें यह बखूबी पता है कि आयुर्वेद स्नातक-परास्नातक पाठ्यक्रम के लिए वही परीक्षा देनी होती है, जो एलोपैथी में प्रवेश के लिए देनी होती है। इसका तात्पर्य है कि आयुर्वेद का भी एक निश्चित पाठ्यक्रम होता है, जिसमें वे सारे विषय शामिल होते हैं जो एक चिकित्सा विज्ञान के पाठ्यक्रम में होने चाहिए, जिसमें प्राचीन ज्ञान के साथ नवीनतम जानकारियां भी शामिल हैं। ऐसा नहीं है कि चरक, सुश्रुत आदि ने जो लिख दिया वही आयुर्वेद हजारों साल से चल रहा है। उपलब्ध संसाधनों व आवश्यकता के अनुरूप समकालीन प्रयोग होते रहे हैं, जो ज्ञान आयुर्वेद में जुड़ता रहा है और आज भी जुड़ रहा है। यह प्रवृत्ति आयुर्वेद को निश्चित ही विज्ञान सिद्ध करने लिए पर्याप्त है।

देखा जाए तो एलोपैथी समुदाय द्वारा अज्ञानता में नहीं, बल्कि जानबूझकर इस तथ्य की उपेक्षा की जा रही है, ताकि आयुर्वेद के अभिन्न अंग शल्य-शलाक्य (सर्जरी) को खारिज करते हुए स्वास्थ्य के बाजार पर अपना एकाधिकार बनाया जा सके। एलोपैथी समुदाय इसी उद्देश्य से आयुर्वेद की तात्कालिक प्रभाव वाली रासायनिक-धात्विक औषधियों के विरुद्ध षड्यंत्रकारी शोध कर हानिकारक सिद्ध करने में सफल हो चुका है। निश्चित तौर पर इससे आयुर्वेद चिकित्सा का पक्ष कमजोर हुआ है। सबसे दुखद यह है कि सरकार और आयुर्वेद संस्थानों, शिक्षकों, छात्रों और चिकित्सकों ने भी आयुर्वेद की रासायनिक औषधियों को हानिकारक मान लिया है, जबकि यही औषधियां एलोपैथिक रासायनिक औषधियों की विकल्प हैं।

यहां यह भी उल्लेख करना आवश्यक है कि आयुर्वेद की जिन औषधियों को एलोपैथी हानिकारक कहता है, वही आधुनिक यंत्रों, विधियों से निर्मित होकर हर्बल एलोपैथिक की प्रमाणिक प्रभावी औषधियां बन जाती हैं। इसलिए ऐसा लगता है कि एलोपैथिक चिकित्सकों नें जानबूझकर आयुर्वेद पाठ्यक्रम को जानने की कोशिश नहीं की है, या फिर जानते हुए अनजान बनने का स्वांग कर रहे हैं, क्योंकि इससे उनके व्यावसायिक वर्चस्व की जंग कमजोर पड़ सकती है या विरोध करने का नैतिक साहस खत्म हो सकता है।

संबंधित शासनादेश का सबसे कमजोर पक्ष आयुर्वेद संस्थान, शिक्षक, छात्र व चिकित्सक हैं, जो अपने संस्थानों की स्थिति सुधारने, समयानुकूल प्रायोगिक और व्यावहारिक बनाने, कौशल विकास करने और बजट बढ़ाने के लिए कभी मुखर होकर अपनी बात नहीं रखते हैं। विचित्र बात यह है कि एलोपैथी का एक संगठन सरकार को फैसले बदलने के लिए विवश कर देता है, परंतु आयुर्वेद के सैकड़ों संगठन एकजुट होकर कभी बजट बढ़ाने, कॉलेज में फैकल्टी, लैब्स, ओपीडी व पाठ्यक्रम को अधिक व्यावहारिक बनाने समेत कार्यकुशलता का विकास करने के लिए मुखर होते या आंदोलन करते नहीं दिखते हैं। एलोपैथिक औषधियों के विकल्प रसशास्त्र यानी आयुर्वेदिक रसायन विज्ञान से वे ऐसे बचते हैं, जैसे वह आयुर्वेद का अंग ही न हो। इसका कारण भी एलोपैथिक सिस्टम के षड्यंत्रकारी शोध हैं। आयुर्वेद की पराजय यहीं हो जाती है, जब अपनी दवाओं को एलोपैथी के शोधकर्ताओं के कहने पर हानिकारक मान लेते हैं। इस स्थिति में एलोपैथिक चिकित्सक या जनता, भला कैसे आयुर्वेद के सर्जरी कौशल पर विश्वास करेगी?

देश में नहाने से भी ज्यादा जरूरी और भी काम हैं, पर उनकी किसी को फिक्र नहीं

कहते हैं मुसीबत अकेले नहीं आती। एक ठीक से जा भी नहीं पाती कि दूसरी और 'बेहतर' तरीके से हमें दबोच लेती है। वायरस से बचाव के बाद अब ठंड से बचने के जतन करने पड़ रहे हैं। इसी के साथ वैक्सीन लगवाने की भी तैयारी करनी पड़ रही है। रजाई में घुसा हुआ वैक्सीन लगवाने की हिम्मत जुटा ही रहा था कि श्रीमती जी ने नहाने के लिए अंतिम चेतावनी जारी कर दी। शहर में हफ्ते भर से जारी शीतलहर की खबर शायद उन तक नहीं पहुंच पाई थी। मैं उन्हें पहले भी सूचित कर चुका हूं कि अभी संक्रांति पर ही तो 'अस्नान' किया था। लगता है, मेरी इस बात का श्रीमती जी से ज्यादा मौसम ने बुरा मान लिया। उसने हवाओं को भी अपने साथ मिला लिया। मासूम-सी मेरी जान के खिलाफ पूरी कायनात जुट गई। मेरी हालत देखिए कि इस 'अत्याचार' और 'शोषण' के विरुद्ध मैं कोई आंदोलन भी नहीं कर सकता। मैंने श्रीमती जी के प्रस्ताव पर दसवीं बार गंभीरता से सोचना शुरू कर दिया।

पहले तो रजाई ही मुझे नहीं छोड़ रही थी। मुझसे ज्यादा तो वह बेचारी ठंडी थी। बचपन में पढ़ी 'त्याग' और 'बलिदान' की कहानियों को एक-एक कर याद किया। मैंने रजाई से क्षमा मांगी और 'आत्म-बलिदान' के लिए खुद को सशरीर प्रस्तुत कर दिया। जैसे ही हमारे चरण संगमरमरी फर्श पर पड़े, अंगद के पांव की तरह वहीं जम गए। हमने मन ही मन 'हनुमान चालीसा' का पाठ शुरू कर दिया। थोड़ी संजीवनी पाकर मैं स्नानघर के दरवाजे की ओर बढ़ा। घटनास्थल तक मैं ऐसे पहुंचा, जैसे कसाई बकरे को जिबह के लिए पकड़कर ले जाता है। मामला केवल नहाने या सफाई भर का होता

तो कोई न कोई तोड़ मैं निकाल ही लेता, पर बात यहां तक पहुंच गई थी कि हमारे न नहाने से यदि कोई संक्रामक बीमारी फैली तो उसका सीधा-सीधा जिम्मेदार मैं ही होऊंगा। घर के बाहर का मसला होता तो 'जल-संरक्षण' पर गर्म बयान देकर निकल लेता, लेकिन यहां बात बिल्कुल निजी थी और संवेदनशील भी।

मेरे सामने अब कोई चारा न था। केवल आधी बाल्टी पानी था, जो बड़ी देर से मुझे ललकार रहा था। बाल्टी की ओर से नजरें हटाकर बाहर की ओर देखा, पर कोहरे की घनी चादर ने हमें वहीं ठिठका दिया। बाहर की धुंध के बजाय मुझे बाल्टी के अंदर का खुलापन ज्यादा अच्छा लगा। इससे मुझे बड़ी हिम्मत मिली। पानी से अध-भरा डिब्बा पहले मैंने अपनी हिम्मत पर ही उड़ेला, वह वहीं जम गई। अंगुलियों ने आपस में सहयोग करने से एकदम इन्कार कर दिया। अभी तक मैं ठीक से पानी के संसर्ग में आया भी नहीं था कि बाहर से श्रीमती जी की नसीहत आई, 'अजी सुनते हो! साबुन वहीं रखा है, उसे भी आजमा लेना।' इतना सुनते ही मेरे बचने की सारी उम्मीदें ध्वस्त हो गईं। मैंने झट से पानी का दूसरा डिब्बा साबुन पर ही न्योछावर कर डाला। बाल्टी में अभी भी काफी पानी था, जो मुझे लगातार घूर रहा था। मुझे उसे भी खत्म करना पड़ा। जब बाथरूम में मेरे नहाने के सारे साक्ष्य मौजूद हो गए, 'अच्छे दिनों' के तौलिए में लिपटकर मैं बाहर आ गया।

बाथरूम के बाहर जश्न का माहौल था। बच्चों ने हमारे स्वागत की पूरी तैयारी कर रखी थी। रेडियो में देशभक्ति के गाने बज रहे थे। श्रीमती जी ने गोभी के गरम पकौड़ों के साथ गिलास भर चाय हमारे सामने पेश कर दी। पकौड़े खाते हुए मैं सोचने लगा कि देश में हमारे नहाने से भी ज्यादा जरूरी और भी काम हैं, पर उनकी किसी को फिक्र नहीं। कुछ कानून स्थगित हैं, कुछ की वैक्सीन स्थगित है। एक पार्टी ने तो 'ठंड' के प्रकोप से बचने के लिए अपने अध्यक्ष का चुनाव गर्मियों तक स्थगित कर दिया। फिर मेरा नहाना कुछ दिनों के लिए क्यों नहीं स्थगित हो सकता है यही सवाल मैंने श्रीमती जी से कर दिया। श्रीमती जी पहले से ही तैयार बैठी थीं। कहने लगीं, 'लगता है तुम्हारे दिमाग में सर्दी ज्यादा चढ़ गई है, जो सर्र-बर्र बक रहे हो। इसीलिए कहती हूं, रोज नहाया करो। इम्युनिटी मजबूत होगी और दिमाग भी ठीक रहेगा।' अचानक मेरी नजर अखबार की ओर गई। पहली ही खबर थी, 'ठंड ने बीस साल का रिकॉर्ड तोड़ा। इतना पढ़ते ही पकौड़े छोड़कर मैं रजाई में फिर से समा गया!

लकड़ी नहीं हैं पेड़

सुप्रीम कोर्ट ने वृक्षों की सही कीमत आंकने के लिए जो विशेषज्ञ समिति गठित की थी, उसके द्वारा इसके तरीकों को लेकर की गई सिफारिशें देश को नई दिशा देने वाली हैं। पश्चिम बंगाल की एक रेलवे ओवरब्रिज परियोजना से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल जनवरी में इस पांच सदस्यीय समिति का गठन किया था। पेड़ों से निकलने वाली लकड़ी की मात्रा के आधार पर उनका मूल्य तय करने की परिपाटी को गलत बताते हुए समिति ने कहा है कि पूरे परिवेश में उनके योगदान को ध्यान में रखते हुए ही उनकी कीमत तय की जा सकती है। इस समझ के आधार पर समिति का निष्कर्ष यह है कि एक पेड़ की कीमत साल भर में 74,500 रुपये बैठती है। जाहिर है, जो पेड़ जितना पुराना होगा, उसकी कीमत भी इस दृष्टि से उतनी ही ज्यादा होगी।

समिति के मुताबिक सौ साल का भरा-पूरा पेड़ एक करोड़ रुपये से भी ज्यादा कीमती हो सकता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी इस रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया है और इस पर केंद्र सरकार समेत तमाम पक्षों से राय मांगी गई है। यह डर स्वाभाविक है कि अगर इन सिफारिशों को ज्यों का त्यों लागू कर दिया गया तो हर परियोजना की लागत इतनी बढ़ जाएगी कि न सिर्फ उन्हें बना रही कंपनियों बल्कि सरकारों के भी दिवालिया होने का खतरा पैदा हो जाएगा। फिर भी हमें इतना तो स्वीकार करना ही पड़ेगा कि पेड़ महज लकड़ी नहीं हैं। वे न केवल खुद में एक जिंदा चीज हैं बल्कि असंख्य जीवों के आश्रय के रूप में एक पूरी दुनिया की भूमिका निभाते हैं। समिति ने ठीक ही कहा है कि किसी भी परियोजना को अंतिम रूप देते समय यह देखा जाना चाहिए कि कितने पेड़ उसकी राह में आ रहे हैं। संभव हो तो परियोजना के स्थान और स्वरूप में बदलाव करके पेड़ों को बचा लेना चाहिए। और ऐसा न हो सके तो पहली कोशिश पेड़ों की जगह बदलने की होनी चाहिए। अंतिम विकल्प के रूप में पेड़ काटने ही पड़ें तो भी एक पेड़ के बदले पांच पौधे लगाने का चलन नाकाफी है।

समिति का कहना है कि छोटे आकार के पेड़ के लिए 10, मध्यम आकार के वृक्ष के लिए 25 और बड़े आकार के वृक्ष के लिए 50 पौधे रोपे जाने चाहिए। एक जरूरत यह भी है कि ऐसे हर पौधारोपण कार्यक्रम की पांच साल बाद ऑडिटिंग करना अनिवार्य बनाया जाए ताकि इसका पूरा ब्योरा उपलब्ध रहे कि जितने पौधे लगाए गए उनमें से कितने वृक्ष के रूप में विकसित हो पाए हैं। गौरतलब है कि समिति की यह सिफारिश ऐसे समय में आई है जब मंदी से उबरने के लिए सरकार का सारा जोर देश में ज्यादा से ज्यादा इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित करने पर है। ऐसे में यह सुनिश्चित करना जरूरी हो जाता है कि विकास के नाम पर कहीं हमारे परिवेश का ऐसा नुकसान न हो जाए, जिससे आगे चलकर उबरा ही न जा सके।

समर्थन मूल्य पर सरकारी खरीद ने पंजाब में जो समस्याएं पैदा कीं, वही अब दूसरे राज्यों में भी फैल रही हैं

ऐसे में इस वर्ग की आय में बढ़ोतरी मांग को बढ़ावा देगी। यानी श्रम सुधार इन निम्न मध्यम आय वाले परिवारों के लिए घरेलू आय में वृद्धि करके मांग को बढ़ावा देगा और मांग बढ़ने से जीडीपी में वृद्धि होगी। जब सरकार किसी कंपनी को कर छूट देती है तो वह तत्काल निवेश या खर्च में तब्दील नहीं होता, लेकिन किसी कामगार को 500 रुपये भी अतिरिक्त मिलता है तो वह कुछ जरूरत की नई चीजें खरीदना चाहता है, जो तत्काल मांग पैदा करता है।

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तीन कृषि कानूनों के अमल पर अस्थायी रोक के बावजूद किसान संगठनों का अड़ियल रवैया कायम है। यही कारण है कि किसान संगठनों के साथ सरकार की दसवें दौर की वार्ता भी बेनतीजा रही। किसान संगठन तीन नए कृषि कानूनों को रद करने और न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की गारंटी की मांग पर अड़े हैं। उनका सबसे ज्यादा जोर एमएसपी पर सरकारी खरीद की गारंटी पर है। इसमें दोराय नहीं कि कृषि उत्पादन बढ़ाने और किसानों को एक निश्चित आमदनी सुनिश्चित कराने में एमएसपी की अहम भूमिका रही है, लेकिन फिर एमएसपी वोट बैंक की राजनीति का जरिया बन गया। नेताओं में राजनीतिक हित लाभ के लिए ऊंचा एमएसपी घोषित करने की होड़ मच गई। यदि एमएसपी का सबसे ज्यादा फायदा पंजाब के किसानों को मिला तो उसके दुष्परिणाम भी उसे ही झेलने पड़े हैं। शायद इसी कारण किसान आंदोलन का केंद्र बिंदु भी पंजाब बन चुका है। एमएसपी की राजनीति को समझने के लिए पंजाब से बेहतर दूसरा उदाहरण नहीं हो सकता।

खाद्यान्न आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए किसानों को उन्नत बीजों के साथ रियायती दरों पर उर्वरकों, कीटनाशकों, रसायनों के इस्तेमाल के लिए प्रोत्साहित किया गया। इसके चलते पंजाब में परंपरागत फसलों को छोड़कर गेहूं-धान की खेती की जाने लगी। 1960-61 में पंजाब में गेहूं की खेती 14 लाख हेक्टेयर और धान की खेती 2.27 लाख हेक्टेयर में होती थी, जो 2019-20 में

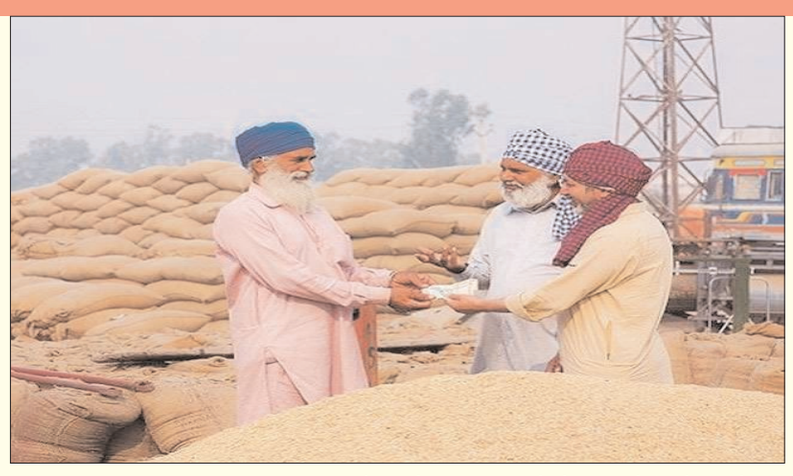

बढ़कर क्रमशः 35.08 लाख हेक्टेयर और 29.20 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गई।

रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों आदि के अंधाधुंध इस्तेमाल से शुरू में तो पैदावार बढ़ी, लेकिन आगे चलकर इसमें गिरावट आनी शुरू हुई। उदाहरण के लिए पंजाब में 1972 से 1986 के बीच कृषि वृद्धि दर 5.7 फीसद रही जो 1987 से 2004 के बीच 3 फीसद और 2005 से 2014 के बीच घटकर महज 1.6 फीसद रह गई। एक ओर खेती की लागत बढ़ी तो दूसरी ओर उपज से होने वाली आमदनी घटी। परिणामस्वरूप किसान कर्ज के दुष्चक्र में फंसते चले गए। राजनीतिक दलों और सरकारों ने किसानों को कर्ज के दुष्चक्र से बाहर निकालने के लिए खेती को फायदे का सौदा बनाने के बजाय मुफ्त बिजली-पानी का पासा फेंका। इससे हानिकारक होने के बावजूद गेहूं-धान के फसल चक्र को बढ़ावा मिला।

पंजाब में मुफ्त बिजली के पांसे का नतीजा 14 लाख नलकूपों के रूप में सामने आया। आज पंजाब के प्रत्येक नलकूप धारक किसान को सालाना 45,000 रुपये सब्सिडी मिलती है। इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि पंजाब में भूजल तेजी से नीचे गिरा। भूजल की दृष्टि से आज पंजाब के 137 ब्लॉकों में से 110 ब्लॉक अति दोहित की श्रेणी में आ चुके हैं। इसके बावजूद पंजाब के किसान संगठन गेहूं-धान की सरकारी खरीद की गारंटी के लिए आंदोलन कर रहे हैं।

समर्थन मूल्य पर सरकारी खरीद ने पंजाब में जो समस्याएं पैदा की हैं, वही समस्याएं अब दूसरे राज्यों में भी फैल रही हैं, क्योंकि सरकारें गेहूं-धान की सुनिश्चित सरकारी खरीद के जरिये किसानों का वोट हासिल करना चाहती हैं। मध्य प्रदेश में गेहूं की सरकारी खरीद को मिले प्रोत्साहन का नतीजा है कि आज वह पंजाब को पीछे छोड़ते हुए पहले नंबर पर आ चुका है। 2019-20 में मध्य प्रदेश में गेहूं की रिकॉर्ड 1.27 करोड़ टन की सरकारी खरीद हुई। इसी तरह छत्तीसगढ़ सरकार ने 2020-21 के खरीफ सत्र के लिए 2500 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से धान खरीदने का एलान किया है। गेहूं-धान को मिले सरकारी प्रोत्साहन का ही नतीजा है कि आज देश के गोदाम गेहूं-चावल से पटे पड़े हैं। 2020 के खरीफ सत्र से पहले देश में 280 लाख टन चावल का भंडार था, जो पूरी दुनिया को खिलाने के लिए पर्याप्त है।

एमएसपी पर सरकारी खरीद के चक्रव्यूह के कारण ही किसानों ने गन्ने की खेती को प्राथमिकता दी। इसका नतीजा चीनी के बंपर उत्पादन के रूप में सामने आया। इस साल सरकार ने 600 करोड़ रुपये की सब्सिडी देकर 60 लाख टन चीनी का निर्यात किया, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में चीनी की कीमत 22 रुपये किलो है, जबकि भारत में समर्थन मूल्य पर गन्ने की खरीद से चीनी 34 रुपये किलो पड़ रही है। गेहूं, धान और गन्ने की खेती को मिली गलत प्राथमिकता का नतीजा यह हुआ कि दलहन, तिलहन और मोटे अनाजों की खेती पिछड़ती गई, जिससे उनकी पैदावार तेजी से घटी। आज जिस देश के गोदाम गेहूं-चावल से भरे पड़े हैं, वही देश हर साल एक लाख करोड़ रुपये का खाद्य तेल और दालें आयात करता है। इसी तरह सरकार हर साल आठ लाख करोड़ रुपये का पेट्रोलियम पदार्थ आयात करती है। इस भारी भरकम आयात से बचने के लिए सरकार गेहूं, धान और गन्ने से एथनॉल उत्पादन को बढ़ावा देने की नीति पर काम कर रही है। इससे एक ओर पेट्रोलियम आयात पर निर्भरता कम होगी तो दूसरी ओर गेहूं, चावल के भंडारण में होने वाले भारी भरकम खर्च से बचा जा सकेगा।

सबसे बड़ी समस्या यह है कि छोटे किसानों के पास अपनी उपज बेचने का नेटवर्क नहीं है। इन किसानों की मंडी व्यवस्था तक पहुंच बनाने के लिए सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक मंडी यानी ईनाम नामक पोर्टल शुरू किया है। इसके अलावा उत्पादन क्षेत्रों को खपत केंद्रों से जोड़ने के लिए किसान रेल चल रही है, जिससे बिना बिचौलिये के किसानों की उपज सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंच रही है। केंद्र सरकार छोटे किसानों को किसान उत्पादन संगठन (एफपीओ) से भी जोड़ रही है, ताकि वे बाजार अर्थव्यवस्था से कदमताल कर सकें। इन एफपीओ को किसी कंपनी जैसी सुविधाएं मिल रही हैं। स्पष्ट है कि सरकार एक फसली खेती को बढ़ावा देने वाली एमएसपी से आगे बढ़कर बहुफसली खेती की ओर कदम बढ़ा रही है।

गौरवशाली भारत के स्वामी प्रकाशक एवं मुद्रक प्रवीण कुमार सिंह द्वारा आला प्रिंटिंग प्रेस 3636 कटारा दिना बेग लाल कुआं, दिल्ली.... से मुद्रित एवं, ब्लॉक नं. 23 मकान नं. 399 त्रिलोकपुरी दिल्ली....91 से प्रकाशित संपादक -प्रवीण कुमार सिंह टेलीफोन नं. 011.22786172 फैक्स नं. 011.22786172
RNI, No. DELHIN383334, E-mail: gauravashalibarat@gmail.com इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के पीआरबी एट के तहत

संक्षिप्त खबर

अवॉर्ड वापसी के अगुआ उदय प्रकाश ने दिया अयोध्या में श्रीराम मंदिर के लिए दान, रसीद पोस्ट करते हो गए ट्रोल

लखनऊ । पांच साल पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार लौटाकर अवॉर्ड वापसी की प्रथा प्रारंभ करने वाले लेखक उदय प्रकाश गुरुवार से फिर चर्चा में हैं। गुरुवार को उन्होंने आज की दान-दक्षिणा (अपने विचार, अपनी जगह पर सलामत) लिखकर राम मंदिर निर्माण के लिए चंदे की रसीद फेसबुक पर पोस्ट की। इसके बाद क्या था, की-बोर्ड क्रांतिकारियों की फौज उन पर टूट पड़ी और देख ही देखते वह इंटरनेट मीडिया पर ट्रोल हो गए।

आइडी हैक किए जाने की आशंका और गाली-ताली के बीच उदय प्रकाश खुद सामने आए। उन्होंने दान को राजनीति के चश्मे से न देखने की अपील की। दैनिक जागरण से टेलीफोन पर हुई बातचीत में उन्होंने कहा कि मैं कोरोना के चलते मार्च से झारखंड में हूं। मेरे दान पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। वैसे तो ये बड़ा सीधा सा मामला है, सब अपनी आस्था से राम मंदिर के लिए चंदा दे रहे हैं। दरअसल, प्रख्यात शिक्षाविद, कवि और आलोचक उदय प्रकाश ने 2015 में साथी कन्नड़ साहित्यकार एमएम कलबुर्गी की हत्या के बाद अपना साहित्य अकादमी अवॉर्ड लौटा दिया था। उन्होंने कहा था कि देश में असहिष्णुता बढ़ी है। इसके बाद देश में तमाम साहित्यकारों, लेखकों और कवियों ने अवार्ड वापस किए थे।

कमेंट्स भी जोरदार ~ उनकी पोस्ट पर एक यूजर ने लिखा... जब वे समूह में पीछे पड़ते हैं तो अपने आपको बचाना मुश्किल होता है। एक यूजर ने उन्हें कोट करते हुए लिखा कि बड़े-बड़े नाम भी हकीकत में ऐसे ही छोटे निकलते हैं। पहले भी आप अपने विचारों का मुरब्बा बना चुके हैं। कोई हैरत नहीं आदरणीय। एक सज्जन कमेंट किया कि अभी न जाने कितने भ्रम और टूटेंगे, कितने नायकों से भरोसा उठेगा। एक यूजर ने लिखा कि यह आपके जीवन का अच्छा कार्य हो सकता है, आपको पता चल गया कि आप कितनी असहिष्णु बिरादरी के विचारों को आत्मसात किए हुए थे।

बिहार में जहरीली शराब पीने से 16 की मौत मामले में बर्खास्त पुलिसकर्मियों को राहत, मिलेगा पूरा वेतन

पटना । पटना हाईकोर्ट ने एक बार फिर शराबबंदी के दौरान जहरीली शराब से हुई मौत के चलते बर्खास्त हुए 10 पुलिसकर्मियों को बड़ी राहत दे दी है। हटाए गए पुलिसकर्मियों को बहाल करने का भी आदेश दिया है इस घटना को लेकर कुल 29 पुलिसकर्मी हटाए गए थे। पटना हाईकोर्ट ने बर्खास्तगी का आदेश किया रद- बताते चलें कि बिहार के गोपालगंज जिले के खजुरिया ग्राम में शराब पीने से 16 लोगों की जाने गई थी द्य कोर्ट ने गुरुवार को विभिन्न पदों पर रहे पुलिसकर्मियों के बर्खास्तगी के आदेश को रद्द कर दिया। न्यायाधीश आशुतोष कुमार ने इस मामले में दस पुलिसकर्मियों की बर्खास्तगी को रद्द करते हुए राहत दी। इन पुलिसकर्मियों में मिथिलेश्वर सिंह, नीतीश कुमार सिंह, मनीष कुमार, सुनील कुमार श्रीवास्तव, चंद्रिका राम, धीरज कुमार राय, राज भारत प्रसाद सिंह, मनोज कुमार सिंह, राकेश कुमार सिंह व नवल कुमार सिंह शामिल हैं।

हालांकि 10 पुलिसकर्मियों को राहत देने के पहले हाईकोर्ट ने पांच पुलिसकर्मियों को पहले ही राहत दे दी थी। इन पुलिसकर्मियों को डायरेक्टर जनरल सह इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने सेवा से बर्खास्त करने का आदेश दिया था। घटना विगत 16 अगस्त, 2016 की है, जब अवैध शराब पीने की वजह से 16 लोगों की मौत के बाद गोपालगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। अदालत ने इनकी सेवा को तत्काल बहाल करने का भी आदेश दिया है। आदेश में यह भी कहा गया है कि अवैध आदेश की वजह से सेवा से बाहर रहने की अवधि का पूरा वेतन और अन्य पारिश्रमिकों का भी हकदार याचिकाकर्ता होगा। अब नए आदेश से दस पुलिस कर्मियों को राहत मिल गई है। मामले में 16 लोगों की जान गई थी। घटना उस समय बिहार में चर्चा का विषय बन गई थी। इस घटना को लेकर कुल 29 पुलिसकर्मी हटाए गए थे।

वाहन चलाते समय बरतें सावधानी, थोड़ी सी लापरवाही हो सकती है जानलेवा

गया। जगजीवन महाविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों एवं एनसीसी के कैडेट ने सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत नुक्कड़ नाटक कर लोगों को जागरूक किया। स्वयंसेवकों व कैडेटों ने जगजीवन कॉलेज के मुख्य द्वार पर यह आयोजन किया। इस नाटक के जरिए बिना हेलमेट गाड़ी नहीं चलाने, नियंत्रित गति में वाहन परिचालन, सीट बेल?ट लगाने की अपील की गई। साथ ही लहरिया कट गाड़ी चलाने वाले, गलत दिशा में गाड़ी चलाने वाले का हश्र दिखाया गया। अलग-अलग भूमिकाओं में छात्र-छात्राओं ने सड़क सुरक्षा का संदेश दिया। महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉ. कुमार राजीव रंजन ने स्वयंसेवकों एवं कैडेट्स के नुक्कड़ नाटक की सराहना की। उन्होंने कहा कि लोगों को सबक लेना चाहिए। यातायात नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। हेलमेट हमारा सुरक्षा कवच है। गाड़ी चलाते वक्त हमें इसे अवश्य पहनना चाहिए। भले ही कुछ देर हो जाए लेकिन कभी भी तेज रफ्तार में गाड़ी नहीं चलाएं। सड़क पार करते समय सावधानी बरतें।

राष्ट्रीय सेवा योजना की कार्यक्रम पदाधिकारी डॉ. अनु रानी और एनसीसी के नोडल अधिकारी डॉ. सुनील कुमार के निर्देशानुसार सारी गतिविधियां की जा रही थी। इस मौके पर उन्होंने स्वयंसेवकों एवं कैडेट्स की हौसला अफजाई की। नुक्कड़ नाटक से संदेश को जन- जन तक पहुंचाने के लिए धन्यवाद दिया। कहा कि ऐसे आयोजन से लोग जागरूक होंगे। गलत तरीके से वाहन परिचालन का हश्र देखकर लोग यातायात नियमों के पालन के प्रति प्रेरित होंगे। इस नुक्कड़ नाटक का संचालन राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक मैक्स कुमार ने किया। इस टीम में माधुरी कुमारी, धीरज कुमारी, प्रेरणा कुमारी , लव कुश कुमार, सीनियर कैडेट् अब्दुल, विमलेंदु, राजन, चिकु , रवि, राहुल कुमार शामिल हुए। मौके पर एनसीसी और एनएसएस के दर्जनों कैडेट्स व स्वयंसेवक उपस्थित थे।

मुखिया के पुत्र को मारी गोली, एक सप्ताह पूर्व एक लाख की मांगी थी रंगदारी

भागलपुर। पंचायत चुनाव को लेकर पकरा की मुखिया कदम देवी के पुत्र कुमार गौरव को गोली मारकर घायल कर दिया गया। आनन-फानन उसे अनुमंडल अस्पताल नवगछिया पहुंचाया गया। चिकित्सकों ने भागलपुर के लिए रेफर कर दिया, लेकिन विक्रमशिला सेतु जाम होने के कारण उसे इलाज के लिए पूर्णिया ले जाया गया। हालांकि वहां से भी बेहतर इलाज के लिए भागलपुर रेफर कर दिया गया। पुलिस इस मामले में बिलरिया के पुत्र को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। बताया जाता है कि गौरव भोजन करने के बाद हाथ धोने घर के पीछे गया था। हाथ धोकर वह जैसे ही पीछे मुड़ा कि पेड़ पर चढ़कर पहले से घात लगाए अपराधी ने गोली मार दी। घायल गौरव ने बताया कि कुख्यात राजकिशोर राय उर्फ बिलरिया उर्फ झोटहना ने उसे गोली मारी है। पंचायत में इस बार मुखिया पद पर वह खड़ा होने की बात कह रहा था। वह मुखिया के पद पर खड़ा होने से हम लोगों को मना कर रहा था। एक सप्ताह पूर्व ही उसने पांच लाख रुपये की रंगदारी की मांग की थी। मना करने पर गोली मार दी। घायल ने पुलिस को बिलरिया समेत दस लोगों के नाम बताए हैं। गोली गौरव की रीढ़ की हड्डी में फंसी हुई है। घटना के पश्चात नवगछिया अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने स्थल पर पहुंचकर घायल कर स्वजनों से जानकारी ली। इस संबंध में नवगछिया थानाध्यक्ष ने बताया कि अभी तक घायल का बयान नहीं दर्ज हुआ है। घायल के साथ पुलिस पदाधिकारी मौजूद हैं। बयान आने के बाद प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। घटना को लेकर मुखिया के घर के पास स्कूल में पुलिस कैंप कर रही है।

बिलरिया का है लंबा इतिहास– पुलिस के मुताबिक आरोपित बिलरिया का लंबा आपराधिक इतिहास हैं। पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के लिए 50 हजार रुपये का इनाम भी घोषित किया था। एसटीएफ की मदद से पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था। वह जमानत पर बाहर निकला हुआ है। तेतरी पंचायत के पूर्व मुखिया पुलकित ड्क्षसह के भाई की अपराधियों ने गोली मार कर हत्या कर दी थी, जिसमें बिलरिया भी नामजद आरोपित था।

योगी सरकार देगी विदेश में रोजगार पाने का मौका, यूपी के 50 हजार युवा लेंगे अमेरिका में ऑनलाइन फ्री ट्रेनिंग

लखनऊ । उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। इस बाबत उनके द्वारा शुरू कराए गए प्रयासों के नतीजे दिखने लगे हैं। व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग यूपी के युवाओं को विदेश में रोजगार हासिल करने के मौके मुहैया कराएगा। कौशल विकास विभाग ने युवाओं के लिए अमेरिका के अंतरराष्ट्रीय डिजिटल लर्निंग प्लेटफार्म कोर्सेरा के माध्यम से निशुल्क ट्रेनिंग कार्यक्रम शुरू किया है। इससे प्रदेश के युवा अंतरराष्ट्रीय मानकों पर ट्रेनिंग हासिल कर इंडस्ट्री के लायक बन सकेंगे। व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के अनुसार अब तक उत्तर प्रदेश के 50 हजार युवाओं को अमेरिका में स्थित डिजिटल लर्निंग प्लेटफार्म कोर्सेरा के जरिए प्रशिक्षण दिलाए जाने की व्यवस्था की है। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद इन युवाओं को कोर्सेरा की ओर

से सार्टिफिकेट भी उपलब्ध कराया जाएगा। विभाग के अनुसार ट्रेनिंग के बाद युवाओं को मिलने वाले सार्टिफिकेट की मान्यता विश्व के कई देशों में है। इससे देश के युवाओं को विदेश में जाकर नौकरी करने के अवसर प्राप्त होंगे।

आभा एप बनाएगी आत्मनिर्भर ~ युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ कर उनको आत्मनिर्भर बनाने की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुहिम प्रदेश में तेजी बढ़ती हुई नजर आ रही है। इस कड़ी में कौशल विकास विभाग की ओर से युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आभा एप को डेवलप किया गया है। इस से जुड़ कर युवा अपनी स्किल को डेवलप कर सकते हैं। एप में कई तरह के स्व रोजगार से जुड़े हुए विडियोज भी अपलोड किए गए हैं। जिनसे युवाओं को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम भी युवाओं को काफी भा रही है। इसमें उद्योगों में अप्रेंटिस के रूप में काम करने वाले युवाओं को एक हजार रुपये प्रतिमाह स्टाइपेंड दिया जा रहा है।

श्रमिकों को दे रहे हैं ट्रेनिंग ~ राज्यमंत्री व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास कपिल देव अग्रवाल के मुताबिक कोविड संक्रमण के दौरान प्रदेश में आए 38 लाख से अधिक श्रमिकों का भी कौशल विकास कार्यक्रम जारी है। इन श्रमिकों की आजीविका का प्रबंध कर उनको पैरों पर खड़ा करने का प्रयास कामयाब हो रहे हैं। श्रमिकों को रिकगनाइजेशन ऑफ प्रिरियर लर्निंग आरपीएल के तहत उनको ट्रेनिंग दिए जाने का काम तेजी से चल रहा है।

उत्तर प्रदेश में कुपोषण से ग्रसित 15 जिले चिन्हित, अब इन परिवारों का बेस लाइन सर्वे करेगा लविवि

लखनऊ । लखनऊ विश्वविद्यालय कुपोषण की समस्या से ग्रसित महिलाओं और बच्चों पर बेस लाइन सर्वे करेगा। इसके लिए नीति आयोग ने विश्वविद्यालय के सांख्यिकी विभाग को सेंटर आफ एक्सीलेंस के तहत यह प्रोजेक्ट दिया है। सर्वे में सहयोग के लिए विभाग और नागपुर की संस्था राम भाऊ महाल्गी प्रबोधिनी के साथ बीते दिनों एमओयू हो चुका है। अब विभाग ने प्रदेश के 15 जिलों में हाउस होल्ड मैपिंग और सूची बनाने का काम शुरू कर दिया है। इसमें प्रोजेक्ट फेलो और रिसर्च स्कालर सहयोग करेंगे।

दरअसल, नेशनल फैमिली हेल्थ के पांचवे सर्वे में भारत में कुपोषण से ग्रसित 100 जिले चिन्हित किए हैं, इनमें 15 जिले उत्तर प्रदेश के हैं। प्रोजेक्ट कोआर्डिनेटर एवं सांख्यिकी विभाग की प्रो. शीला मिश्रा ने बताया कि नीति आयोग के माध्यम से चलाए जा रहे पोषण जन अभियान के लिए बेस लाइन सर्वे कराया जाएगा। महिलाओं, किशोरियों और बच्चों का देखेंगे खानपान~ उन्होंने बताया कि रैंडम बेस लाइन सर्वे से पहले हाउस होल्ड मैपिंग की जा रही है। उसके बाद विभाग एनजीओ के माध्यम से 15 जिले के एक ब्लाक के तीन ग्राम पंचायतों में रैंडम सर्वे करेगा। यहां 15 से 50 आयु वर्ग महिलाओं, छोटे बच्चों और स्तर पान कराने वाली महिलाओं की पोषण की स्थिति का आंकलन किया जाएगा। उनके खान-पान, सैनेटाइजन की आदत, पानी, स्वच्छता से लेकर परिवार की आय सहित कई चीजें देखी जाएंगी। छह महीने तक बेस लाइन सर्वे चलेगा। उसके बाद इसकी रिपोर्ट नीति आयोग को भेजी जाएगी।

18 मार्च को जारी होगी पंचायत चुनाव की अधिसूचना, चारों पदों के लिए एक साथ वोटिंग

लखनऊ । उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने भले ही हाई कोर्ट से 60 दिन की मोहलत मांगी थी, लेकिन वर्ष 2000 में आयोग मात्र 37 दिनों में चुनाव की प्रक्रिया पूरी करने का रिकॉर्ड बना चुका है। जल्द चुनाव कराने को लेकर हाई कोर्ट के रुख को देखते हुए आयोग अब 42 से 45 दिनों में ही चुनाव कराने की तैयारी में जुट गया है। 30 अप्रैल, 2021 तक प्रक्रिया पूरी करने के लिए आयोग 18 मार्च को पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी कर सकता है। बशर्ते राज्य सरकार पदों के आरक्षण की अधिसूचना समय से जारी कर दे।

वैसे तो उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव पिछले वर्ष 25 दिसंबर से पहले ही हो जाने चाहिए थे, लेकिन कोरोना के कारण टले चुनाव अब ज्यादा टलते नहीं दिखाई दे रहे हैं। गुरुवार को हाई कोर्ट के संबंधित फैसले से साफ है कि अब चुनाव को लेकर किसी तरह की टालमटोल नहीं हो सकती है। अब आयोग को चूंकि 30 अप्रैल तक चुनाव की प्रक्रिया पूरी ही करनी है, इसलिए वह 60 दिन के बजाय 42 से 45 दिनों में चुनाव कराने का कार्यक्रम बनाने की दिशा में काम करने लगा है।

उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव पर हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान मौजूद रहे राज्य निर्वाचन आयोग के अपर निर्वाचन आयुक्त वेद प्रकाश वर्मा ने कोर्ट के फैसले पर कहा कि आयोग, हाई कोर्ट द्वारा तय समय-सीमा में चुनाव कराने को पूरी तरह से तैयार

है। चुनाव कराने के लिए हमारी मतदाता सूची प्रकाशित हो चुकी है। 52.50 करोड़ मतपत्र व 90 हजार मतपेटियां जिलों में भेजी जा चुकी हैं। अमिट स्याही का आर्डर भी हो चुका है।

राज्य निर्वाचन आयोग वर्ष 2000 में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 37 दिनों में ही करा चुका है। वर्ष 2005 में दो राउंड में चुनाव कराए गए थे। पहला राउंड 41 दिन व दूसरा 33 दिनों का रहा था। इसी तरह वर्ष 2010 में 45 दिनों के एक ही राउंड में पूरी चुनाव प्रक्रिया पूरी की गई थी। वर्ष 2015 में दो राउंड में हुए चुनाव में पहला राउंड 42 दिनों का व दूसरा 37 दिनों का रहा था।

चूंकि इस बार पूरी चुनाव प्रक्रिया 45 दिनों के अंदर ही पूरी की जानी है, इसलिए आयोग चारों पदों के लिए एक साथ चार चरणों में चुनाव कराने की तैयारी में जुटा है। यानी प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य व जिला पंचायत सदस्य के लिए एक साथ वोट डाले जाएंगे। सुरक्षा व्यवस्था व कर्मियों की संख्या को देखते हुए बस तय यह किया जाना है कि किसी भी चरण में एक ही जिले को चार चरणों में बांटकर एक हिस्से के सभी पदों का चुनाव कराया जाए या फिर हर एक चरण में 18 मंडलों के एक चौथाई जिलों के सभी पदों के चुनाव कराए जाएं।

बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव मई 2021 तक कराने की चुनाव आयोग की मांग अस्वीकार कर दी है। सख्त रुख अपनाते हुए कोर्ट ने आयोग को 30 अप्रैल तक पंचायत चुनाव कराने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को 17 मार्च तक सीटों का आरक्षण पूरा करने का भी आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति एमएन भंडारी व न्यायमूर्ति आरआर अग्रवाल की खंडपीठ ने विनोद उपाध्याय की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है।

यूपी विधान परिषद के नवनिर्वाचित सदस्यों ने ली पद एवं गोपनीयता की शपथ, नहीं पहुंचे सपा के राजेन्द्र चौधरी

लखनऊ । उत्तर प्रदेश विधान परिषद में नवनिर्वाचित सदस्यों ने शुक्रवार को पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। विधान परिषद के नवनिर्वाचित सदस्यों को कार्यकारी सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह ने विधान भवन के तिलक हॉल में उच्च सदन की सदस्यता की शपथ दिलाई। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के सभी दस सदस्यों ने शपथ ली, लेकिन समाजवादी पार्टी के सदस्य राजेन्द्र चौधरी शपथ लेने नहीं पहुंचे। हाल ही में विधान परिषद में 12 सदस्य नवनिर्वाचित हुए हैं, जिनमें कुंवर मानवेंद्र सिंह समेत भाजपा के 10 और सपा के दो सदस्य शामिल हैं।

उत्तर प्रदेश विधान परिषद के नवनिर्वाचित सदस्यों में भाजपा की तरफ से सबसे पहले उप मुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, लक्ष्मण आचार्य, महामंत्री गोविन्द नारायण शुक्ला, अश्विनी त्यागी, सुरेंद्र चौधरी, धर्मवीर प्रजापति, अरविंद कुमार शर्मा ने शुक्रवार को पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। इस दौरान सपा के सदस्य व राष्ट्रीय प्रवक्ता राजेन्द्र चौधरी के अलावा भाजपा के सलिल विश्नोई शपथ लेने नहीं पहुंचे। हालांकि बाद में भाजपा के सलिल विश्नोई को सभापति कक्ष में शपथ दिलाई गई।

उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कुंवर मानवेंद्र सिंह दूसरी बार प्रोटेम सभापति नियुक्त हुए हैं। इससे पहले वह छह मई, 2002 से दो अगस्त 2004 तक प्रोटेम सभापति रह चुके हैं। प्रोटेम सभापति के तौर पर उन्होंने विधान परिषद के नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। इसकी शुरुआत उन्होंने सपा के नवनिर्वाचित सदस्य अहमद हसन को रविवार को ही अपने कार्यालय कक्ष में शपथ दिलाकर की थी। अहमद हसन को विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष भी नियुक्त कर दिया गया है।

उत्तर प्रदेश की 100 सदस्यीय विधान परिषद में मौजूदा संख्या बल 98 है, जिसमें सपा के 51 सदस्य हो गए हैं। सदस्यों की संख्या के आधार पर सपा का ही बहुमत है। ऐसे में सपा अहमद हसन के लिए सभापति पद की दावेदारी करना चाह रही थी, लेकिन राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने भाजपा के कुंवर मानवेंद्र सिंह को विधान परिषद का प्रोटेम सभापति नियुक्त कर दिया। विधान परिषद में बहुमत वाली सपा ने कुंवर मानवेंद्र सिंह को प्रोटेम सभापति नियुक्त किये जाने पर एतराज जताया है। 18 फरवरी से शुरू होने वाले विधानमंडल के बजट सत्र में इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तकरार होना तय है।

सीपीआई नेता कन्हैया के खिलाफ हुई उनकी ही पार्टी, बिहार की घटना को ले हैदराबाद में पारित किया निंदा प्रस्ताव

पटना । भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी भाकपा के युवा नेता और जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार आजकल बिहार के सियासी गलियारे में कम नजर आते हैं। बिहार की सियासी गर्माहट से उनका नदारद रहना कई लोगों को खलता भी है। इस बीच वे चर्चा में हैं अपनी ही पार्टी के नेता के साथ मारपीट और बदसलूकी को लेकर। यह मारपीट पटना में करीब दो महीने पहले ही हुई थी, लेकिन अब उनकी अपनी ही पार्टी ने इस मामले को लेकर कन्हैया कुमार के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया है। वह लोकसभा चुनाव में बीजेपी के फायर ब्रांड लीडर गिरिराज सिंह के खिलाफ बेगूसराय से चुनाव लड़कर हार गए थे। वह फिलहाल पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य हैं।

दिसंबर का ही बताया जा रहा है मामला- यह मामला दिसंबर का ही बताया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार दिसंबर में ही पार्टी की ओर से बेगूसराय जिला काउंसिल की बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में कन्हैया को भी आना था। यह बैठक अचानक रद कर दी गई, लेकिन इसकी सूचना कन्हैया कुमार को समय रहते नहीं दी गई। इसी मुद्दे को लेकर पार्टी के कार्यालय सचिव इंदूभूषण की पिटाई कर दी गई। कहा यह जा रहा है कि यह मारपीट कन्हैया कुमार के समर्थकों ने की थी। इस दौरान कन्हैया के भी वहां रहने की बातें चर्चा में रही थीं, हालांकि उन्होंने खुद इस तरह की किसी गतिविधि का हिस्सा होने से इनकार किया था।

हैदराबाद में पारित किया गया निंदा प्रस्ताव– कुछ दिनों पहले सीपीआई की हैदराबाद में आयोजित तीन दिवसीय बैठक में कन्हैया के इस व्यवहार की आलोचना की गई और इसके खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। इस बैठक में पार्टी के कई बड़े नेता शामिल थे। पार्टी नेताओं ने कन्हैया से उनके व्यवहार में शालीनता बरतने की अपील की।

रालोद की महापंचायत में जुट रहे किसान, भारी पुलिस बल तैनात

शामली । उत्तर प्रदेश के शामली स्थित भैंसवाल गांव में आज रालोद ने किसानों की महापंचायत बुलाई गई है। इस दौरान प्रशासन ने भी भारी पुलिस बल तैनात किया है। मौके पर पुलिस के आलाधिकारी और फोर्स भी मौजूद है। वहीं किसानों का पंचायत में आना जारी हो गया है। कुछ किसान रास्ते में हैं तो कुछ पंचायत स्थल पर पहुंच चुके हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि कुछ ही देर में पंचायत शुरू हो जाएगी। अभी मंच पर नेता नहीं पहुंचे हैं।

हालाकि कुछ स्थानीय नेताओं का पहुचना जारी है। किसानों की भी भीड़ जुटनी शुरू हो गई है। सुबह से ही पंचायत में किसानों का पहुंचना जारी हो गया है। हालांकि, काफी देर के इंतजार के बाद किसानों की टोली आनी शुरू हो गई थी। करीब 12.30 तक एक-दो किसान ही मैदान में नजर आ रहे थे। धीरे-धीरे सभी किसानों की भीड़ भी जुट गई है, अभी कुछ किसान रास्ते में हैं जो अपने साधन से पंचायत स्थल पर पहुंच रहे हैं।

इसी बीच में सुरक्षा बल भी भारी तादात में तैनात है। पीएससी के अलावा पुलिस अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं। राकेश टिकैत ने इस पंचायत को लेकर किनारा कर लिया है। उन्होंने कहा है कि इस पंचायत से उनका कोई लेना-देना नहीं है।

भारी फोर्स तैनात– प्रशासन और किसान के आमने सामने आने के बाद आखिरकार पंचायत होने की कवायद शुरू हो गई है। प्रशासन ने भी इसके मद्देनजर भारी फोर्स शहर और पंचायत स्थल पर तैनात कर दिए हैं। साथ ही आयोजकों से वार्ता भी की जा रही है। उधर, रास्ते में किसानों का पहुंचना जारी हो गया है। प्रशासन ने फोर्स के साथ पुलिस अधिकारी भी तैनात किए हैं।

अधिकारियों ने क्या बताया–

एडीएम अरविंद कुमार सिंह और एएसपी राजेश श्रीवास्तव के साथ वार्ता में रालोद नेताओं ने कहा कि पंचायत की तैयारियों को अंजाम दिया जा चुका है।

पंचायत पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार भैंसवाल गांव स्थित स्वामी कल्याण देव कन्या गुरुकुल भैंसवाल के मैदान में होगी। एसडीएम शामली संदीप कुमार औरव और सीओ थानाभवन अमित सक्सेना ने आयोजन स्थल का मुआयना किया।

प्रशासन और आयोजकों से हुई मुलाकात- वहीं, आयोजक भी गुरुवार शाम तक पंचायत की तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगे रहे। रालोद के जिलाध्यक्ष योगेंद्र चेयरमैन ने बताया कि वह अन्य रालोद नेताओं के साथ पुलिस-प्रशासन से मिले थे। एसपी सुकीर्ति माधव ने बताया कि पंचायत को लेकर सुरक्षा और कानून-व्यवस्था के मद्देनजर पुलिस बल तैनात किया गया है। आयोजकों से लगातार वार्ता की जा रही है।

दुबई के सर्वर से चलता था पंजाब में पकड़े कैसिनो का नेटवर्क, 100 करोड़ पहुंचा लेनदेन का रिकार्ड

पटियाला । पंजाब के बनूड़ के एक होटल में गोवा की तर्ज पर चल रहे कैसिनो का सर्वर दुबई से आपरेट किया जाता था। आनलाइन जुड़ने वाले ग्राहकों के लिए आइडी व मास्टर पासवर्ड लाने के लिए गिरोह के कुछ सदस्य दुबई जाते थे। आरोपित दीपक कुमार अपने साथियों के साथ दुबई जाकर यह सब कुछ लाता था, जिसके बाद आइडी और मास्टर पासवर्ड ग्राहकों को अलाट कर दिए जाते थे।

सूत्रों के अनुसार आरोपितों से जारी पूछताछ के दौरान यह बात सामने आई है कि पिछले लंबे समय से यह गिरोह आनलाइन बेटिंग करवा रहा था, जिसके लिए हर दो महीने बाद ही होटल बदल देते थे। बनूड़ वाला होटल भी करीब दो महीने पहले ही किराये पर लिया गया था, जहां से यह लोग आनलाइन बेटिंग करवा रहे थे। जुए में शामिल होने वाले व्यक्ति के पास जान-पहचान का पुराना ग्राहक होना जरूरी था।

मंगलवार को हुई पूछताछ में पुलिस के पास से उक्त खुलासा हुआ है। आर्गेनाइज्ड क्राइम कंट्रोल यूनिट (ओकू) के एसपी जसकीरत सिंह मंगलवार को भी दिन भर गिरफ्तार आरोपितों से पूछताछ करते रहे और पूछताछ देर रात तक जारी रही। पकड़ी गई लड़कियां पंजाब, नगालैंड व नेपाल की हैं। जिनकी उम्र 18 से 25 वर्ष के बीच है। इन लड़कियों को सप्लाई करने वाले की तलाश में पुलिस की टीम छापामारी कर रही है।

बनूड़ होटल में कैसीनो का यह खेल करीब दो महीने से चल रहा था जबकि इससे पहले भी अन्य जगह पर यह कैसिनों चलता रहा है। पुलिस टीम को मौके पर बरामद रजिस्टर से चेक करने पर रोजाना डेढ़ से दो करोड़ रुपये तक के लेनदेन का रिकार्ड मिला है। अभी तक पुलिस जांच में करीब एक अरब के लेनदेन होने की आशंका जताई जा रही है।

न्यूटिमा अस्पताल के एक डॉक्टर और उसके साथियों पर सामूहिक दुष्कर्म का आरोप, शिकायत के बावजूद नहीं हो रही कार्रवाई

मेरठ । बच्ची का इलाज कराने आई महिला से न्यूटिमा अस्पताल के नर्सरी इंचार्ज और उसके दो साथियों ने दुष्कर्म किया। आरोप है कि शिकायत के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। शुक्रवार को पीड़िता ने एसएसपी कार्यालय पर शिकायत की।

यह है मामला– एसपी क्राइम ने सीओ और थाना पुलिस को मौके पर बुलाकर जांच का आदेश दिया। मोदीनगर निवासी पीड़िता ने बताया कि उसकी चार साल की बेटी को हर्निया है। गत 31 जनवरी को वह गढ़ रोड स्थित न्यूटीमा हॉस्पिटल आई थी। उसकी मुलाकात नर्सरी इंचार्ज से हुई। आरोप है कि नर्सरी इंचार्ज ने अपनी गाड़ी में बैठा कर कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया। जब उसे होश आया तो वह एक घर में थी। मौके पर आरोपित समस्त उसके दो और साथ ही थे।

आरोप है तीनों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। उसने चौकी पुलिस से शिकायत की लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। आरोप है उसे धमकी दी जा रही थी। वह किसी तरह शुक्रवार को एसएससी कार्यालय पहुंची।

एक नजर

विधानसभा चुनाव से पहले केरल में बीजेपी को झटका, एनडीए से अलग होकर बीडीजेएस ने बनाई नई पार्टी

कोच्चि । विधानसभा से पहले केरल में भारतीय जनता पार्टी को झटका लगा है। भारत धर्म जन सेना पार्टी, जो कि केरल में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का हिस्सा थी, ने गठबंधन से नाता तोड़ लिया और यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट में शामिल होने का फैसला करते हुए एक नई पार्टी बनाने की घोषणा की है। केरल विधानसभा चुनावों से पहले नए गुट ने एमके नीलकंदन मास्टर के नेतृत्व में एक नई राजनीतिक पार्टी, भारतीय जन सेना की घोषणा की है। बीजेएस के कार्यकारी अध्यक्ष वी गोपाकुमार ने आरोप लगाया कि बीडीजेएस का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) राजनीतिक ÷टूल÷ के रूप में कर रही है। गोपकुमार ने कहा, हम एक मिनट के लिए भी एनडीए में नहीं रख सकते हैं क्योंकि हम इस साजिश से नाखुश हैं। बीजेएस यूडीएफ पर पूरी तरह से भरोसा करके काम करेगा। लगभग 12 सामुदायिक संगठनों ने हमारे समर्थन की घोषणा की है। बीडीजेएस भाजपा के लिए एक उपकरण के अलावा कुछ भी नहीं है। वे एक ऐसे संगठन में नहीं रह सकते हैं जो राज्य में राजनीतिक रूप से अप्रासंगिक हो गया है। इसके परिणामस्वरूप नई पार्टी का गठन किया गया है। गोपीकुमार ने आगे आरोप लगाया कि बीजेपी सीपीआईएम के साथ संबंध बनाने के लिए फिर से सत्ता में आने के लिए हिंदू भक्तों को धोखा दे रही है। हमें भरोसा है कि यूडीएफ सत्ता में आने पर सबरीमाला मुद्दे पर अध्यादेश लाएगी। उन्होंने कहा कि एमके नीलकंदन मास्टर बीजेएस, नई पार्टी के अध्यक्ष होंगे।

राजस्थान सरकार ने शर्तों के साथ खाटूश्याम जी मेले के आयोजन की अनुमति दी

जयपुर । राजस्थान के सीकर जिले में स्थित खाटूश्यामजी मंदिर में फाल्गुनी लक्खी मेले के आयोजन को राजस्थान सरकार ने मंजूरी दे दी है। इससे पहले कोरोना महामारी के चलते मेले पर रोक लगाई गई थी। लेकिन देशभर से श्रद्धालुओं ने राज्य सरकार से विभिन्न माध्यमों के जरिए मेले का आयोजन करने का अनुरोध किया। इसके बाद सरकार ने मेले के आयोजन की अनुमति दे दी है। मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को पहले ऑन लाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा। एक मोबाइल नंबर से एक ही श्रद्धालु का रजिस्ट्रेशन होगा। हमेशा की तरह इस बार मेले में भंडारे की अनुमति नहीं होगी। प्रसाद का वितरण भी नहीं होगा। प्रतिवर्ष मेले के दौरान लगने वाली अस्थायी दुकानें भी नहीं लगाई जाएगी। धर्मशालाओं व होटलों में क्षमता के 50 फीसदी ही लोग ठहर सकेंगे। मंदिर में प्रसाद व माला चढ़ाने की अनुमति नहीं होगी। सीकर जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी ने बताया कि मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को अपनी कोरोना जांच रिपोर्ट दिखानी होगी। ये रिपोर्ट श्रद्धालु अपने मोबाइल पर अथवा हार्ड कॉपी में दिखा सकेंगे। मेला इस माह के अंत से शुरू होगा। उल्लेखनीय है कि इससे पहले कोविड-19 की गाइडलाइन के कारण जिला प्रशासन और मंदिर कमेटी ने इस साल मेले का आयोजन नहीं करने का निर्णय लिया था। लेकिन देशभर से श्रद्धालुओं ने सीकर जिला प्रशासन, राज्य सरकार व जनप्रतिनिधियों से मेले का आयोजन करने को लेकर आग्रह किया था। इस कारण सरकार ने कुछ शर्तों के साथ मेले के आयोजन की अनुमति दे दी है। मेले में प्रदेश के विभिन्न जिलों के साथ ही कलकत्ता, दिल्ली, असम सहित देश के विभिन्न हिस्सों से श्रद्धालु खाटूश्यामजी दर्शन करने के लिए आते हैं।

राजभवन की ओर बढ़ रहे दिव्यांगों को पुलिस ने बख्शी नगर में रोका, डिसेबिल्टी एक्ट 2016 लागू करने की कर रहे मांग

जम्मू । जम्मू-कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बावजूद यहां डिसेबिल्टी एक्ट 2016 लागू न किए जाने से हताश दिव्यांग शुक्रवार को जब राजभवन की ओर बढ़ने लगे तो पुलिस ने उन्हें बख्शी नगर में रोक लिया। जेएंडके हैंडीकैप्ड एसोसिएशन व जेएंडके हैडीकैप्ड वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले ये दिव्यांग मंगलवार से बख्शी नगर क्रासिंग के निकट क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठे है और आज अपनी मांग को उपराज्यपाल तक पहुंचाने के लिए इन दिव्यांगों ने बख्शी नगर से रैली निकाली और राजभवन की ओर कूच किया लेकिन पुलिस ने उन्हें वहां से आगे नहीं जाने दिया। इन दिव्यांगों का कहना है कि कानून के तहत उन्हें सरकारी नौकरियों में आरक्षण न दिए जाने समेत अन्य लाभों से भी वंचित रखा जा रहा है। जेएंडके हैंडीकैप्ड एसोसिएशन के वरिष्ठ उप-प्रधान अब्दुल रशीद भट्ट के अनुसार वे पिछले कई सालों से अपनी जायज मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं लेकिन आज तक उनकी आवाज किसी ने नहीं सुनी। भट्ट ने कहा कि पहले जम्मू-कश्मीर के अलग संविधान के चलते उनकी अनदेखी होती रही लेकिन अब जम्मू-कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बने हुए भी एक साल से अधिक का समय हो गया। इस एक साल में उन्होंने जम्मू-कश्मीर में डिसेबिल्टी एक्ट 2016 को लागू करते हुए उन्हें संविधान के तहत मिले अधिकार दिए जाने की मांग को लेकर जगह-जगह गुहार लगाई। भट्ट ने कहा कि वे अपनी मांग को लेकर उपराज्यपाल से भी मिले लेकिन इसके बावजूद सरकार की ओर से जम्मू-कश्मीर में डिसेबिल्टी एक्ट 2016 लागू करने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया, इससे विवश होकर उन्हें भूख हड़ताल शुरू करनी पड़ी। आज वो अपनी मांग को लेकर उपराज्यपाल के पास जाना चाहते थे लेकिन पुलिस ने उन्हें जबरन रोक लिया। भट्ट ने कहा कि जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा, उनका आंदोलन जारी रहेगा।

कृषि कानून के खिलाफ आन्दोलन को ओडिशा नव निर्माण कृषक संगठन का समर्थन, दोपहर 12 से 3 बजे तक चक्का जाम

भुवनेश्वर । कृषि कानून के खिलाफ चल रहे आन्दोलन को ओडिशा में समर्थन करते हुए नव निर्माण कृषक संगठन ने शनिवार को प्रदेश में चक्का जाम करने का आह्वान किया है। नव निर्माण किसान संगठन की तरफ से शनिवार को दोपहर 12 बजे से अपराह्न 3 बजे तक राज्य के 22 से 23 जिले में शांतिपूर्ण ढंग से आन्दोलन करने की जानकारी दी गई है। नव निर्माण कृषक संगठन के आवाहक अक्षय कुमार ने कहा है कि कृषि कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए जाने के साथ ही केन्द्र सरकार द्वारा किसानों पर किए जा रहे अत्याचार के बारे में लोगों को जानकारी दी जाएगी। यहां उल्लेखनीय है कि केन्द्र सरकार के तीन विवादित कृषि कानून के खिलाफ विभिन्न किसान संगठनों ने 6 फरवरी को देश भर में चक्का जाम करने का आह्वान किया है। हालांकि भारतीय किसान संघ (वीकेएस) 6 फरवरी को होने वाले चक्का जाम आन्दोलन में शामिल नहीं होगा। किसान आंदोलनकारी अपनी मांगों को लेकर 6 फरवरी को देशव्यापी चक्का जाम की तैयारी कर रहे हैं, वहीं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत का कहना है कि राजधानी दिल्ली में चक्का जाम नहीं होगा। जो लोग दिल्ली के बॉर्डर पर नहीं आ पाये हैं वे लोग अपने-अपने स्थानों पर ही 6 फरवरी को किसानों के समर्थन में शांतिपूर्वक चक्का जाम करेंगे। प्रदर्शनकारियों के चक्का जाम की घोषणा को ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस ने गाजीपुर बॉर्डर पर सुरक्षा इंतजाम बढ़ा दिए हैं। बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा ने घोषणा की है कि 6 फरवरी को दोपहर 12 से तीन बजे तक नेशनल और स्टेट हाईवे जाम रहेंगे, साथ ही 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में हुए ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा के बाद किसानों पर दर्ज मामलों और गिरफ्तारी का भी विरोध किया जाएगा।

पेड़ से टकराई इनोवा कार, एसबीआइ मैनेजर समेत दो की दर्दनाक मौत, दो की हालत गम्भीर

भुवनेश्वर । ओडिशा के बलांगीर जिले में शुक्रवार सुबह हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में दो लोगों की मौत हो गई और दो अन्य लोग गम्भीर रूप से घायल हो गए हैं। बलांगीर जिले के टिटिलागढ़ के सागरपाली चौराहे पर यह दुर्घटना हुई है। मृतक दो लोगों में से एक डाबुगां एसबीआइ ब्रांच मैनेजर राकेश हेम्ब्रम हैं जबकि अन्य एक इनोवा कार के मालिक सत्यजीत मादला हैं। मृतक सत्यजीत के पिता रामेश्वर मादला तथा ड्राइवर भीम हरिजन भी इस हादसे में बुरी तरह से घायल हुए हैं। प्राप्त जानकारी के मुताबिक आज भोर 4 बजे के करीब यह हादसा हुआ है। इनोवा कार से ये सभी लोग नवरंगपुर से भुवनेश्वर की तरफ आ रहे थे। सागरपाली के पास गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया और गाड़ी पेड़ से टकरा गई। इनोवा कार की रफ्तार अधिक होने से जब गाड़ी पेड़ से टकराई तो कार के आगे का हिस्सा पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। हादसे में राकेश हेम्ब्रम एवं सत्यजीत मादला की घटना स्थल पर ही मौत हो गई है।

किसान आंदोलन के समर्थन में ग्रेटा थनबर्ग का ट्वीट भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा का हिस्सा, खालिस्तान समर्थक संगठन ने मुहैया कराए थे टूलकिट

नई दिल्ली । किसान आंदोलन की आड़ में भारत के खिलाफ विदेशी प्रोपेगेंडा की हकीकत अब सामने आने लगी है। एक जांच में खुलासा हुआ है कि कृषि कानूनों के खिलाफ भारत में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करने वालीं ग्रेटा थनबर्ग का ट्वीट खालिस्तानी संगठन के प्रोपेगंडा का हिस्सा था। दरअसल, ग्रेटा थनबर्ग ने एक ट्वीट किया था, जिसे उन्होंने बाद में डिलीट कर लिया। इसकी प्रारंभिक जांच में यह बात सामने निकलकर आयी है कि इसके पीछे कनाडा स्थित खालिस्तान का समर्थन करने वाले संगठन का हाथ है।

वरिष्ठ सरकारी सूत्रों ने कहा कि ग्रेटा थनबर्ग ने अपने ट्वीट में जो पावर प्वाइंट टूलकिट का इस्तेमाल किया था, जिसका उद्देश्य भारत के हितों को नुकसान पहुंचाना है, एक स्वघोषित खालिस्तान समर्थक धालीवाल द्वारा स्थापित पीस फॉर जस्टिस संगठन द्वारा तैयार किया गया था। यह कनाडा के वैंकूवर में स्थित है।

पॉवरपाइंट में भारत को निशाना बनाते हुए टास्क बांटे गए थे। टूलकिट में साममान रूप से भारत की योग और चाय की छवि को चोट पहुंचाने, 26 जनवरी को वैश्विक व्यवधान के साथ-साथ कृषि कानूनों को निरस्त करना मकसद था। थे। आपको बता दें कि थनबर्ग ने पोस्ट तो हटा दिया था, लेकिन इससे पहले भारत में कई लोगों ने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया, जो देखते ही देखते वायरल हो गया।

एक रिपोर्ट के मुताबिक, एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ÷ग्रेटा द्वारा गलत तरीके से साझा किए गए दस्तावेज़ों से पता चलता है कि रिहाना और अन्य लोगों द्वारा किए गए ट्वीट भारत की छवि को खराब करने के लिए चलाए गए बड़े अभियान का हिस्सा था। इस तरह के सभी बयानों/ट्वीट्स को भारत और विदेश में महत्वपूर्ण लोगों द्वारा देखना महत्वपूर्ण है।

केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने एक फेसबुक पोस्ट में दावा किया, थनबर्ग के हटाए गए ट्वीट से भारत के खिलाफ एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक साजिश के असली डिजाइन का पता चला है। उन दलों की जांच करने की आवश्यकता है जो इस बुरी मशीनरी के तार खींच रहे हैं। सिंह ने कहा कि निर्देशों को स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया था।

कैसे, कब और क्या इसकी पूरी जानकारी दी गई थी। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा, ÷किसानों के विरोध के समर्थन में थनबर्ग ने जो टूलकिट ट्वीट किया, वह वास्तव में अराजकता का एक स्कूल था। उनका (विदेशी व्यक्तित्वों) का इन कानूनों से कोई लेना-देना नहीं है, वे सिर्फ देश में अराजकता और परेशानी की स्थिति पैदा करना चाहते हैं।

हॉस्पिटल केयर टेकर के पदों पर सीधी भर्ती का रास्ता खुलेगा, सीएम ने दी प्रस्ताव को मंजूरी

जयपुर । राजस्थान सरकार प्रदेश के अस्पतालों में 'हॉस्पिटल केयर टेकर' के पदों पर शीघ्र योग्य एवं दक्ष अभ्यर्थियों की सीधी भर्ती करेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसके लिए हॉस्पिटल केयर टेकर के पद की शैक्षणिक योग्यता में संशोधन के लिए मंत्रिमण्डलीय ज्ञापन के प्रारूप का अनुमोदन कर दिया है।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के प्रस्ताव के अनुसार, हॉस्पिटल केयर टेकर का पद राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम, 1965 में सम्मिलित है। इन सेवा नियमों में संशोधन कर हॉस्पिटल केयर टेकर के पद पर सीधी भर्ती के लिए योग्यता 'अस्पताल प्रबंधन अथवा अस्पताल प्रशासन अथवा हॉस्पिटल एण्ड हैल्थकेयर मैनेजमेन्ट में एमबीए अथवा दो वर्षीय पीजी डिप्लोमा' करने का प्रस्ताव है।

गौरतलब है कि वर्तमान में इस पद के लिए केवल पैरा मेडिकल अथवा नर्सिंग का प्रशिक्षण प्राप्त ?से कार्मिक योग्य हैं, जिन्होंने वर्ष 1987 से पहले एक वर्ष का कोर्स किया हो। उक्त योग्यताधारी अभ्यर्थी नहीं मिलने की स्थिति में हॉस्पिटल केयर टेकर के अधिकतर पद रिक्त चल रहे हैं। सीधी भर्ती के लिए योग्यता में संशोधन के बाद हॉस्पिटल केयर टेकर के पदों पर योग्य एवं दक्ष अभ्यर्थियों की शीघ्र भर्ती का मार्ग प्रशस्त होगा।

भर्ती का हो रहा इंतजार

बता दें कि इस भर्ती का युवा लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। कोरोना महामारी के दौरान हॉस्पिटल केयरटेकर की अस्पतालों में काफी कमी देखी गई। ऐसे में उम्मीद थी कि जल्द ही यह भर्ती परीक्षा होगी। सरकार ने अब इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। माना जा रहा है कि जल्द ही इस भर्ती के लिये विज्ञप्ति जारी कर दी जाएगी। विज्ञप्ति जारी होने के बाद भर्ती परीक्षा होगी और उसके बाद इस साल के अंत तक ही नियुक्ति दी जा सकती है।

वीवीआईपी उड़ानों के लिए केंद्र पर एयर इंडिया का लगभग 500 करोड़ रुपये बकाया

नई दिल्ली । विभिन्न सरकारी विभागों पर एयर इंडिया लिमिटेड का लगभग 500 करोड़ का भुगतान बकाया है, जबकि एयर लाइन पहले ही आर्थिक रूप से संघर्ष कर रही है। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बुधवार को राज्यसभा को बताया कि 31 दिसंबर, 2020 तक एयरलाइन का 'वीवीआईपी ऑपरेशन्स' के लिए बकाये सहित विभिन्न सरकारी विभागों पर विमान किराये के रूप में, 498.17 करोड़ रुपये का बकाया शामिल है।

पुरी ने कहा, ÷आमतौर पर भारत सरकार के विभागों की क्रेडिट अवधि चालान की प्राप्ति से 15 से 30 दिनों तक होती है और क्रेडिट अवधि के भीतर भुगतान न करने की स्थिति में एयर इंडिया को कोई ब्याज नहीं दिया जाता है÷

एयर इंडिया ने घरेलू ऋणदाताओं से पहले ऋण को पूरा करने के लिए अल्पकालिक ऋण सुविधा के माध्यम से 225 करोड़ उधार लिया है। वित्तवर्ष 2019-20 अनंतिम आंकड़ों के अनुसार, एयर इंडिया का कुल कर्ज 38,366.39 करोड़ रुपये था। पुरी ने कहा, ''उपरोक्त राशि वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान एयर इंडिया एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड के विशेष ऋण वाहन (एसपीवी) के लिए 22,064 करोड़ रुपये के ऋण हस्तांतरण के बाद है।'' 31 मार्च, 2020 तक, एयर इंडिया की कुल शुद्ध अचल संपत्ति 45,863.27 करोड़ थी, जिसमें भूमि और भवन, विमान बेड़े और इंजन, अन्य अचल संपत्तियां, सही उपयोग की संपत्ति और अमूर्त संपत्ति शामिल थीं

अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता कोलकाता में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सम्मेलन के दौरान ।

कोरोना की रफ्तार हुई धीमी, बीते 24 घंटों में 15 हजार से ज्यादा लोग हुए ठीक

नई दिल्ली । भारत में कोरोना के खिलाफ दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चल रहा है। देश टीकाकरण शुरू होने से राहत महसूस कर रहा है। लेकिन, वायरस का खतरा अभी तक टला नहीं है। पिछले 24 घंटों में देशभर में कोरोना के 12,408 नए मामले सामने आए हैं, जिससे देश में कोरोना के कुल आंकड़े 1,08,02,591 तक पहुंच गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में कोरोना से 120 लोगों की मौत हो गई है जिससे देश मो कोरोना का डेथ टॉल 1,54,823 पहुंच गया है। एक ओर जहां 1,04,80,455 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं वहीं 1,51,460 लोग अब भी कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं। बीते 24 घंटों मे 15,853 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। भारत कोरोना के खिलाफ डट कर लड़ाई लड़ रहा है, पहले चरण में हेल्थ वर्कर्स को टीका लगाया गया है और दूसरे चरण में फंट लाइन् वॉरियर्स को वैक्सीन लगाई जा रही है। 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को टीका लगाने की तैयारी भी चल रही है, स्वास्थ्य मंत्रालय के दिए आंकड़ो के मुताबिक अब तक देशभर में 49,59,445 लोगों को टीका लगाया जा चुका है।

पपला गुर्जर ने गर्लफ्रेंड पर खर्च किए लाखों रुपये, पूछताछ में हुए कई खुलासे

जयपुर । राजस्थान के अलवर जिले के बहरोड़ थाने पर फायरिंग कर फरार हुए पपला गुर्जर ने फरारी के दौरान ना केवल खुद ऐश किए, बल्कि अपनी गर्लफ्रेंड जिया पर भी लाखों रुपए खर्च किए। रिमांड के दौरान पुलिस पूछताछ में पपला और जिया ने इस बारे में जानकारी दी। जानकारी के अनुसार हरियाणा से जिया के बैंक खाते में 13 लाख रुपए जमा करवाए गए। साथ ही पपला ने जिया को नई स्कूटी भी दिलाई। अब पुलिस पपला को रूपए पहुंचाने वालों की तलाश में जुटी है। साथ ही जिन लोगों ने फरारी के दौरान पपला गुर्जर की मदद की, उनकी भी पड़ताल की जा रही है।

जयपुर रेंज आइजी हवासिंह घुमरिया ने बताया कि वांटेड पपला की महिला मित्र जिया को सात दिन की पुलिस रिमांड के बाद कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। हरियाणा से कोल्हापुर में जिया के बैंक खाते में मोटी रकम किस-किसने डलवाई है, इस बात का भी पता किया जा रहा है।

पपला ने बताया पिता को ट्रांसपोर्टर

पूछताछ में जिया ने बताया कि वांटेड पपला ने उसे बताया था कि उसके पिता को ट्रांसपोर्ट का कारोबार है। पिता के पास कई ट्रक है। उसके पिता जरूरत होने पर रूपए देते रहते है। साथ ही कहा कि उसके पिता ने ही जिया के खाते में रुपए जमा करवाए है। जबकि पपला के पिता खेती करते है और इतने अमीर भी नहीं है। पपला का खुद के घर आना-जाना बहुत कम है।

अभी भी है प्रेम का खुमार

पुलिस सूत्रों की मानें तो पपला और जिया में अब भी प्रेम का खुमार है। दोनों अलग रहते हुए एक-दूसरे के बारे में पुलिसवालों से पूछताछ करते रहते है। गौरतलब है कि पपला और उसकी महिला मित्र को नीमराना थाने में रखा गया। साथ ही पूछताछ के दौरान कई और बातें सामने आई है। ऐसे में जल्द ही पुलिस बहरोड़ थाने में फायरिंग से जुड़े मामले में कुछ और खुलासे कर सकती है।

पॉक्सो कानून पर बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा महिला आयोग

नई दिल्ली । राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्लू) ने बॉम्बे हाई कोर्ट उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है जिसमें कहा गया था कि किसी नाबालिग लड़की के सीने पर कपड़ों के ऊपर से हाथ लगने को पोक्सो एक्ट के तहत यौन हमला नहीं माना जा सकता है। यौन हमले के लिए यौन मंशा से त्वचा से त्वचा का संपर्क होना जरूरी है। मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च अदालत की पीठ ने हाईकोर्ट के उक्त फैसले पर 27 जनवरी को रोक लगा दी थी।

अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने शीर्ष अदालत के समक्ष कहा था कि यह फैसला अभूतपूर्व है और इससे खतरनाक नजीर स्थापित होने की संभावना है। शीर्ष अदालत ने महाराष्ट्र सरकार को नोटिस भी जारी किया था और अटार्नी जनरल को इस फैसले के खिलाफ अपील दाखिल करने की अनुमति प्रदान की थी।

राष्ट्रीय महिला आयोग ने अपनी याचिका में कहा है कि अगर शारीरिक संपर्क की ऐसी विकृत व्याख्या की अनुमति दी गई तो इसका उन महिलाओं के बुनियादी अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा जो समाज में यौन अपराधों का शिकार होती हैं। साथ ही यह व्याख्या महिलाओं के हितों की रक्षा के मकसद से बनाए गए विभिन्न कानूनों के तहत निर्धारित लाभकारी विधिक सुरक्षा उपायों को कम करेगी।

आयोग का कहना है कि हाई कोर्ट के आदेश में की गई ऐसी संकीर्ण व्याख्या खतरनाक नजीर स्थापित करती है जो महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा पर गहरा प्रभाव डालेगी। बता दें कि वकीलों की एक संस्था यूथ बार एसोसिएशन आफ इंडिया पहले ही हाई कोर्ट के उक्त फैसले के खिलाफ याचिका दाखिल कर चुकी है। उल्लेखनीय है कि बॉम्बे हाई कोर्ट के उक्त फैसले पर सामाजिक कार्यकर्ता और बच्चों के अधिकारों से जुड़े संगठनों ने भी आपत्ति जताई थी और महाराष्ट्र सरकार से इसके खिलाफ अपील दाखिल करने का आग्रह किया था। यही नहीं राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने भी महाराष्ट्र सरकार से इस फैसले के खिलाफ तुरंत अपील दाखिल करने को कहा था।

फाइजर ने भारत में कोविड वैक्सीन के लिए आवेदन वापस लिया

नई दिल्ली । फाइजर ने भारत में अपने कोविड -19 वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग के लिए मांगे गए आवेदन को वापस लेने का फैसला किया है। फाइजर के प्रवक्ता ने कहा, अपने कोविड-19 वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग की मांग के अनुसरण में, फाइजर ने 3 फरवरी को ड्रग नियामक प्राधिकरण की विषय विशेषज्ञ समिति की बैठक में भाग लिया। बैठक में विचार-विमर्श और अतिरिक्त जानकारी जुटाने के बाद, कंपनी ने इस समय अपना आवेदन वापस लेने का फैसला किया है। प्रवक्ता ने कहा, फाइजर का प्राधिकरण के साथ संवाद जारी रहेगा और भविष्य में वैक्सीन उपलब्ध कराने को लेकर अनुमोदन अनुरोध को फिर से जारी किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि फाइजर, भारत में सरकार द्वारा उपयोग के लिए अपने वैक्सीन को उपलब्ध कराने और आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण के लिए अपेक्षित मार्ग का अनुसरण करने के लिए प्रतिबद्ध है।

ओडिशा को रेल परियोजनाओं के लिए बजट में मिले 6995.58 करोड़, चालू परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने पर जोर

भुवनेश्वर । ओडिशा राज्य में चल रही विभिन्न रेल परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए केन्द्र सरकार ने इस वर्ष के बजट में कुल 6995.58 करोड़ रुपये का आवंटन किया है। राशि के आवंटन में इस बात का ख्याल रखा गया है कि धन की कमी के कारण विकास कार्यों की गति प्रभावित न हो। यात्री सुविधा, रोड ओवर ब्रिज, रोड अंडर ब्रिज, सीमित उंचाई के उपमार्ग से संबंधित सड़क संरक्षा कार्य मदों में बजट राशि में उल्लेखनीय वृद्धि की गयी है। खुर्दा-बलांगीर रेल परियोजना के कार्य को और गति प्रदान करने के लिए इस वर्ष 1000.50 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। यह राशि गत वर्ष के 520 करोड़ के आवंटन से 92.4 प्रतिशत अधिक है।

दोहरीकरण परियोजनाओं विशेष रूप से बांसपानी-दैतारी-टमका-जखपुरा के लिए गत वर्ष के 80 करोड़ की तुलना में 228 करोड़ रुपये (185 प्रतिशत की वृद्धि) का आवंटन किया गया है। इसके साथ ही ब्रुंदामल-झारसुगुड़ा फ्लाईओवर के लिए 20 करोड़, भद्रक-निर्गुणडी तीसरी लाइन के लिए 229 करोड़, बुढ़ापंक-सालगांव के लिए 215 करोड़, राउरकेला-झारसुगुड़ा तीसरी लाइन के लिए 230 करोड़, नारायणगड़-भद्रक तीसरी लाइन के लिए 225 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।

ओडिशा राज्य में यात्री सुविधाओं से संबंधित कार्यों के लिए जहां गत वर्ष 129 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था, वहां इस वर्ष इस मद में 429 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। समपार फाटकों को समाप्त करने के लिए भी 400 करोड़ रुपये का आवंटन इस वर्ष किया गया है।

वर्ष 2021.22 में ओडिशा में आधारभूत संरचना व संरक्षा संबंधी कार्यों के लिए 5528 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। इसके अलावा कंप्यूटराइजेशन, रॉलिंग स्टॉक, लीज मद, विद्युतीकरण, यात्री सुविधा, कारखाने, कर्मचारी कल्याण आदि मदों में आवंटित की गयी राशि को शामिल करने पर ओडिशा की रेल परियोजनाओं के लिए बजट में कुल 6995.58 करोड़ रुपये का आवंटन हुआ है।

केंद्र के अपीलें दायर करने में देरी पर सुप्रीम कोर्ट सख्त

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की ओर से अपीलें दायर करने में देरी पर सख्त रुख अपनाया है। साथ ही कहा कि सरकार अपने सभी विभागों को इस संबंध में आदेश जारी करके अपना कामकाज दुरुस्त करे। अदालत ने कहा कि ऐसे कई मामलों में जुर्माना लगाने के बावजूद ऐसा लगता है कि बधिरों को कुछ भी कहना बेकार है।

दिल्ली हाई कोर्ट की ओर से पारित एक आदेश के खिलाफ अपील करने में 6616 दिनों की देरी पर सर्वोच्च अदालत ने कहा कि केंद्र ने आज जैसे विशेष अनुमति याचिका दायर की है जैसे पहले की सब याचिकाएं रद्दी की टोकरी में फेंक दी हों।

जस्टिस एसके कौल, दिनेश महेश्वरी और हृषिकेश की खंडपीठ ने कहा कि इतने दिशा-निर्देशों के बावजूद याचिका दायर करने में देरी करने वाले अधिकारियों से जुर्माना वसूलने के निर्देश के बावजूद लगता है कि इससे किसी को फर्क ही नहीं पड़ता है।

कोर्ट ने छह पन्ने के अपने आदेश में सरकार की ओर से देर से अपील दायर करने की आदत को सर्वोच्च अदालत से अंतिम निर्णय लेने की जुगत लगता है। ताकि उन्हें कोर्ट से एक सर्टीफिकेट मिल जाए कि अब इस मामले में कुछ नहीं हो सकता है। उनका मकसद सिर्फ खानापूरी करना होता है और गलती करने वाले अधिकारियों की खाल बचाना होता है।

यह वह अधिकारी हैं जो प्रक्रिया को पूरा करने में चूक जाते हैं या फिर जानबूझकर देरी करते हैं। इसलिए अदालत ने इस मामले में जिम्मेदार अधिकारी पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना चार हफ्ते में रिकार्ड वेलफेयर फंड में जमा कराने को कहा है।

श्वेता बच्चन को बिलकुल पसंद नहीं अपनी भाभी ऐश्वर्या राय की एक आदत, चैट शो में किया था खुलासा

सदी के महानायक अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की बेटी श्वेता बच्चन नंदा और उनकी भाभी ऐश्वर्या राय के बीच अच्छी बनती है. श्वेता अक्सर ऐश्वर्या के टैलेंट और मेहनत की प्रशंसा करती हैं, लेकिन एक बार ये भी कहा कि वो अपनी मिस वर्ल्ड रह चुकी भाभी ऐश्वर्या से नफरत करती हैं.

करण जौहर के चैट शो 'कॉफी विद करण' में जब श्वेता से पूछा गया कि वह ऐश्वर्या की किस आदत से प्यार और किस आदत से नफरत करती हैं. तो इस सवाल के जवाब में श्वेता ने कहा कि 'ऐश्वर्या अपनी मेहनत की बदौलत बॉलीवुड में अपनी जगह बनाने वाली हीरोइन होने के साथ साथ मजबूत महिला और शानदार मां हैं, लेकिन उनकी एक आदत मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है. उन्हें जब भी फोन करो वह कभी फोन नहीं उठाती और न ही फोन और मैसेज का कभी पलट कर जवाब देती है. इस आदत से मुझे बहुत नफरत है'.

शो के दौरान भाई अभिषेक बच्चने के बारे में पूछे जाने पर श्वेता ने कहा कि वह अपने परिवार को लेकर बहुत ही समर्पित हैं. एक अच्छे पति होने के साथ साथ एक अच्छे बेटे भी हैं. जब करण जौहर ने श्वेता से पूछा कि अभिषेक की किस बात को नापसंद करती हैं तो श्वेता ने कहा कि 'उसे लगता है वह सब कुछ जानता है, उसकी ये आदत मुझे बिल्कुल पसंद नहीं'. अमिताभ और जया की बेटी होने के बावजूद श्वेता बच्चन खुद को लाइमलाइट से दूर रखती हैं. जब श्वेता से ये पूछा गया कि उन्होंने फिल्मों में काम क्यों नहीं किया तो श्वेता ने साफगोई से बताया कि एक तो उन्हें कैमरा फेस करने से डर लगता है और दूसरा उन्हें न तो अपना चेहरा ही हीरोइन जैसा लगता है और न ही एक्टिंग करने का हुनर उनके अंदर हैं.

2021 श्रुति हासन(Shruti Haasan) के लिए काफी व्यस्त रहने वाला है. उन्होंने हाल में एक्शन थ्रिलर सालार (Salaar) की शूटिंग शुरू की है.

कंगना रनौत ने रिहाना की तस्वीरें शेयर कर लिखा, संघी नारी सबपे भारी... देख लो लेफ्ट विंग के रोल मॉडल

कंगना रनौत ने अमेरिकी पॉप सिंगर रिहाना पर तीखा हमला बोलते हुए लगातार कई ट्वीट किए हैं। कंगना रनौत ने अपनी और रिहाना की तस्वीरों के कोलाज शेयर करते हुए लिखा है, 'संघी नारी सबपे भारी बनाम लिब्रू रोल मॉडल्स। सभी भारतीय एकजुट हो जाओ और अपनी ताकत दिखाओ। इसके अलावा एक और ट्वीट में कंगना रनौत ने लिखा है, राइट विंग रोल मॉडल बनाम लेफ्ट विंग रोल मॉडल... । दरअसल रिहाना ने न्यूड शो किए थे, जिनकी तस्वीरों को शेयर करते हुए कंगना रनौत ने हमला होला है। एक तरफ कंगना रनौत ने अपनी उन तस्वीरों को शेयर किया है, जिनमें वह साड़ी और परंपरागत ड्रेस में नजर आ रही हैं, जबकि रिहाना अपने अंदाज में दिख रही हैं।

रिहाना के अलावा कंगना रनौत ने दिलजीत दोसांझ पर भी एक बार फिर हमला बोला है। इससे पहले मंगलवार को भी कंगना रनौत ने रिहाना के उस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए उन पर हमला बोला था, जिसमें उन्होंने किसान आंदोलन का समर्थन किया था। रिहाना ने किसान आंदोलन पर सीएनएन की एक न्यूज को शेयर करते हुए लिखा था, हम लोग इस पर बात क्यों नहीं कर रहे हैं।

रिहाना के इस ट्वीट के जवाब में कंगना रनौत ने लिखा था, कोई भी बात इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि ये किसान नहीं, आतंकवादी हैं। जो भारत को बांटना चाहते हैं ताकि चीन हमारे देश पर कब्जा कर ले और यूएसए जैसी चाइनीज कॉलोनी द्व हम तुम्हारे जैसे मूर्ख नहीं है जो अपने देश को बेच दें।

सपना चौधरी ने कराया पति वीर के नाम का टैटू, शेयर किया वीडियो

हरियाणवी क्वीन और देसी गर्ल सपना चौधरी ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह पति वीर के नाम का कलाई पर टैटू कराती नजर आ रही हैं। हाल ही में सपना चौधरी ने यह टैटू कराया है। वीडियो के जरिए वह इस टैटू को फ्लॉन्ट करती नजर आ रही हैं। फैन्स भी सपना चौधरी के इस नए टैटू को देखकर तारीफ कर रहे हैं।

बता दें कि मां बनने के बाद सपना चौधरी काफी सुर्खियों में रहीं। सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वालीं सपना चौधरी आजकल खुद की फोटोज और वीडियोज शेयर करती रहती हैं। इसके अलावा हाल ही में सपना चौधरी का नया गाना 'लोरी' रिलीज हुआ है। सपना चौधरी का यह गाना बच्चे के प्रति मां के प्यार और परवरिश पर आधारित है।

पिछले दिनों इंस्टाग्राम पर फैन्स के साथ लाइव जुड़ीं सपना चौधरी ने इस गाने की रिलीज के बारे में बताया था। इसके साथ ही उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल लॉन्च करने का ऐलान भी किया था। सपना चौधरी का कहना है कि यह गाना उन्होंने हरियाणवी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए लॉन्च किया है।गौरतलब है कि सपना चौधरी ने साल 2020 में जनवरी में ब्वॉयफ्रेंड वीर साहू संग सात फेरे लिए थे। इसके बाद अक्टूबर के महीने में वह बेबी ब्वॉय की मां बनी थीं। कुछ दिनों पहले सपना ने बेटे की फोटो भी शेयर की थी जो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी।

सपना चौधरी के पति वीर साहू हरियाणवी गाने लिखने के साथ एक्टिंग भी करते हैं। स्टेज परफॉर्मेंस के लिए हरियाणा सहित कई राज्यों में लोकप्रिय सपना चौधरी अक्सर अपनी फैमिली के साथ इंस्टाग्राम पर तस्वीरें शेयर करती रहती हैं।

अनन्या पांडे ने जताई ऑनलाइन ट्रोल्स और नफरत पर नाराजगी, बोलीं- बहुत कम उम्र में मैंने यह सब देखा

एक्ट्रेस अनन्या पांडे ने करण जौहर की फिल्म 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2' से फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा था। तभी से वह सोशल मीडिया सेंसेशन बनी हुई हैं। स्टार किड होने के बावजूद उन्होंने नेपोटिज्म का सामना किया है। ऑनलाइन ट्रोल्स और नफरत से भरे कॉमेंट्स को एक्सपीरियंस किया है। अनन्या पांडे की सोशल मीडिया पर काफी बार आलोचना भी हुई है। क्या आप जानते हैं कि ऑनलाइन ट्रोल्स और नफरत का शिकार वह बॉलीवुड डेब्यू के बाद नहीं, बल्कि कम उम्र से ही हो रही हैं?

पिंकविला से बात करते हुए अनन्या पांडे ने कहा, मुझे लगता है कि सोशल मीडिया पर मैं काफी छोटी उम्र में एक्सपोज हो गई। मेरी काफी सारी फोटोज सामने आ रही थीं, जिन पर मैंने लोगों के अंदर मेरे प्रति भड़ास और नफरत देखी। यह सिर्फ एक बार में ही मैंने नहीं देखा, समय के साथ देखा। मैं नफरत और नेगेटिविटी से घिरती जा रही थी। जब भी मैं खुद को ट्रोल होते देखती थी तो सोचती थी कि मेरे से ज्यादा मेरे पैरेंट्स दुखी होंगे, यह सब देखकर।

अनन्या पांडे कहती हैं कि मैं चीजों को इग्नोर करने में भरोसा करती हूं। हेटर्स को प्यार देने में विश्वास

रखती हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि इन चीजों की जरूरत सबसे ज्यादा उन्हें ही है। शायद वह एक ऐसी जगह से आते हैं जो इनसिक्योरिटी से भरी होती है या उनकी जिंदगी में कुछ अधूरा होता है, इसलिए वह आपके बारे में ऐसी बातें कर अपनी भड़ास निकाल रहे होते हैं।

संक्षिप्त समाचार

पोको एम3 भारत में लॉन्च

नई दिल्ली। ऑनलाईन स्मार्टफोन ब्रांड पोको ने अपने लेटेस्ट स्मार्टफोन पोको एम3 के लॉन्च की घोषणा की। यह ब्रांड सेगमेंट का सर्वश्रेष्ठ परफॉर्मर प्रस्तुत करके एम सीरीज की विरासत को आगे बढ़ा रहा है। पोको एम3 में 6जीबी रैम, 48 एमपी का ट्रिपल कैमरा सेटअप, 6000 एमएएच की बैटरी, फुल एचडी डिस्प्ले, क्वालकोम स्नैपड्रैगन 662 चिपसेट है। इसका मूल्य 10999 रुपए से शुरू होता है। आईसीआईसीआई बैंक के ग्राहकों को 1000 रुपए की अतिरिक्त छूट मिलेगी। अनुज शर्मा, कंट्री डायरेक्टर, पोको इंडिया ने कहा, अपने पहले साल पोको ने अनेक मानदंड स्थापित किए। स्वतंत्र ब्रांड बनने के 10 महीनों में ही हम भारत में तीसरी सबसे बड़ी ऑनलाईन स्मार्टफोन कंपनी बन गए हैं। यह हमारे ब्रांड के सिद्धांत एवरीथिंग यू नीड, नथिंग यू डोंट को ग्राहकों के मिले अपार समर्थन का प्रमाण है।

बीएमडब्ल्यू मोटोराड सफारी 2021 एडिशन शुरू

नई दिल्ली। बीएमडब्ल्यू मोटोराड इंडिया ने भारत में अपने अनूठे राइडिंग एक्सपीरियंस बीएमडब्ल्यू मोटोराड सफारी 2021 की शुरुआत की है। असली विशिष्टता के सार को सामने लाते हुए इस मोटोराड सफारी को केवल भारत में बीएमडब्ल्यू मोटरसाइकल ओनर्स के लिए तैयार किया गया है और यह दो पहियों पर जबरदस्त राइडिंग एडवेंचर की पेशकश करेगी। विक्रम पावाह, प्रेसिडेंट, बीएमडब्ल्यू ग्रुप इंडिया ने कहा, देश भर में 50 प्लस विशेष रूप से तैयार राइडिंग एक्सपीरियंस का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रतिभागियों को खोज और रोमांच का पूरा-पूरा अहसास मिलेगा और हर राइड देश भर के अलग-अलग गंतव्यों को एक्सप्लोर करेगी। इस सीरीज की शुरूआत जयपुर से बीकानेर के लिए बीएमडब्ल्यू मोटोराड डेजर्ट सफारी के साथ हुई जिसमें भारतीय थार रेगिस्तान को एक्स्प्लोर किया जाएगा। प्रतिभागियों को बेहतरीन राइडिंग स्किल के साथ सफारी का अधिक से अधिक आनंद उठाने का मौका मिलेगा।

डाबर इंडिया की अमेजन से भागीदारी

नई दिल्ली। आयुर्वेदिक कंपनियों में से एक डाबर इंडिया लिमिटेड ने डाबर ऑर्गेनिक हनी लॉन्च करने के लिये अमेजन इंडिया के साथ भागीदारी की है। यह डाबर के घर से निकला पहला ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। केमिकल्स का इस्तेमाल किये बिना, जैविक तरीके से वनस्पतियों से प्राप्त और जंगली मधुमक्खियों द्वारा बनाया गया, पोषक तत्वों और एंटीऑक्सीडेंट से प्रचुर डाबर ऑर्गेनिक हनी पूरी तरह से अनप्रोसेस्ड और अनपाश्चुराइज्ड होने का वादा करता है। डाबर इंडिया में हेल्थ सप्लीमेंट्स के मार्केटिंग हेड प्रशांत अग्रवाल ने कहा, ऑर्गेनिक केवल उत्पादों का एक प्रकार नहीं है। यह धीरे-धीरे मुख्यधारा की जीवनशैली बन रहा है। हमें विश्वास है कि इस जीवनशैली को पसंद करने वाले लोग हमारे डाबर ऑर्गेनिक हनी को निश्चित रूप से अपने डेली रूटिन में जोड़ेंगे।

भूमि ने बताया सर्दियों से बचने का देशी नुस्खा

नई दिल्ली। बॉलीवुड की जानी-मानी अभिनेत्री भूमि पेडनेकर ने बताया कि कैसे ठंडे मौसम में विक्स वैपोरब के साथ स्टीम लेने, एक ग्लास गुनगुना हल्दी और दूध पीने जैसे आम घरेलू उपायों से उन्हें खांसी-जुकाम जैसी परेशानियों से बचने में मदद मिलती है। इंस्टाग्राम पर उन्होंने कहा, मेरे नुस्खे बहुत आसान हैं और इन्हें मैंने अपनी मां को देखकर सीखा है। जब मैं छोटी थी और मुझे खांसी और जुकाम होता था, तो मां मुझे भाप दिलवाती थी। वह भी सबके घरों में इस्तेमाल होने वाले सबके फेवरेट विक्स वैपोरब से। आज भी मैं इसे करती हूं, क्योंकि वीवीआर में नीलगिरी, पुदीना, कपूर और अजवाइन जैसी पारंपरिक चीजें है और यह बंद नाक व खांसी से तुरंत ही आराम दिलाती हैं।

कोटक का टोल भुगतान पर कैशबैक ऑफर

नई दिल्ली। राष्ट्रीय व राज्य राजमार्गों, एक्सप्रेसवे और शहर के भीतर सफर को स्मार्ट, सस्ता और सुविधाजनक बनाने के लिए कोटक महिन्द्रा बैंक ने सभी पैसेंजर कारों के लिए कोटक एनईटीसी फास्टैग पर बड़े ऑफर की घोषणा की है। ऑफर के तहत पूरे भारत में टोल भुगतान पर 500 रुपए तक का कैशबैक ऑफर दिया जा रहा है। इसके साथ ही कोटक ने एनईटीसी फास्टैग पर जारी करने की फीस भी माफ कर दी है। यह ऑफर सभी लोगों के लिए है चाहे वे कोटक के ग्राहक हों या नहीं। यह ऑफर 31 मार्च, 2021 तक चुनिंदा चैनलों से कोटक एनईटीसी फास्टैग खरीदने पर लागू होगा। पुनीत कपूर, प्रेसिडेंट-प्रोडक्ट्स, ऑल्टरनेट चैनल्स व कस्टमर ऐक्सपीरियेंस डिलिवरी, कोटक महिन्द्रा बैंक ने कहा, फास्टैग ने कैशलैस भुगतान के जरिए सफर को तनाव मुक्त और आसान बना दिया है।

नीतिगत दरें यथावत, नहीं बढ़ेगी ईएमआई

अगले वित्त वर्ष में विकास दर 10.5 प्रतिशत रहने का अनुमान

मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने महंगाई को लक्षित दायरे में आने का हवाला देते हुए कोरोना वायरस से प्रभावित अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के उद्देश्य से नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं करने का निर्णय लिया है। समिति की तीन दिवसीय बैठक के बाद रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्ति कांत दास ने शुक्रवार को बैठक में लिए गए निर्णय की जानकारी देते हुए कहा कि नीतिगत दरों को यथावत रखने का फैसला किया गया है।

उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के बाद पहली बार दिसंबर 2020 में खुदरा महंगाई आरबीआई के लक्षित दायरे छह प्रतिशत के नीचे आ गई है। उन्होंने कहा कि कोरोना द्वारा प्रभावित अर्थव्यवस्था को तीव्र विकास के पथ पर लाने के उद्देश्य से नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि रेपो दर चार प्रतिशत, रिवर्स रेपो दर 3.35 प्रतिशत पर यथावत है। इसके साथ ही एमएसएफ 4.25 प्रतिशत और बैंक दर 4.25 प्रतिशत पर स्थिर है। ये दरें अब तक के रिकॉर्ड निचले स्तर पर हैं।

उन्होंने कहा कि समिति ने कोरोना के कारण सीआरआर में की गई कमी को 27 मार्च 2021 से चरणबद्ध तरीके से वृद्धि कर चार प्रतिशत करने का निर्णय लिया है। अभी यह दर तीन प्रतिशत पर है। पिछले वर्ष 26 मार्च को सीआरआर को कम कर तीन प्रतिशत किया गया था। अब 27 मार्च 2021 को इसमें आधी फीसदी की बढ़ोतरी की जाएगी। इसके बाद मई 2021 में फिर से आधी फीसदी की बढ़ोतरी होगी और यह फिर से चार प्रतिशत पर पहुंच जाएगा।

शिकायत निवारण प्रणाली का किया जायेगा एकीकरण

रिजर्व बैंक ने बैंकिंग प्रणाली में एक देशए एक बैंक लोकप्रहरी की संकल्पना लागू करने की शुक्रवार को घोषणा की। उसने कहा कि बैंकिंग प्रणाली में ग्राहकों की शिकायत निवारण प्रणाली का एकीकरण किये जाने की जरूरत है। अभी देश की बैंकिंग प्रणाली में तीन अलग-अलग बैंक लोकप्रहरी होते हैं। ये बैंक लोकप्रहरी बैंकिंग, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों तथा डिजिटल लेन-देन के लिये होते हैं। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने मौद्रिक नीति समिति की बैठक के निष्कर्षों की जानकारी देते हुए कहा, विवादों को सुलटाने की वैकल्पिक व्यवस्था को सरल बनाने तथा विनियमित निकायों के ग्राहकों के प्रति इसे अधिक जवाबदेह बनाने के लिये तीनों बैंक लोकप्रहरी व्यवस्थाओं का विलय कर एक देशए एक बैंक लोकप्रहरी की अवधारणा को अमल में लाने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि इस कदम का लक्ष्य एक केंद्रीयकृत संदर्भ प्रदान कर एकीकृत योजना के तहत बैंकों, एनबीएफसी तथा प्रीपेड भुगतान समाधान मुहैया कराने वाली गैर बैंकिंग कंपनियों के ग्राहकों को उनकी शिकायतों के निवारण के लिये एकल मंच प्रदान करना है। दास ने कहा कि रिजर्व बैंक ई-इंटीग्रेटेड बैंक लोकप्रहरी योजना को जून 2021 से शुरू करना चाह रहा है। दास ने कहा कि वित्तीय उपभोक्ता संरक्षण का महत्व नीतिगत क्षेत्र में बढ़ा है। रिजर्व बैंक इसी पर काम कर रहा है।

मौद्रिक नीति की मुख्य बातें

- रेपो दर 4.00 प्रतिशत पर यथावत
- रिवर्स रेपो दर 3.35 प्रतिशत पर यथावत
- मार्जिनल स्टैंडिंग फैसेलिटी (एमएसएफ) 4.25 प्रतिशत पर यथावत
- बैंक दर 4.25 प्रतिशत पर यथावत
- अगले वित्त वर्ष में जीडीपी वृद्धि दर 10.5 प्रतिशत रहने का अनुमान
- चालू वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में खुदरा महंगाई 5.2 प्रतिशत रहने की संभावना
- अगले वित्त वर्ष की पहली छमाही में खुदरा महंगाई 5.2 प्रतिशत से 5.0 प्रतिशत के बीच रहने का अनुमान
- मौद्रिक नीति समिति की अगले वित्त वर्ष में पहली द्विमासिक बैठक पांच से सात अप्रैल के बीच

सभी शेष 18000 बैंक शाखाएं सितंबर तक सीटीएस के अधीन होंगी

भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को कहा कि भुगतान और निपटान प्रणाली को अधिक बेहतर, तेज और सटीक बनाने के लिए सभी शेष 18000 शाखाएंए जो केंद्रीकृत समाशोधन प्रणाली चेक ट्रंकेशन सिस्टम सीटीएस के तहत नहीं हैं, उन्हें सितंबर तक सीटीएस के दायरे में लाया जाएगा। सीटीएस के तहत भुगतान और जमाओं के लिए कागज रहित अभौतिक सत्यापन किया जाता है। सीटीएस का इस्तेमाल 2010 से किया जा रहा है और इसके दायरे में लगभग 150000 बैंक शाखाएं हैं। आरबीआई ने एक बयान में कहा कि चूंकि 18000 बैंक शाखाएं अभी भी औपचारिक समाशोधन व्यवस्था के बाहर हैं, इसलिए परिचालन दक्षता को बढ़ाने और ग्राहकों को बेहतर सेवाएं देने के लिए सितंबर तक उन्हें सीटीएस के दायरे में लाना प्रस्तावित है। केंद्रीय बैंक ने यह भी कहा कि वह धोखाधड़ी और चालबाजी के खिलाफ डिजिटल भुगतान सेवाओं के लिए एक लगातार चालू रहने वाली एक हेल्पलाइन स्थापित करेगा। आरबीआई ने साथ ही कहा कि वह जल्द ही परिचालकों और अधिकृत भुगतान प्रणालियों के प्रतिभागियों के लिए आउटसोर्सिंग दिशानिर्देश जारी करेगा। केंद्रीय बैंक ने यह भी कहा कि बेहतर उपभोक्ता सुरक्षा उपायों के तहत वह तीन लोकपाल योजनाओं, बैंकिंग लोकपाल योजनाए एनबीएफसी के लिए लोकपाल योजना और डिजिटल लेनदेन के लिए लोकपाल योजनाए को एकीकृत करेगा।

महंगाई पहली छमाही में पांच प्रतिशत के पास रहने की उम्मीद

अनुकूल परिस्थितियों तथा कुछ खाद्य पदार्थों विशेषकर सब्जियों की कीमतों का दबाव कम होने से खुदरा मुद्रास्फीति के इस साल नवंबर-दिसंबर तक नरम होकर 4.3 प्रतिशत पर आ जाने का अनुमान है। रिजर्व बैंक ने मौद्रिक नीति बयान में शुक्रवार को इसकी जानकारी दी। रिजर्व बैंक ने कहा कि खुदरा मुद्रास्फीति के चालू वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही जनवरी से मार्च 2021 में 5.2 प्रतिशत पर आ जाने का अनुमान है। इसी तरह नये वित्त वर्ष की पहली छमाही अप्रैल से अगस्त 2021 में खुदरा मुद्रास्फीति का अनुमान पहले के 5.2 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत कर दिया गया है। केंद्रीय बैंक का कहना है कि खुदरा मुद्रास्फीति वित्त वर्ष 2021-22 की तीसरी तिमाही अक्टूबर से दिसंबर 2021 में और नरम होकर 4.3 प्रतिशत पर आ सकती है। कोरोना वायरस महामारी की चपेट में आने के बाद खुदरा मुद्रास्फीति पहली बार दिसंबर तिमाही में छह प्रतिशत के दायरे में आ गई। रिजर्व बैंक ने मौद्रिक नीति वक्तव्य में शुक्रवार को इसकी जानकारी दी।

पारदर्शिता रेटिंग एजेंसियों को उत्साहित करेगी

मुंबई। देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई के अर्थशास्त्रियों ने राजकोषीय नियमों को पुनर्परिभाषित किये जाने के लिये बजट की सराहना की है। उनका कहना है कि आंकड़ों में पारदर्शिता बाजार के साथ रेटिंग एजेंसियों को उत्साहित करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को अपने बजट भाषण में कहा कि 2020-21 में राजकोषीय घाटा 9.5 प्रतिशत और अगले वित्त वर्ष 2021-22 में कम होकर 6.8 प्रतिशत रहेगा। राजकोषीय घाटे के आंकड़े से सरकार के साथ पर प्रभाव को लेकर संदेह बढ़ा है। एक विदेशी ब्रोकरेज कंपनी ने कहा कि वैश्विक एजेंसियां बजट के परिणाम को देखते हुए भारत की साख को कम कर कबाड़ की श्रेणी में ला सकती हैं। हालांकि कुछ तबकों में पारदर्शिता को लेकर सीतारमण की सराहना की गई है। अर्थशास्त्रियों ने कहा, आंकड़ों में अधिक पारदर्शिता लंबे समय तक बाजार और यहां तक कि रेटिंग एजेंसियों को उत्साहित करेगी। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई के अर्थाास्त्रियों ने एक रिपोर्ट में कहा कि बजट ने राजकोषीय नियमों को पुनर्परिभाषित किया है। बही खातों से अलग रखे जाने वाले मदों को घाटे में शामिल किया गया है।

एसबीआई अर्थशास्त्री का कहना

भारतीय स्टेट बैंक ने टॉप 10 में बनाई जगह

मुंबई। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक, एसबीआई ने मार्केट कैप के लिहाज से टॉप 10 में जगह बना ली है। इसका मार्केट कैप सुबह 3.64 लाख करोड़ रुपए हो गया। जबकि अभी तक टॉप 10 में रहने वाला एयरटेल अब 11वें नंबर पर पहुंच गया है। उसका मार्केट कैप 3.17 लाख करोड़ रुपए है। बजाज फाइनेंस का मार्केट कैप 3.31 लाख करोड़ रुपए रहा है। एसबीआई के शेयरों में हाल के समय में अच्छी बढ़त रही है। गुरुवार को इसने अपना रिजल्ट जारी किया था। इसमें उसको पांच हजार करोड़ रुपए से ज्यादा फायदा हुआ था। हालांकि यह मुनाफा 2019 की दिसंबर तिमाही की तुलना में कम था। मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिहाज से रिलायंस इंडस्ट्रीज अभी टॉप पर है। इसका मार्केट कैप 12.25 लाख करोड़ रुपए है। टाटा कंसलटेंसी सर्विसेस टीसीएस का मार्केट कैप 11.77 लाख करोड़ रुपए है। एचडीएफसी बैंक का शेयर भी नया रिकॉर्ड रोज बना रहा है। शुक्रवार को इसका शेयर बढ़कर 1618 रुपए पर चला गया। इससे इसका मार्केट कैप 8.91 लाख करोड़ रुपए हो गया। मई में एसबीआई बैंक का शेयर 149 रुपए पर था। उस समय इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 1.33 लाख करोड़ रुपए था। तब से अब तक इसका शेयर 250 रुपए बढ़ चुका है। मार्केट कैप 2.30 लाख करोड़ रुपए बढ़ चुका है। विश्लेषक अभी भी इस शेयर में अच्छा रिटर्न देख रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि बुरे फंसे कर्ज यानी एनपीए पर इसने अच्छा काम किया है। ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस ने इस शेयर में 58 फीसदी की तेजी की बात कही है।

मार्केट कैप पहुंचा 3.64 लाख करोड़ रुपए पर

लिसा स्टालेकर ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल

सिडनी। ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान लिसा स्टालेकर को ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट हाल ऑफ फेम में शामिल किया गया है।

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने की घोषणा

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने शुक्रवार को यह घोषणा की। पुणे में जन्मी स्टालेकर ने ऑस्ट्रेलिया की तरफ से 12 साल के अपने करियर के दौरान आठ टेस्ट, 125 वनडे और 54 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले। वनडे और टी20 प्रारूप में ऑस्ट्रेलिया की चार विश्वकप विजेता टीम की सदस्य रही स्टालेकर ने 2006 में न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन वनडे में टीम की अगुवाई की थी। उन्हें 2007 में साल की अंतरराष्ट्रीय महिला क्रिकेटर चुना गया था। उन्हें 2007 और 2008 में आस्ट्रेलिया की सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना गया था जिसके लिये उन्हें बेलिंडा क्लार्क पदक मिला था। उन्हें अगस्त 2020 में आईसीसी क्रिकेट हाल ऑफ फेम में शामिल किया गया था।

पर्थ स्कॉर्चर्स और सिडनी सिक्सर्स के बीच होगी खिताबी भिड़ंत

कैनबरा। पर्थ स्कॉर्चर्स ने ब्रिसबेन हीट को हराकर बिग बैश लीग (बीबीएल) के फाइनल में जगह बना ली।

बीबीएल : पर्थ स्कॉर्चर्स ने डकवर्थ-लुईस नियम के तहत ब्रिसबेन हीट टीम को 49 रनों से मात दी

कैनबरा के मनुका ओवल में बिग बैश लीग के चैलेंजर मैच में पर्थ स्कॉर्चर्स ने डकवर्थ-लुईस नियम के तहत ब्रिसबेन हीट टीम को 49 रनों से मात दी। अब 6 फरवरी को पर्थ टीम का मुकाबला खिताब के लिए सिडनी सिक्सर्स से होगा। ब्रिसबेन हीट ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। पर्थ स्कॉर्चर्स के ओपनर कैमरन बेनक्रॉफ्ट और लियाम लिविंगस्टोन ने 114 रनों की ओपनिंग साझेदारी की। लिविंगस्टोन (76) ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए 39 गेंदों पर 5 चौके और 6 छक्के जड़े। फिर बेनक्रॉफ्ट ने मिशेल मार्श के साथ मिलकर 75 रनों की पार्टनरशिप की। बेनक्रॉफ्ट ने 42 गेंदों में 6 चौकों की मदद से नाबाद 58 और मार्श ने 28 गेंदों में 5 चौके और 2 छक्कों की मदद से नाबाद 49 रन बनाए। पर्थ टीम का स्कोर 18.1 ओवर में 189-1 था, कि बारिश के कारण मैच को रोक दिया गया। बारिश के कारण पारी दोबारा शुरू नहीं हो पाई और ब्रिसबेन टीम को 18 ओवर में 200 रनों का लक्ष्य मिला। क्रिस लिन (22) और जो डेनली (14) ने पहले विकेट के लिए 37 रनों की साझेदारी की। इसी स्कोर पर जेसन बेहरनडॉर्फ ने लगातार गेंदों पर विकेट चटकाते हुए ब्रिसबेन को बड़े झटके दिए। देखते ही देखते टीम के 6 विकेट मात्र 88 के स्कोर तक गिर गए। ब्रिसबेन हीट 18 ओवर में 9 विकेट पर 150 रन ही बना पाई और उसे 49 रनों से शिकस्त झेलनी पड़ी।

रूट के 100वें टेस्ट में शतक से इंग्लैंड मजबूत

भारत के खिलाफ पहले टेस्ट के पहले दिन इंग्लैंड ने तीन विकेट खोकर बनाए 263 रन

चेन्नई। कप्तान जो रूट (नाबाद 128) के 100वें टेस्ट में शतक के अद्भुत कारनामे और उनकी डॉमिनिक सिब्ले (87) के साथ तीसरे विकेट के लिए 200 रन की जबरदस्त साझेदारी की बदौलत इंग्लैंड ने भारत के खिलाफ यहां एमए चिंदबरम स्टेडियम में पहले टेस्ट के पहले दिन शुक्रवार को तीन विकेट पर 263 रन का मजबूत स्कोर बना लिया।

पहले टेस्ट का पहला दिन पूरी तरह इंग्लैंड के कप्तान जो रुट की रिकॉर्ड बल्लेबाजी के नाम रहा। भारत के खिलाफ पांचवां शतक और ओवरऑल अपने करियर का 20वां शतक बनाया। रूट 197 गेंदों में 14 चौकों और एक छक्के की मदद से 128 रन बनाकर क्रीज पर हैं। अपने कप्तान का बखूबी साथ देने वाले सिब्ले दिन के आखिरी ओवर की तीसरी गेंद पर आउट हुए। सिब्ले ने 286 गेंदों पर 12 चौकों की मदद से 87 रन की शानदार पारी खेली। दोनों ने तीसरे विकेट के लिए 390 गेंदों में 200 रन की जबरदस्त साझेदारी कर इंग्लैंड को बेहद मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। रुट ने अपने टेस्ट करियर का आगाज भारतीय जमीन पर किया था। उन्होंने अपना 50वां टेस्ट भी भारत में और 100वां टेस्ट भी भारत में खेला। भारत के खिलाफ उनका यह पांचवां शतक है। भारत ने सुबह के सत्र में दबदबा बनाया लेकिन दिन के दूसरे और तीसरे सत्र में रूट और सिब्ले की जोड़ी छायी रही। उन्होंने भारतीय गेंदबाजों को कोई मौका नहीं दिया। भारतीय कप्तान विराट कोहली रणनीति और गेंदबाजी संतुलन के लिहाज से कमजोर दिखायी दिए। भारत ने तीसरे सत्र में 80 ओवर पूरे होने के बाद दूसरी नई गेंद भी ली लेकिन इसका दोनों बल्लेबाजों पर कोई असर नहीं पड़ा। दिन के आखिरी ओवर में जसप्रीत बुमराह ने सिब्ले को पगबाधा कर भारत को कुछ राहत दिलाई। बुमराह का भारतीय जमीन पर यह दूसरा विकेट था। बुमराह ने इससे पहले सुबह के सत्र में डेनियल लॉरेंस को भी पगबाधा किया था। लॉरेंस का खाता नहीं खुला था। ओपनर रोरी बर्न्स 33 रन बनाकर ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन की गेंद पर आउट हुए थे।

कैप्टन मूर की याद में काली पट्टी बांध मैदान पर उतरे इंग्लैंड के खिलाड़ी

इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाड़ी भारत के खिलाफ पहले क्रिकेट टेस्ट के पहले दिन दूसरे विश्व युद्ध में हिस्सा ले चुके इंग्लैंड के दिवंगत कैप्टन टॉम मूर की याद में हाथ पर काली पट्टी बांधकर मैदान पर उतरे। 100 वर्षीय सर टॉम मूर का हाल ही में कोरोना वायरस के कारण अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया था। वह पूर्व सैनिक होने के साथ ही विभिन्न कामों के लिए धन जुटाते थे। उन्होंने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भी धन जुटाया था। इंग्लैंड के कप्तान जो रुट ने वीडियो संदेश के जरिए सर मूर को श्रद्धांजलि दी।

रूट दुनिया के एक मात्र खिलाड़ी जिन्होंने अपने 98वें, 99वें और 100वें टेस्ट में शतक बनाया

रूट दुनिया के एकमात्र ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने अपने 98वें, 99वें और 100वें टेस्ट में शतक बनाया है। रूट ने भारत में आने से पहले श्रीलंका के खिलाफ दो टेस्टों की सीरीज में 228 और 186 रन बनाए थे। उसमें अब उन्होंने एक और शतक जोड़ लिया है। रूट ने अपने टेस्ट करियर का आगाज भारतीय जमीन पर किया था। उन्होंने अपना 50वां टेस्ट भी भारत में और 100वां टेस्ट भी भारत में खेला। भारत के खिलाफ उनका यह पांचवां शतक है।

100वें टेस्ट में शतक बनाने वाले इंग्लैंड के तीसरे और दुनिया के नौवें बल्लेबाज बने रूट

विश्व रैंकिंग में पांचवें नंबर के बल्लेबाज रूट अपने 100वें टेस्ट में शतक बनाने वाले इंग्लैंड के तीसरे और दुनिया के नौवें बल्लेबाज बन गए हैं। इंग्लैंड के कॉलिन काउड्रे ने 1968 में अपने 100वें टेस्ट में 104 रन, पाकिस्तान के जावेद मियांदाद ने 1989 में 145 रन, वेस्टइंडीज के गार्डन ग्रीनिज ने 1990 में 149 रन, इंग्लैंड के एलेक स्टीवर्ट ने 2000 में 105 रन, पाकिस्तान के इंजमाम उल हक ने 2005 में 184 रन, ऑस्ट्रेलिया के रिकी पोंटिंग ने 2006 में 120 और नाबाद 143 रन, दक्षिण अफ्रीका के ग्रीम स्मिथ ने 2012 में 131 रन और दक्षिण अफ्रीका के हाशिम अमला ने 2017 में 134 रन बनाए थे। रूट का नाम अब इन विशिष्ट बल्लेबाजों की श्रेणी में जुड़ गया है जिन्होंने 100वें टेस्ट में शतक बनाने का कारनामा किया है।

रूट 100वां टेस्ट खेलने वाले इंग्लैंड के 15वें खिलाड़ी

इंग्लैंड के कप्तान जोसफ एडवर्ड रूट भारत के खिलाफ एम चिदंबरम स्टेडियम में शुक्रवार को मैदान पर उतरने के साथ ही 100 टेस्ट खेलने वाले इंग्लैंड के 15वें खिलाड़ी बन गए। 30 वर्षीय रुट को उनके 100वें टेस्ट की उपलब्धि के लिए उनके टीम साथी बेन स्टोक्स ने विशेष कैप भेंट की। इंग्लैंड के राष्ट्रीय चयनकर्ता एड स्मिथ ने भी अपने कप्तान को विशेष कैप भेंट की। इस अवसर पर विकेटकीपर जोस बटलर को उनके 50वें टेस्ट की उपलब्धि के लिए उनके कप्तान रुट ने विशेष कैप भेंट की। मौजूदा समय में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में शुमार रूट 100वें टेस्ट में उतरने के साथ ही यह उपलब्धि हासिल करने वाले इंग्लैंड के 15वें खिलाड़ी बन गए। इंग्लैंड की तरफ से 100 से ज्यादा टेस्ट मैच खेलने वाले खिलाड़ियों में एलेस्टेयर कुक (161), जेम्स एंडरसन (158), स्टुअर्ट ब्रॉड (144), एलेक स्टीवर्ट (133), इयान बेल (118), ग्राहम गूच (118), डेविड गॉवर (117), माइक आर्थटन (115), कॉलिन काउड्रे (114), ज्योफ्री बॉयकाट (108), केविन पीटरसन (104), इयान बॉथम (102), एंड्रयू स्ट्रॉस (100) और ग्राहम थोर्प (100) शामिल हैं।

बुमराह ने श्रीनाथ का रिकॉर्ड तोड़ा

भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह इंग्लैंड के साथ शुरू हुई टेस्ट सीरीज में अपने करियर का 18वां मैच खेल रहे। यह अपने घर में बुमराह का पहला टेस्ट है। बुमराह ने इससे पहले घर में कभी टेस्ट नहीं खेला। वह विदेशों में सबसे अधिक टेस्ट खेलने के बाद घर में टेस्ट खेलने का रिकार्ड अब अपने नाम कर चुके हैं। पहले यह रिकॉर्ड एक अन्यतेज गेंदबाज जवागल श्रीनाथ के नाम था, जिन्होंने अपने पदार्पण के बाद से 12 टेस्ट विदेश में खेल और फिर जाकर उन्हें घर में खेलने का मौका मिला। इस क्रम में रुद्र प्रताप सिंह (11), सचिन तेंदुलकर (10) और आशीष नेहरा (10) के भी नाम हैं। बुमराह की बात की जाए तो उन्होंने पांच जनवरी 2018 को न्यूलैंड्स में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ डेब्यू किया था। बीते महीने वह भारत के आस्ट्रेलिया दौरे का हिस्सा थे। वह सिडनी टेस्ट में खेले थे लेकिन चोट के कारण ब्रिस्बेन टेस्ट में नहीं खेल सके थे।

चोटिल पटेल बाहर, कुलदीप को नहीं मिला मौका

भारतीय कप्तान विराट कोहली ने इंग्लैंड के खिलाफ शुक्रवार से शुरु हुए पहले टेस्ट की पूर्व संध्या पर कहा था कि चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव को पहले मैच में मौका मिल सकता है लेकिन मैच शुरु होने से पूर्व चोटिल लेफ्ट ऑर्म स्पिन ऑलराउंडर अक्षर पटेल बाहर हो गए और उनकी जगह एक अन्य लेफ्ट ऑर्म स्पिनर शाहबाज नदीम को अंतिम एकादश में जगह मिली है। बीसीसीआई ने मैच शुरु होने से पहले बताया कि अक्षर पटेल ने बाएं घुटने में दर्द की शिकायत की है और उन्हें इस मैच से बाहर रखा गया है। पटेल को गुरुवार को वैकल्पिक ट्रेनिंग सत्र में यह परेशानी हुई थी। बीसीसीआई की मेडिकल टीम उनकी निगरानी कर रही है।

टेस्ट मैचों का सैकड़ा लगाने वाले तीसरे सबसे युवा खिलाड़ी बने रूट

रूट 100 टेस्ट खेलने वाले तीसरे सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। चेन्न ई टेस्ट के पहले दिन रूट की उम्र 30 साल 37 दिन है। टेस्ट इतिहास में सबसे कम उम्र में 100वां टेस्ट खेलने का रिकार्ड इंग्लैंड के ही पूर्व कप्तान एलिस्टर कुक के नाम है, जिन्होंने साल 2013 में 28 साल 353 दिनों की उम्र में 100वां टेस्ट खेला था। कुक ने इंग्लैंड के लिए सबसे अधिक 161 टेस्ट खेले। इसके बाद भारत के सचिन तेंदुलकर का नाम है। सचिन ने साल 2002 में 29 साल 134 दिन की उम्र में अपना 100वां टेस्ट खेला था। सचिन ने साल 2013 में अपने करियर का 200वां टेस्ट भी खेला था।